ISSN 2454-504X | 01-15 मार्च, 2025 | राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका | RNI No. DELHIN/2002/08663

₹ 15

दूसरा मत

दूसरा मत कामयाबी के 22 साल

www.doosramat.com | YOUTUBE DOOSRA MAT | जहां सच बोलते हैं शब्द

प्रो.(डॉ.) ध्रुब कुमार को रामकृष्ण परमहंस शिखर सम्मान

डॉ. पी के वर्मा को डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिखर सम्मान

डॉ. महेश प्रसाद सिंह को रविन्द्र नाथ टैगोर शिखर सम्मान

प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार को विवेकानंद शिखर सम्मान

रूपरेखा बदलेंगी रेखा!

बेटी : एक ग़ज़ल

यक़ीनन यह एक नायाब ग़ज़ल-संग्रह है। एक ही क़ाफ़िया और एक ही रदीफ़ पर, एक ही विषय और एक ही ख़्याल के अनेकों आयाम पर लिखी गई यह संसार की किसी भी भाषा और विधा की सबसे अनूठी साहित्यिक-कृति है। 'बेटी' को विषय बनाकर और संपूर्णता में एक नारी के विराट वैभव और शक्तियों का मूल्यवान उल्लेख कर, हिन्दी-ऊर्दू के इस माहिर शायर ने हिन्दी-ग़ज़ल-गोई में एक कमाल पैदा कर दिया है।

पिछली सदी के एक महान कवि काशीनाथ पाण्डेय ने 'बयाने-क्रौंच ताईर' नाम की, तीस हज़ार छः सौ नब्बे पंक्तियों वाली एक कविता लिखी थी, जिसे संसार की सबसे लम्बी कविता मानी जाती है। उन्होंने अपनी इस एक कविता से साहित्य-संसार को चमत्कृत कर दिया था। उसी तरह पत्रकार और शायर ए आर आज़ाद ने एक सौ छह पृष्ठों में पांच सौ तीस अशआर, अर्थात एक हज़ार साठ पंक्तियों की एक ग़ज़ल लिखी है। इस लिहाज़ से यह कोई 'ग़ज़लों का संग्रह नहीं', बल्कि एक विशाल ग़ज़ल की किताब है।

कवि की काव्य-कल्पनाएं भी चेतना में रोमांच भरती हैं। ये बेटी को 'एक मुकम्मल ग़ज़ल' मानते हैं। यह एक ख़ूबसूरत और उम्दा अहसास है। एक बेटी में उन्होंने दोनों जहान की ख़ूबसूरती और ताक़त देख ली है। इस एक ग़ज़ल में नारी-विमर्श के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। 'बेटी : एक ग़ज़ल' के हवाले से, सुबुद्ध कवि ने सदियों से उपेक्षित 'औरत' को एक ऐसा मक़ाम दिया है, जहां उसका ओहदा और रुतबा अपने चरम उत्कर्ष पर दिखाई देता है।

इस ग़ज़ल के हर एक शेर से गुज़रना एक रोमांचक अनुभूति की तरह है, जो हृदय को सुंदर, मनोरम और स्थायी भाव से भर देती है। दुनिया की इस अनूठी ग़ज़ल को बेशक हर उस पाठक को पढ़ना चाहिए, जो अदब की दुनिया से ज़रा भी सरोकार रखते हैं। इसे पढ़ने के पहले मैं भी नहीं जानता था कि यह शायर इतना भी लाजवाब है। मेरी अशेष मंगल कामनाएं कवि के प्रति तो है ही, आपके लिए भी है कि आपके हाथ में यह नायाब चीज़ मिली है! मैंने इस किताब (ग़ज़ल) की कोई पंक्ति उद्धृत नहीं की है। ताकि इसे आप ख़ुद पढ़ें!

डा. अनिल सुलभ

अध्यक्ष,बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन

बेटी : एक ग़ज़ल

बेटी पर 1060 अशआरों वाली अब तक की नायाब एवं अभूतपूर्व ग़ज़ल

ए आर आज़ाद

मैं 94 वर्ष का हूं। और उर्दू कविता से प्रेम करता हूं। यह प्रेम बहुत कुछ अंजान आदमी का प्रेम है, जिसे अंग्रेज़ी में Blind Love कहते हैं। इसलिए उर्दू कविता के बारे में जो कुछ कहूं, उसकी पहले तस्दीक़ कर ली जाए। मेरा विचार ये रहा है कि उर्दू कविता में स्त्री अधिकांशतः प्रेमिका के रूप में चित्रित हुई है। अपवाद के रूप में मुझे केवल मीर अनीस दिखते हैं। पारिवारिक संबंधों पर वैसी एक रचना शायद किसी भाषा में न हो। इसके साथ मीर तक़ी मीर का वह शेर याद आता है, जिसका मिसरा है-

अब आया ध्यान ए आराम-ए-जाँ इस ना-मुरादी में
कफ़न देना तुम्हें भुले थे हम असबाब-ए- शादी में

फ़िराक़ गोरखपुरी ने इस क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का काम किया है। उनकी एक रूबाई उर्दू साहित्य को अभूतपूर्व समृद्धि से भर देती है -

है ब्याहता पर रूप अभी कुंवारा है
मां है पर अदा जो भी है दोशीज़ा है
वो मोद भरी मांग भरी गोद भरी
कन्या है, सुहागन है जगत माता है

बेटी पर ऐसा रूप मैंने कहीं नहीं देखा है।

आज़ाद साहब ने बड़ी कृपा करके अपनी मूल्यवान और प्रिय पुस्तक- बेटी : एक ग़ज़ल पढ़ने को भेजी। इस उम्र में आंखों की कमज़ोरी के कारण मैं पूरी किताब अच्छी तरह नहीं पढ़ पाया। लेकिन जितना पढ़ा, उससे पर्याप्त प्रभावित हुआ। मैं यह बिना संकोच के कह सकता हूं कि बेटी पर ग़ज़ल की पूरी किताब लिख देना बहुत मेहनत और लगन का काम है। अच्छा हो कि आज़ाद साहब अगले एडिशन में इस किताब की एक भूमिका लिखाएं। और अच्छी तरह बताएं कि बेटी पर ऐसी अभूतपूर्व किताब लिखने की- नज़्म में नहीं, प्रेरणा कहां से मिली? ज़िंदगी में वो कौन सा अनुभव, और वो कौन सी घटना थी, जिसने यह धनुष उठाने का उत्साह और साहस उनको दी।

एक ही विषय पर संकल्प करके लंबी किताब लिखने में सबसे बड़ा ख़तरा होता है कि कुछ सामग्री भर्ती के लिए देनी पड़ती है। केवल यह होता है कि देखिए हम एक ही विषय पर लिख रहे हैं अदबदा कर। और इससे विषय की सीमा के कारण शिल्प में बेज़रूरत का ठहराव आ जाता है। कुछ अल्फ़ाज़ ढीले इस्तेमाल होते हैं।

आज़ाद साहब की इस लंबी किताब में मुझे कोई शेर भर्ती का नहीं मिला। और ये पता चला कि उनके पास हिन्दी शब्दों का अपूर्व भंडार है। इसमें देसी, तत्सम और तद्भव तीनों प्रकार के शब्दों का उपयोग समान रूप से किया गया है।

मैं आज़ाद साहब का व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ हूं कि उन्होंने ऐसी नायाब किताब मुझे पढ़ने को दी है। यह किताब हिन्दी ग़ज़ल के साहित्य में एक नयापन लाती है। और ग़ज़ल के रीतिकालीन यानी रुग्न या कोठे से उतारकर सामान्य भारतीय परिवार के आत्मीय परिवेश में ला देती है। मुझे आशा है कि आज़ाद साहब हिन्दी ग़ज़ल को नित नूतन रचनाओं से समृद्ध करेंगे।

डा. विश्वनाथ त्रिपाठी

बी-5, एफ-2, दिलशाद गार्डेन, दिल्ली-110045

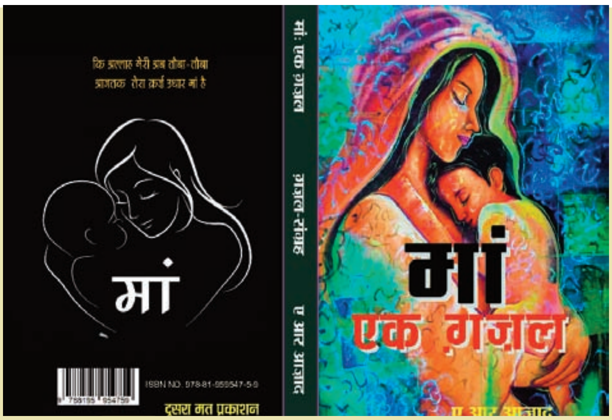

फार्म- IV

(नियम 8 देखिए)

दूसरा मत

1. **प्रकाशन स्थान** : दिल्ली

2. **प्रकाशन अवधि** : पाक्षिक

3. **मुद्रक का नाम** : ए आर आज़ाद

राष्ट्रीयता

(क) क्या आप भारत के नागरिक हैं? : हां

(ख) यदि विदेशी हैं, तो मूल देश : लागू नहीं

कार्यालय पता : 81बी- सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

4. **प्रकाशक का नाम** : ए आर आज़ाद

राष्ट्रीयता

(क) क्या आप भारत के नागरिक हैं? : हां

(ख) यदि विदेशी हैं, तो मूल देश : लागू नहीं

कार्यालय पता : 81बी- सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

5. **संपादक का नाम** : ए आर आज़ाद

राष्ट्रीयता

(क) क्या आप भारत के नागरिक हैं? : हां

(ख) यदि विदेशी हैं, तो मूल देश: लागू नहीं

कार्यालय पता : 81बी- सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059

6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं तथा समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हैं : ए आर आज़ाद

मैं ए आर आज़ाद एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक 01/03/2025

ह./
(ए आर आज़द)
प्रकाशक

दूसरा मत
जहां सच बोलते हैं शब्द

RNI No. DELHIN/2002/08663

वर्ष: 24, अंक: 05

01-15 मार्च, 2025

संपादक
ए आर आज़ाद

संपादकीय सलाहकार
मन्तेश्वर झा (IAS R.)
(पूर्व प्रमुख सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार)

प्रमुख परामर्शी एवं प्रमुख क़ानूनी सलाहकार
न्यायमूर्ति राजेन्द्र प्रसाद
(अवकाश प्राप्त न्यायधीश, पटना उच्च न्यायालय)

प्रमुख सलाहकार
जियालाल आर्य (IAS R.)
(पूर्व गृह सचिव एवं पूर्व चुनाव आयुक्त बिहार)

ब्यूरो प्रमुख
रुफी शमा

राजनीतिक संपादक
देवेंद्र कुमार प्रभात

बेगूसराय ब्यूरोचीफ सह ब्यूरो बिहार
एस आर आज़मी

ब्यूरो ऑफिस बिहार
बजरंगबली कॉलोनी, नहर रोड,
जज साहब के मकान के सामने, फुलवारी शरीफ,
पटना, बिहार-801505

संपादकीय एवं पंजीकृत कार्यालय
81-बी, सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन,
उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
Email: doosramat@gmail.com
MOBILE. 9810757843
Whatsapp. 9643709089

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
ए आर आज़ाद द्वारा 81-बी, सैनिक विहार, फेज़-2, मोहन गार्डेन, उत्तम नगर, नयी दिल्ली-110059 से प्रकाशित एवं शालीमार ऑफसेट प्रेस, 2622, कूचा चेलान, दरियागंज, नयी दिल्ली-110002 से मुद्रित।
संपादक-ए आर आज़ाद

पत्रिका में छपे सभी लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, इनसे संपादक या प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। पत्रिका में छपे लेखों के प्रति संपादक की जवाबदेही नहीं होगी।
सभी विवादों का समाधान दिल्ली की हद में आने वाली सक्षम अदालतों में ही होगा।
**उपरोक्त कुछ पद अवैतनिक हैं।*

आवरण 34
रूपरेखा बदलेंगी रेखा!

महिला दिवस 06
महिला चाहें तेज़ी

प्रसंगवश 14
... मुस्लिम महिलाओं का योगदान

प्रेरक 12
एक सशक्त महिला मनीषा

महिला दिवस 20
सोशल मीडिया और ....

जायज़ा 46
अपार संपदा, पिछड़ता कृषि क्षेत्र

जज़्बा 27
बेहाथ तीरंदाज

दृष्टिपथ : ...महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत 10
महिला दिवस : एक बेहद ज़रूरी मामलों.. 18
महिला दिवस : विज्ञान में महिलाओं... 22
महिला दिवस : बदलना होगा नज़रिया 24
बेबाक : संकीर्णता से बौना बनते नेता 28
पड़ताल : अफ़सरशाही पर मोदी और ट्रंप 30
कहानी : 'क़सबे का आदमी' 66

दिल्ली तो देश का दिल है

ए आर आज़ाद

दिल्ली देश का दिल भी है, और देश की राजधानी भी। दिल्ली एक ऐसी दास्तान है, जहां अब भी दो सुल्तान होते हैं। दोनों की अपनी-अपनी ठसक और हनक के साथ-साथ सनक भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली के बड़े सुल्तान नरेंद्र मोदी, और दिल्ली के छोटे सुल्तान अरविन्द केजरीवाल रहे हैं। दोनों ने एक-दूसरे से जमकर गुत्थम-गुत्थी की। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल इसी लड़ाई को हथियार बनाकर देश के बड़े सुल्तान के पैरों तले से ज़मीन खिसकाते रहें। उन्हें यह एहसास कराते रहें कि यह 'आम आदमी' की दिल्ली है। यानी मेरी दिल्ली है। दिल्ली के बादशाह से दो-दो हाथ कर उन्हें यह संदेश देते रहे कि दिल्ली मेरी बंदरिया है, मैं जैसे, चाहूं वैसे नचाऊं।

मोदी और शाह दिल्ली में रहकर केंद्र की सत्ता पर क़ाबिज़ होकर और कई राज्यों में सत्तासीन होकर भी दिल्ली की सत्ता को पाने की कसक मन में दबाए रहे। दिल का दर्द, दिल में ही रहा। लेकिन केजरीवाल का दिल्ली को लेकर नज़रिया विश्वसनीय नहीं होने के कारण दिल्ली के लोगबाग ने उन्हें कुछ दिनों के लिए अवकाश पर भेजने का आख़िरकार मन बना ही लिया।

केजरीवाल दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी के लोगों के मन को पढ़ने और अपने हिसाब से गढ़ने में कामयाब रहे। और अगली कड़ी में उन्होंने दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले असंख्य लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ़्त की योजनाओं से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यह आकर्षण का केंद्र कई वर्षों तक चला। लेकिन जब बीजेपी ने इन्हीं के रास्तों को चुना, तो जनता के बीच एक सफल पैग़ाम गया कि दिल्ली का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब केंद्र और दिल्ली यानी दोनों में एक ही दल और गठबंधन की सत्ता और सरकार हो।

दिल्ली की जनता ने 2024 तक किसी भी राजनीतिक उठापटक का इंतज़ार किया। लेकिन 2024 के परिणाम ने दिल्ली की जनता को आश्वस्त कर दिया कि अब दिल्ली का भला केंद्र के हिसाब से चलने और ढलने में ही है। इस मिज़ाज और इस हवा की कशिश में बड़ी आसानी से अनधिकृत कॉलोनियों के बाशिन्दे गिरफ़्तार हो गए। नतीजे बदलने की उम्मीद जब पूरज़ोर हुई तो फिर 'आप' का वरदान ही 'आप' के लिए 'श्राप' बन गया।

केंद्र के हाथ दिल्ली की सरकार लगी है। दिल्ली की सत्ता सुख के लिए बीजेपी को एक लंबे अरसे से तपस्या, उपासना, हवन और जंग करनी पड़ी है। अब दिल्ली को बीजेपी से बेहतर कौन समझ सकता है? बीजेपी पर और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर दिल्ली को दिल बनाए रखने की ज़िम्मेदारी है। यह दायित्व नैतिक भी है। और इम्तहान वाला भी। इस परीक्षा में बीजेपी को और केंद्र की सत्तासीन पार्टियों को अब कुछ करके दिखाना होगा। अब कोई जुमला नहीं चलेगा। अब कोई बहानेबाज़ी नहीं चलेगी। बहाना और चालाकी की अपनी एक उम्र होती है। उस उम्र को बेमौत मा-रकर ही बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता पर क़ाबिज़ हुई है।

दिल्ली क्या चाहती है, इसे जानने के लिए दिल्ली के बाशिंदों के मन को पढ़ना होगा। दिल्ली को पेरिस बनाने का सपना अरविन्द केजरीवाल ने जनता को दिखाया था, उसे पूरा करना होगा। और अगर बीजेपी दिल्ली को पेरिस नहीं बना सकती है, तो फिर शीला दीक्षित वाली सरकार में, जो दिल्ली की ख़ूबसूरती थी, कम से कम उतना बहाल कर देना केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की बीजेपी सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी है। वैसे भी आज की बेतरतीब रोड और उसकी हालत को देखकर ही तो बीजेपी के एक लीडर ने दिल्ली की सड़कों को किसी ख़ास लोगों के गाल से उपमा देकर, उस तरह का बनाने का जुमला फेंका था। अब इस जुमले में केंद्र सरकार और बीजेपी ख़ुद फंस चुकी है। दिल्ली की सड़कों और सुविधाओं को उसे हर हाल में विश्वस्तरीय बनाना होगा। क्योंकि दिल्ली में काम बोलता है, जुमला नहीं। इस बात का ख़्याल और अंदाज़ा बीजेपी और केंद्र सरकार को होनी ही चाहिए। जय हिन्द! जय भारत!! ●

महिलाएं चाहें तेज प्रगति

रचना बादल

8 मार्च को स्त्री विमर्श को सार्थक करते हुए महिला दिवस मनाने की परंपरा 1975 में शुरू हुई। इस साल ही महिला वर्ष घोषित किया गया। 1975 में ही संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने था के उद्देश्य के साथ महिला वर्ष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल की। तब से ही हर वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष थीम चुनी जाती है जो उस समय की प्राथमिकताओं को दशार्ती है। हर वर्ष एक नई थीम होती है जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और विकास के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होती है।

पिछले 5 वर्षों की थीम

यह थीम इस विचार पर आधारित थी कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इसमें समावेशी समाज की आवश्यकता को रेखांकित किया गया था। कुल मिलाकर दो शब्दों में बात की जाए तो यह उम्मीद की गई थी कि हर व्यक्ति लैंगिक समानता के लिए अपना योगदान देगा।

2021 : चुनौती चुनें

दूसरा मत

महिला दिवस
की हार्दिक
शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं
दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

इस थीम ने महिलाओं को असमानता के खिलाफ आवाज उठाने और परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका संदेश था कि केवल चुनौती देने से ही बदलाव संभव होगा।

संक्षेप में कहा जाए तो संदेश था कि चुनौतियां एवं समस्याओं से भाग नहीं जाए अभी तो चुनौतियों का डटकर सामना किया जाए या फिर महिलाओं की प्रगति के लिए खुद चुनौतियां खड़ी करके उनका हल निकाला जाए।

2022 : आज लैंगिक समानता, कल के लिए स्थिरता

इस वर्ष की थीम ने जलवायु परिवर्तन और लैंगिक समानता के आपसी संबंध पर जोर दिया। इसका उद्देश्य था महिलाओं की भागीदारी के बिना एक सतत भविष्य संभव नहीं है।

2023 : डिजिटलः नवाचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लैंगिक समानता

यह थीम डिजिटल युग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य था कि तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में महिलाओं को समान अवसर मिले। यह समय की मांग भी थी और आज भी है कि जब तक महिलाएं तकनीकी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेगी उनका वास्तविक विकास होना संभव नहीं है इसीलिए डिजिटल इन्नोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लैंगिक समानता पर जोर दिया गया था।

2024 : महिलाओं में निवेश करें, प्रगति को तेज करें

पिछले वर्ष की थीम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर केंद्रित रही। इसका मुख्य संदेश है कि महिलाओं में निवेश करने से समाज और अर्थव्यवस्था में तेजी से प्रगति होगी। यानी यानी उन का मानना था कि यदि महिलाओं से संबंधित क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाएगा तभी प्रगति को पंख लगा सकेंगे और साथ ही साथ महिलाओं का विकास भी हो सकेगा।

2025 : तेजी से कार्रवाई

इस थीम का उद्देश्य लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को तेज करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार, वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 2158 तक का समय लग सकता है, जो लगभग पाँच पीढ़ियों के बराबर है। इसलिए, इस थीम के माध्यम से, समाज को संयुक्त रूप से प्रयास करने और ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि महिलाओं के अधिकारों और समानता को शीघ्रता से सुनिश्चित किया जा सके।

थीम का प्रभाव

संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष के लिए एक नई थीम इसलिए चुनी ताकि उसका अधिकाधिक प्रभाव महिला विकास एवं उन्नयन तथा उनके अपडेशन पर पढ़ सके एवं महिलाओं का जीवन पहले के मुकाबले बेहतर हो सके साथ ही साथ में समझ में सर ऊंचा करके सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे सके और निश्चित रूप से इस प्रकार से थीम बेस्ड महिला वर्षों ने अपना असर दिखाई भी है।

सामाजिक परिवर्तनः

हर वर्ष एक थीम के साथ महिला दिवस मनाने से सामाजिक परिवर्तन गतिशील हुए हैं तथा विभिन्न देशों की सरकारों ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए विभिन्न नीतियां बनाई

हैं। इसका प्रभाव सामाजिक परिदृश्य पर भी दिखाई दिया है।

कानूनी सुधारः

दुनिया भर के तीसरी दुनिया के देश जिम एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप मुख्य रूप से शामिल है आज भी महिलाओं को वह समानता का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वह हकदार है लेकिन प्रतिवर्ष एक थीम को लेकर महिला वर्ष या महिला दिवस मनाने से इस क्षेत्र में सुधार हुआ है जिसके परिणाम स्वरूपकई देशों ने लैंगिक समानता को कानूनी रूप से सशक्त

करने के लिए नए कानून बनाए हैं।

आर्थिक सशक्तिकरण:

हर वर्ष महिला दिवस मानने से जहां महिलाओं में जागरूकता आई है वहीं उनके लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं महिला रोजगार में वृद्धि हुई है आज में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में खुलकर कार्य कर रहे हैं तथा समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में अभिनव योगदान दे रही है साथ ही साथ सरकारों एवं स्वायत्त साहसी संस्थाओं ने भी महिला उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई हैं।

तकनीकी भागीदारी:

भले ही कुछ देशों में महिला वर्षीय महिला दिवस एक औपचारिकता मात्र बनकर रह गए हैं लेकिन फिर भी दुनिया भर में इसका व्यापक प्रभाव भी पड़ा है जिससे महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में अधिक अवसर प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। और इसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया भर के देशों में महिलाएं तकनीकी क्षेत्र में बाढ़-चाड करने केवल हिस्सा ले रहे हैं अभी तू नए-नए नवाचारों में अपना सक्रिय योगदान भी दे रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष व थीम का उद्देश्य केवल महिलाओं की स्थिति सुधारना नहीं है, बल्कि एक संतुलित और समावेशी समाज बनाना है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। हमें सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा, ताकि एक न्यायसंगत और प्रगतिशील दुनिया बनाई जा सके।

(व्यक्त विचार लेखिका के अपने हैं)

अध्यापिकाओं की बढ़ती संख्या महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत

प्रियंका सौरभ
स्तंभकार

यूडीआईएसई+ 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्कूल शिक्षकों में अब 53.34 प्रतिशत महिलाएं हैं, जो शिक्षा में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। उच्च शिक्षा में केवल 43% संकाय महिलाएं हैं, नेतृत्व की भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व और भी कम है। शैक्षणिक जगत में लैंगिक समानता अभी भी जड़ जमाये पूर्वाग्रहों, व्यावसायिक बाधाओं और संस्थागत कठिनाइयों के कारण बाधित है। भारत के शिक्षण कार्यबल में महिलाओं के प्रतिशत में वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता, समावेशिता और सामाजिक समानता में आमूलचूल परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। शिक्षणशास्त्र में लैंगिक पूर्वाग्रहों को चुनौती दी जाती है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है, और महिला विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाती है। छात्रों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, महिला शिक्षक कक्षा में अधिकाधिक भागीदारी और लिंग-संवेदनशील शिक्षण को प्रोत्साहित करती हैं। यूनेस्को की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं द्वारा संचालित कक्षाओं में समावेशी भागीदारी 20% अधिक होती है। सामाजिक बाधाओं और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करके, महिला शिक्षकों की उपस्थिति लड़कियों के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाती है। महिला शिक्षकों की संख्या में वृद्धि के कारण बिहार की कन्या उत्थान योजना में महिलाओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लिंग भूमिकाओं, बाल विवाह और मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में बातचीत को सामान्य बनाकर, महिला शिक्षक समानता को बढ़ावा देती हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत किशोरियों को महिला शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिला शिक्षकों द्वारा भावनात्मक समर्थन देने की संभावना अधिक होती है, जिससे विद्यार्थियों का कल्याण बेहतर होता है।

उच्च शिक्षा संकाय पदों में महत्वपूर्ण लैंगिक असमानताएं महिला संकाय सदस्यों के कम प्रतिनिधित्व के कारण होती हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार, शिक्षण पदों पर पुरुषों की संख्या अधिक होने के बावजूद, उच्च शिक्षा संकाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 43% है। आईआईटी और एनआईटी में महिला संकाय का प्रतिनिधित्व अभी भी 20% से कम है, जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में लैंगिक असमानताओं को दर्शाता है। अकादमिक नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर स्तर तक सीमित है, जहां उनका प्रतिशत तेजी से गिरता है। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में 25% से भी कम पूर्ण प्रोफेसर महिलाएं हैं, जो निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है। भारत के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों में 10% से भी कम कुलपति महिलाएं हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं के कारण, केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में महिलाओं की भागीदारी अधिक है, जबकि ग्रामीण और उत्तर भारतीय विश्वविद्यालयों में यह कम है। केरल के सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में आधे से अधिक प्राध्यापक महिलाएं हैं, जबकि बिहार और राजस्थान में यह प्रतिशत 30% से भी कम है। नियुक्ति और पदोन्नति में अचेतन पूर्वाग्रहों के कारण महिलाओं के नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाने की संभावना कम होती है। अकादमिक महिलाओं को

प्रायः मार्गदर्शन और मजबूत व्यावसायिक नेटवर्क का अभाव होता है, जो शोध के अवसरों और कैरियर में उन्नति के लिए आवश्यक है। कई महिलाएं घर के कामकाज की दोहरी जिम्मेदारी के कारण अपने करियर में ब्रेक ले लेती हैं, जिसका असर उनकी उन्नति और शोध कार्य की संभावनाओं पर पड़ता है।

समान कैरियर उन्नति के अवसर सुनिश्चित करना, लिंग कोटा स्थापित करना, चयन समितियों की निष्पक्षता सुनिश्चित करना तथा स्पष्ट पदोन्नति मानकों को लागू करना, शैक्षणिक नियुक्ति समितियों में 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व की अनिवार्यता के द्वारा, जर्मनी का डीएफजी कार्यक्रम अधिक महिलाओं को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षाविदों में महिलाओं की मेंटरशिप और नेटवर्किंग अवसरों तक पहुंच बढ़ानाः महिला संकाय सदस्यों को वरिष्ठ शिक्षाविदों के साथ जोड़ने के लिए औपचारिक मेंटरशिप कार्यक्रम स्थापित करना, वित्तपोषण के अवसरों, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर सलाह देना। केंद्रित मार्गदर्शन और समर्थन नेटवर्क के मूल्य के प्रमाण के रूप में, अमेरिका का ₹विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं₹ कार्यक्रम नेतृत्व भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में सहायक रहा है। कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना, परिसर में बाल देखभाल सेवाएं प्रदान करना, सवेतन मातृत्व अवकाश बढ़ाना, तथा लचीले कार्यकाल पथ को लागू करना, महिला संकाय सदस्यों को मातृत्व के बाद एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार प्रदान करके उनके शोध करियर को जारी रखने में मदद करता है। महिलाओं की प्रशासनिक और शैक्षणिक दृश्यता में सुधार लाने के लिए विशिष्ट वित्तपोषण उपलब्ध कराना तथा उनके लिए नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम चलाना, भारत की ₹महिला वैज्ञानिक योजना₹ महिला शोधकताओं को करियर ब्रेक के बाद वित्त पोषण प्रदान करके शिक्षा जगत में वापस लौटने में मदद करती है। उच्च शिक्षा संकाय में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 43% है, जो कक्षा के बाहर उनके प्रभाव को सीमित करता है। आईआईटी और आईआईएम में महिला शिक्षकों का प्रतिशत 20% से भी कम है।

यूजीसी का जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (जीएटीआई) कार्यक्रम महिला संकाय सदस्यों को नेतृत्वकारी पदों पर आसीन होने के लिए प्रोत्साहित करता है। समान वेतन के दिशा-निर्देश स्थापित करें, श्रम कानूनों को अधिक सख्ती से लागू करें तथा अनुबंध शिक्षकों को नियमित करें। निजी शिक्षा में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 का सशक्त प्रवर्तन आवश्यक है। परिसर में सुरक्षा प्रोटोकॉल, परिवहन विकल्प और शिकायत प्रक्रिया को बेहतर बनाएं। शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा उपायों की स्थापना को निर्भया फंड (2013) द्वारा वित्त पोषित किया गया है। लिंग-संतुलित शिक्षण स्टाफ प्रारंभिक शिक्षा में स्त्रीकरण को कम करेगा और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों को सामान्य बनाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में, फिनलैंड और स्वीडन पुरुषों की भर्ती को आक्रामक रूप से प्रोत्साहित करते हैं। गुमनाम शिकायत निवारण प्रक्रियाएं स्थापित करें, सुनिश्चित करें कि आंतरिक शिकायत समितियां (आईसीसी) कार्यरत हों, तथा सभी विश्वविद्यालयों में कठोर उत्पीड़न-विरोधी नीतियां लागू करें। यूजीसी के 2023 निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों में आईसीसी आवश्यक है; हालाँकि, अभी भी कार्यान्वयन में खामियाँ हैं, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण संस्थानों में। शिक्षा जगत में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन कार्यक्रम, समावेशी नियुक्ति प्रथाएं, संस्थागत परिवर्तन और बहुआयामी रणनीति आवश्यक हैं। परिवार-अनुकूल कार्यस्थलों को बढ़ावा देना, पारदर्शी पदोन्नति की गारंटी देना, तथा भेदभाव-विरोधी कानूनों को मजबूत बनाना, उच्च शिक्षा में महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हो सकता है। लिंग-संवेदनशील, योग्यता-आधारित नीतियों की ओर प्रतिमान बदलाव से प्रतिनिधित्व में सुधार होगा और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ●

एक सशक्त महिला मनीषा उपाध्याय की प्रेरणादायक यात्रा

मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म निर्माण और साहित्य के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाली मनीषा उपाध्याय आज भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके व्यक्तित्व की बहुआयामी उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि अगर संकल्प और समर्पण हो, तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम उनकी असाधारण यात्रा पर प्रकाश डालते हैं।

मनीषा उपाध्याय ने अपने करियर की शुरूआत मीडिया जगत में की। और शीघ्र ही अपनी प्रभावशाली रिपोर्टिंग और प्रस्तुति कौशल के कारण शीर्ष पत्रकारों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 18 वर्षों तक इंडिया टीवी, ईटीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे प्रतिष्ठित समाचार चैनलों में वरिष्ठ संपादकीय पदों पर कार्य किया। उनकी खोजी पत्रकारिता ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। इनमें आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार का पदार्फाश करने वाली 'मिशन लोकपाल' रिपोर्ट शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने स्वयंभू संत आसाराम बापू के आपराधिक कृत्यों को उजागर करने वाले 'ऑपरेशन हे राम' नामक विशेष रिपोर्ट की प्रस्तुति की।

उनकी पत्रकारिता में निडरता और निष्पक्षता का परिचय उनकी उस रिपोर्ट से मिलता है, जिसे शाहजहांपुर दुष्कर्म मामले में जोधपुर उच्च न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। उनके निर्देशित डॉक्यूमेंट्री 'टू फेसेस ऑफ कश्मीर' को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय सांसदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के सामने प्रदर्शित किया गया।

मनीषा उपाध्याय की क्षमताएं केवल पत्रकारिता तक सीमित नहीं हैं। उन्होंने टेलीविजन और सिनेमा में भी अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। वे एशिया के पहले महिला केंद्रित चैनल 'फोकस टीवी' और पहले मैट्रिमोनियल चैनल 'शगुन टीवी' की प्रोग्रामिंग प्रमुख भी रही हैं। उन्होंने 20 से अधिक टेलीविजन शो का निर्देशन और निर्माण किया, जिनमें 'दिल पे मत ले यार', 'बोलो ग्राहक बोलो' और 'क्योंकि रात अभी बाकी है' जैसे शो प्रमुख हैं।

मनीषा उपाध्याय केवल मीडिया और साहित्य तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई। वे 2017-2019 के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने वाली पहली महिला थीं। वे उपभोक्ता मामलों के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भी हैं।

उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिनमें 'अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान', 'राजीव गांधी रत्न पुरस्कार', 'स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन अवार्ड' और 'वी.वी. गिरी जर्नलिज्म ऑफ करेज अवार्ड' शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रमुख वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

एक लेखिका के रूप में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। उन्होंने 2000 से अधिक टेलीविजन एपिसोड और डॉक्यूमेंट्रीज की स्क्रिप्ट लिखी हैं। उनकी लिखी हुई एक गजल 'इश्क-क्लिक' फिल्म में शामिल की गई थी, जिसे प्रसिद्ध गायक अंकित तिवारी ने गाया था। उनकी आत्मकथा 'अनकवर - क्रॉनिकल्स ऑफ ट्रायल्स एंड ट्राइंफ्स' अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित हुई और 150 से अधिक देशों में उपलब्ध है। उनकी आगामी पुस्तक 'द आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स' भारत में राजनीतिक नेतृत्व के प्रशिक्षण पर केंद्रित पहली पुस्तक होगी।

मनीषा उपाध्याय की यात्रा न केवल सफलता की कहानी है, बल्कि यह उन सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखती हैं। उनकी उपलब्धियां यह सिद्ध करती हैं कि अगर संकल्प, निडरता और समर्पण हो, तो कोई भी बाधा सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इस विशेष अवसर पर हम मनीषा उपाध्याय जैसी सशक्त महिलाओं को सलाम करते हैं, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने और महिलाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ●

भारत के स्वाधीनता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं का योगदान

रुफी शमा

मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। देश की आजादी की लड़ाई में उनका अविस्मरणीय एवं अतुलनीय योगदान है। उनमें से ऐसी 13 आजादी की मुस्लिम नायिकाओं से हम रुबरू करा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे नाम हैं, जिन्हें सालों साल से भुलाया जाता रहा है। आज हम उन पर खुलकर चर्चा करने जा रहे हैं। इन्हीं में से महत्वपूर्ण नाम हैं-आबदी बानो बेगम, बीबी अम्तुस सलाम, बेगम हजरत महल, मुहम्मदी खानम, बेगम निशातुन्निसा मोहनी, बाजी जमालुन्निसा, कुलसुम सयानी, सैयद फकरूल हाजिया हसन, रशीद उन निसा, बेगम अनीस किदवई, हाजरा बीवी इस्माइल, फातिमा शेख एवं बेगम एजाज रसूल उन लोगों में से हैं, जिन्हें अक्सर भुला दिया गया।

आबदी बानो बेगम

आबदी बानो बेगम स्वतंत्रता आंदोलन की पहली मुस्लिम महिला योद्धा थीं। इन्होंने सक्रिय रूप से खुलकर सियासत में हिस्सा लिया। और भारत को ब्रिटिश राज के बंधन से मुक्त करने के लिए आंदोलन का जवाबदेह हिस्सा बनकर उभरीं। गांधी जी उन्हें बी अम्मा कहकर पुकारा करते थे।

आबदी बानो बेगम का जन्म 1852 में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हुआ था। मालूम हो कि बी अम्मान की शादी रामपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी अब्दुल अली खान से हुई थी। अपने पति की मौत के बाद, बानो ने अपनी संतान दो बेटियों और पांच बेटों को अपने दम पर पाला। उनके बेटे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख हस्ती के तौर पर उभरे। उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ असहयोग आंदोलन के दौरान एक अहम किरदरा निभाया।

1917-1921 तक बी अम्मा की माली हालात खराब थी। बावजूद इसके जब सरोजिनी नायडू की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने,

ब्रिटिश रक्षा अधिनियम के विरोध में हर महीने 10 रुपए का दान दिया।1917 में, बानो भी एनी बेसेंट और उनके बेटों को रिहा कराने के आंदोलन में शामिल हो गईं। नतीजे में 1917 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह आंदोलन बाल गंगाधर तिलक के साथ शुरू किया गया था।

बी अम्मा भारत की स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम महिलाओं के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक थीं। महिलाओं का समर्थन पाने के लिए, महात्मा गांधी ने उन्हें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के एक सत्र में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके भाषण का जबरदस्त असर हुआ। उनके भाषण ने ब्रिटिश भारत के मुसलमानों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इतना ही नहीं उन्होंने खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन जमा करने में अहम भूमिका निभाई।

बीबी अम्तुस सलाम

पटियाला बीबी अम्तुस सलाम महात्मा गांधी की 'दत्तक बेटी', एक सामाजिक कार्यकर्ता और उनकी शिष्य थीं। उन्होंने विभाजन के बाद सांप्रदायिक हिंसा का मुकाबला करने और विभाजन के बाद भारत आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कलकत्ता, दिल्ली और दक्कन में सांप्रदायिक दंगों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में जाकर और अपनी जान जोखिम में डाल कर सांप्रदायिक सौहार्द कायम करने की कोशिश की। बीबी सलाम गांधी आश्रम की एक मुस्लिम कैदी थीं। और वक्त के साथ गांधी की दत्तक पुत्री बन गईं।

नोआखली दंगों के बाद, 9 फरवरी, 1947 को द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक लेख में उल्लेख किया गया था कि अम्तुस सलाम का 25 दिन का उपवास, गांधी और उनके शिष्यों के कामों के सबसे अहम परिणामों में से एक था। दरअसल इसका मकसद अपराधियों को दोषी महसूस कराना था। अपहृत महिलाओं और बच्चों को बचाने की कोशिश में राज्य के अधिकारियों की 'लापरवाही' के विरोध में, वह बहावलपुर के डेरा नवाब में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गईं।

बेगम हजरत महल

1857 के विद्रोह की एक प्रतिष्ठित शख्सियत, बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम ने अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का तोहफा या भत्ता लेने से साफ इंकार कर दिया। और उन्होंने अपने सेनापति राजा जैलाल सिंह की मदद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बहादुरी से लड़ाई लड़ी।

मुहम्मदी खानम

मुहम्दी खानम भविष्य महल, का जन्म 1830 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। गुलाम हुसैन उनके पिता थे। उन्हें साहित्य की समझ थी। हाईवे के लिए जगह बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मस्जिदों और मंदिरों को तोड़ने का काम किया तो उन्होंने जमकर अंग्रेजों से लोहा लिया। जब 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर आक्रमण किया और उनके पति, अवध के अंतिम नवाब को कलकत्ता निर्वासित कर दिया तो बेगम ने अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ लखनऊ में रहने का फैसला किया। 31 मई, 1857 को, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंग्रेजों को शहर से बाहर निकालने के लिए लखनऊ में लड़ाई लड़ी।

7 जुलाई, 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस खादिर को अवध का नवाब घोषित किया। उसने 1,80,000 सैनिकों को खड़ा किया और नवाब की मां के रूप में लखनऊ किले का भव्य रूप से जीर्णोद्धार किया। 7 अप्रैल, 1879 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया।

बेगम निशातुन्निसा मोहनी

बेगम निशातुन्निसा मोहनी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनकी स्वतंत्रता की धारणा को गांधीजी ने अपनाया था। उनका विवाह एक महान स्वतंत्रता योद्धा मौलाना हसरत मोहानी से हुआ। मोहानी ने ही 'इंकलाब जिंदाबाद' का नारा दिया। बेगम मोहनी ब्रिटिश सत्ता की घोर विरोधी मानी जाती थीं। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कट्टरवादी बाल गंगाधर तिलक का समर्थन करके आजादी के आंदोलन को मजबूत किया। जब उनके पति जेल में थे,तब उन्होंने अपने दैनिक, उर्दू-ए-मुल्ला के प्रकाशन को संभाला। और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रहीं।

बाजी जमालुन्निसा

तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली बाजी जमालुन्निसा का 22 जुलाई, 2016 को 101 वर्ष की आयु में इसी शहर में निधन हो गया। जमालुन्निसा बाजी का जन्म 1915 में हैदराबाद में हुआ था। वह स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत एक प्रमुख वकील थीं। उनका लालन-पालन एक उदार एवं प्रगतिशील वातावरण में में हुआ। छोटी ही उम्र में उन्होंने प्रतिबंधित पत्रिका 'निगार' और प्रगतिशील साहित्य पढ़ना शुरू किया।

ब्रिटिश राज के एक घटक, निजाम शासन की पारंपरिक धार्मिक परंपराओं में पले-बढ़े होने के बावजूद, उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। निजाम के दमनकारी शासन और अपने ससुराल वालों की आपत्तियों के बावजूद उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन

में भाग लेना नहीं छोड़ा। अपनी सक्रियता जारी रखी। बाद में, उन्होंने मौलाना हजरत मोहनी जिन्होंने 'इंकलाब-जिंदाबाद' का नारा गढ़ा था और स्वतंत्रता संग्राम में 'थंडर बोल्ट' के रूप में जाना जाता था, से मुलाकात की। इस मुलाकात ने उन्हें राष्ट्र में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कम्युनिस्ट होने के दौरान इंपीरियल सरकार के गिरफ्तार होने से बचने की कोशिश कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को अभयारण्य प्रदान किया।

बुनियादी उच्च शिक्षा की कमी के बावजूद, वे उर्दू और अंग्रेजी में पारंगत थीं। और उन्होंने साहित्यिक समाज बज्मे एहबाब की स्थापना की, जिसने समाजवाद, साम्यवाद और अनुचित रीति-रिवाजों पर समूहों में बहस की।

उन्हें फर्स्ट लांसर में हजरत सैयद अहमद बद-ए-पह दरगाह में दफनाया गया है। वह एक पूर्व विधायक और पायम डेली के संस्थापक सैयद अख्तर हसन की बहन थीं, और उन्हें 'बाजी' के नाम से जाना जाता था।

वह मकदूम मोहिउद्दीन की कम्युनिस्ट पार्टी की करीबी दोस्त और सदस्य थीं। बाजी प्रगतिशील लेखक संघ और महिला सहकारी समिति की संस्थापक सदस्य भी थीं।

कुलसुम सयानी

21 अक्टूबर 1900 को गुजरात में कुलसुम सयानी की पैदाइश हुई। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और सामाजिक अन्याय के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। 1917 में कुलसुम और उनके पिता महात्मा गांधी से मिले। पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की वकालत की। डॉ. जान मोहम्मद सयानी, एक प्रसिद्ध मुक्ति सेनानी, वह पुरुष थे, जिनसे उन्होंने शादी की थी। उन्होंने अपने पति के समर्थन से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

उन्होंने अनपढ़ लोगों के साथ काम करना शुरू किया। और चरखा आंदोलन में शामिल हो गईं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 'जन जागरण' अभियानों पर भी उनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के बारे में भी लोगों में जागरूकता पैदा की।

सैयद फकरूल हाजिया हसन

सैयद फकरूल हाजियान हसन न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि अपने बच्चों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थीं, जो इराक से भारत में आकर बस गया था। उन्होंने अपने बच्चों को स्वतंत्रता सेनानी बनने के लिए पाला। जिन्हें बाद में 'हैदराबाद हसन ब्रदर्स' के रूप में ख्याति मिली।

हाजिया ने आमिर हसन से शादी की, जो उत्तर प्रदेश से हैदराबाद स्थानांतरित हो गए थे। नतीजे में उन्होंने हैदराबादी संस्कृति को भी अपनाया। उनके पति आमिर हसन हैदराबाद सरकार में एक वरिष्ठ पद पर थे। उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान भारत में महिलाओं की पीड़ा को देखा। उन्होंने महिला बच्चों के विकास में बहुत सारे प्रयास किया।

वह हैदराबाद में रहती थी, जो अंग्रेज शासित था, फिर भी वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थीं, क्योंकि वह मजबूत राष्ट्रीय भावनाओं वाली महिला थी।

उन्होंने महात्मा गांधी की मांग के जवाब में हैदराबाद के टूप बाजार में अपनी आबिद मंजिल में विदेशी कपड़ों को जला दिया। उन्होंने असहयोग और खिलाफत आंदोलनों में हिस्सा लिया।

वह भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रत्येक सैनिक को अपने बच्चों में से एक मानती थी। किसी भी समाज में महिलाओं के लिए कुछ नया करना हमेशा से एक चुनौती रही है। समाज की रूढ़िवादी मानसिकता के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं को पर्दा-प्रथा जैसी बेड़ियों से निकल कर खुद को साबित करना बेहद मुश्किल रहा है। इन मुश्किलों के बावजूद इन महिलाओं ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, हर छेत्रों में अपना अमिट योगदान दिया है।

रशीद-उन-निसा

1855 में रशीद-उन-निसा का जन्म पटना के शम्सुल उलामा सैय्यद वहीदुद्दीन खान बहादुर के घर हुआ था। उन्हें पहली महिला उर्दू उपन्यासकार होने का गौरव हासिल है। उनके भाई, इमदाद इमाम असर, उर्दू साहित्य के सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक थे। वो राशिद अली इमाम और हसन इमाम की चाची थीं। उनकी शादी मौलवी मोहम्मद याह्या से हुई थी, जो साहित्य में रूचि रखते थे। वैसे तो रशीद-उन-निसा शिक्षित और संपन्न परिवार से थीं, पर महिला होने के नाते साहित्य और ज्ञान तक उनकी पहुंच बहुत ज्यादा नहीं थी।

पहली किताब का प्रकाशन

बात 1869 की है, जब मौलवी नजीर अहमद के उपन्यास मिरात-उल-उरूस का प्रकाशन हुआ था। तब वो 16 वर्ष की थीं। मिरात-उल-उरूस को पढ़ कर वो काफी प्रभावित हुईं और 1880 में उन्होंने अपना उपन्यास लिखना शुरू किया। उन्होंने इसे छह महीने के भीतर पूरा भी कर लिया। हालांकि यह उपन्यास 1881 में लिखा गया था, लेकिन इसे प्रकाशित करने के लिए पूरे 13 साल का इंतेजार करना पड़ा। 1894 में जब रशीद-उन-निशा के बेटे बैरिस्टर सुलेमान कानून की डिग्री हासिल कर के इंग्लैंड से वापस आए, तब आखिरकार ये उपन्यास छपी। लेकिन तब इसमें लेखिका के नाम की जगह बैरिस्टर सुलेमान की मां, सैयद वहीदुद्दीन खान बहादुर की बेटी और इमदाद इमाम की बहन लिखा गया। ये वो मुश्किल समय था जब लेखिका को अपनी ही किताब को अपने नाम से छपवाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज रशीद-उन-निशा किसी पहचान की मोहताज नहीं। वो हर दौर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा हैं। उनका मानना था कि

हिन्दू हो या मुस्लिम हर महिला को आधुनिक शिक्षा पाने का हक है।

बेगम अनीस कि दवई

बेगम अनीस कि दवई का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में हुआ था। उनके पिता का नाम शेख विलायत अली था। उनकी शादी शफी अहमद किदवई से हुई थी। उनके पिता और पति स्वतंत्रता सेनानी थे। बेगम अनीस कि दवई का भारत की आजादी में अहम योगदान दिया था। लेकिन वो बंटवारे से खुश नहीं थीं। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों ने उनके पति शफी अहमद किदवई की जान ले ली, जो शांति और सद्भाव के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इस घटना ने भी बेगम अनीस का हौंसला टूटने नहीं दिया। उन्होंने दंगों में पीड़ित महिलाओं, बच्चों और विस्थापित लोगों के लिए काम किया। उन लोगों के लिए राहत शिविर लगाए, मरीजों का इलाज किया। और उनके खाने-पीने से लेकर अंतिम संस्कार तक किया। 1957-68 तक वो राज्य सभा की सदस्य रहीं। हिन्दू-मुस्लिम एकता की मिसाल बेगम अनीस ने 16 जुलाई, 1982 को अंतिम सांस लेते हुए इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया।

हाजरा बीबी इस्माइल

आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के तेनाली की रहने वाली हाजरा बीबी इस्माइल की शादी मोहम्मद इस्माइल से हुई थी। ये दंपति गांधी जी के अनुयाई थें। और गांधी जी के खादी आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। हर मुश्किल हालात में हाजरा बीवी ने अपने पति मोहम्मद इस्माइल का साथ दिया। और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रहीं। लीग के विरोध और सामाजिक बहिष्कार ने भी उनका मनोबल नहीं तोड़ा।

उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा उन विद्यालयों से करवाई, जहां राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जाती थी। बार-बार जेल जाने की वजह से खद्दर इस्माइल की तबीयत बिगड़ चुकी थी। और 1948 में उनका निधन हो गया। पति के मौत के बाद भी हाजरा स्माइल ने अपने बच्चों के साथ मिलकर खादी स्टोर को चलाया। देश के लिए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की श्रेणी में जमीन देने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए विनम्रता से मना कर दिया कि वह अपनी देशभक्ति की कीमत नहीं लगाना चाहतीं। 16 जून, 1994 को उनका तेनाली में निधन हो गया। हाजरा बीबी इस्माइल एक समर्पित खादी कार्यकर्ता रहीं। और अंतिम समय तक खादी वस्त्र ही पहना।

फातिमा शेख

फातमिा शेख को पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है। फातिमा शेख ने दलित, आदिवासी और मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए मजबूती और दिलचस्पी से काम किया। उन्होंने शिक्षा के दिशा में महिलाओं और बच्चों को शिक्षित करने के लिए सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के साथ काम किया। वह ज्योतिराव फुले के नेतृत्व वाले सत्यशोधक आंदोलन का एक हिस्सा थीं। जब ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले को परिवार और गांव के सदस्यों ने उनके घर और गांव से निकाल दिया, लोगों ने 1848 में दलित बच्चों और महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू करने के उनके प्रयासों को 'धार्मिक विरोधी कार्य' करार दिया, तो उस्मान और फातिमा शेख ने उन्हें अपना योगदान देकर उनकी मदद की। उन्हें स्कूल में रहने और चलाने दोनों के लिए आवास दिया।

सावित्रीबाई के साथ फातिमा ने एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए कड़ी मेहनत की। फुले परिवार के साथ फातिमा शेख को भी सामाजिक अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था की कठोर संरचनाओं के खिलाफ लड़ रही थीं। फातिमा शेख ने घर-घर जा कर शिक्षा को फैलाया। और लड़कियों को स्कूल भेजने को प्रोत्साहित किया। अफसोस की बात है कि फातिमा शेख, जिस सम्मान की हकदार थीं, वो उन्हें नहीं मिला। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने उनके योगदानों के मद्देनजर पाठ्यपुस्तकों में एक संक्षिप्त परिचय शामिल किया है।

बेगम एजाज रसूल

अपनी आत्मकथा 'पर्दा टू पार्लिआमेन्टः अ मुस्लिम वीमन इन इन्डियन पॉलिटिक्स' की लेखिका बेगम एजाज का असल नाम बेगम साहेबा कुदुसिया था। वो भारत की एक मात्र मुस्लिम महिला हैं, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति में शामिल थीं। उनका जन्म 2 अप्रैल, 1909 को लाहौर में हुआ था। वो पेशे से राजनीतिज्ञ, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थीं। वह उन कुछ महिलाओं में से एक थीं, जो गैर-आरक्षित सीट से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ीं और यूपी विधानसभा के लिए चुनी गई। उन्होंने 1937 से 1940 तक परिषद के उपाध्यक्ष का पद संभाला। 1950 में वो कांग्रेस में शामिल हो गईं। जमीदार घराने से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने जमींदारी उन्मूलन का मजबूती से समर्थन किया था। राजनीति के साथ-साथ बेगम रसूल खेल में भी खूब रुचि रखती थीं। उन्होंने दो दशकों तक भारतीय महिला हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का पद संभाला। और एशियाई महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष भी रहीं। साहित्य में भी उनको बेहद दिलचस्पी थी। और उन्होंने 'थ्री वीक्स इन जापान' नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने विभिन्न समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में भी योगदान दिया। पहली अगस्त, 2001 को बेगम एजाज का निधन हो गया। बेगम एजाज के समाज में योगदान और उनके कार्यों के लिए भारत सरकार ने साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया। ●

एक बेहद जरूरी मामलों में महिलाओं का संघर्ष

अमरपाल सिंह वर्मा

हमारे देश में अक्सर महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। समानता के नारे गूंजते हैं लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि समानता तो दूर, महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय तक पहुंच पाना भी एक बड़ा संघर्ष है? हाल में यह जान कर हैरानी की सीमा नहीं रही कि कोरो इंडिया नामक संगठन को मुम्बई में महिलाओं के लिए 'मूत्र करने का अधिकार' अभियान चलाना पड़ रहा है। इस अभियान के तहत मुंबई के व्यस्ततम इलाकों में महिलाओं के लिए निःशुल्क, स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक मूत्रालयों की स्थापना की वकालत की जा रही है। इससे यह समझ पाना मुश्किल नहीं है कि देश में महिलाओं की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

छोटे और बड़े शहरों में सडकों, बाजारों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर पुरुषों के लिए यूरिनल आसानी से उपलब्ध होते हैं लेकिन महिलाओं के लिए ऐसी सुविधाएं या तो बहुत कम हैं या फिर बेहद खराब स्थिति में होती हैं। ऐसे में महिलाएं मूत्र रोकने को मजबूर हो जाती हैं या फिर असुरक्षित और अस्वच्छ जगहों पर जाने के लिए विवश होती हैं जिसका खामियाजा उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (यूटीआई), किडनी की समस्याओं और अन्य बीमारियों के रूप में भुगतना पड़ता है।

शहरों में ही नहीं, गांवों में भी महिलाओं के लिए शौचालय का अभाव है। कई बार सार्वजनिक शौचालय इतनी असुरक्षित स्थिति में होते हैं कि महिलाएं वहां जाने से डरती हैं। खुले में सार्वजनिक स्थानों पर निवारण करने से उनकी गरिमा और आत्म सम्मान पर असर पड़ता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का

अधिकार) और 15 (लैंगिक भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार) के तहत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। कुछ समय पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यस्थलों और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए टॉयलेट की कमी और मौजूदा टॉयलेट के खराब हालत पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेकर सरकार से जवाबतलब किया है। अपने आदेश में अदालत ने कहा है कि महिलाएं विकासशील देश की रीढ़ की भूमिका निभाती हैं। टॉयलेट के अभाव में महिलाओं को स्वास्थ्य की कई समस्याएं हो रही हैं। अदालत ने कहा कि घर से बाहर निकली महिलाएं अपने लिए टॉयलेट तलाश करती हैं लेकिन उन्हें या तो टॉयलेट ही नहीं मिलता या उसमें पर्याप्त साफ सफाई नहीं होती, जिस कारण महिला वापस घर पहुंचने तक यूरिन रोक लेती हैं। हाई कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि प्रदेश में अपने लिए शौचालयों की कमी के चलते महिलाएं कम पानी पीती हैं और यूरिन रोक लेती हैं, इससे उन्हें बीमारियां हो सकती हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी बिलासपुर जिले के 150 सरकारी स्कूलों में शौचालय न होने और 200 से अधिक स्कूलों में शौचालय उपयोग के लायक नहीं होने पर स्वतः संज्ञान लेकर सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट के ध्यान में आया कि स्कूलों में शौचालयों की कमी के कारण महिला शिक्षक और छात्राएं प्रभावित होती हैं क्योंकि उन्हें पेशाब करने के लिए खुले मैदान में जाना पड़ता है।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के प्रसंज्ञान लेने से जाहिर है कि अब यह केवल सामाजिक समस्या नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार का मामला भी बन गया है पर बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या का समाधान कब होगा? क्या मुम्बई की तर्ज पर सब जगह मूत्र त्याग का अधिकार अभियान चलाकर महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी?

महिलाओं की गंभीर समस्या को हल करने के लिए कोरो इंडिया ने जिस ह्यमूत्र करने का अधिकारह्न नामक महत्वपूर्ण अभियान की शुरूआत की है, वह इस गंभीर मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह पहल सिर्फ महिलाओं के लिए विशेष यूरिनल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है बल्कि यह महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और उनके मूलभूत अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है।

महिलाओं के लिए स्वच्छ और सुरक्षित यूरिनल की सुविधा कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार है जो उन्हें मिलना ही चाहिए। यह केवल उनके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा ही नहीं है बल्कि समानता, गरिमा और आत्मसम्मान का प्रश्न भी है। सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर इस विषय पर गंभीर पहल करनी होगी ताकि महिलाओं को एक ऐसा बुनियादी अधिकार पाने के लिए संघर्ष न करना पड़े जो पुरुषों को बिना किसी प्रयास के उपलब्ध है।

कोरो इंडिया के इस अभियान के बारे में सुनकर एकबारगी किसी को भी अजीब लग सकता है पर इस पर विचार करने से समझ में आता है कि यह मुद्दा कितना गंभीर है और इस पर चर्चा करना क्यों जरूरी है? यह अभियान महिलाओं के लिए सार्वजनिक यूरिनल के अभाव को 'सामान्य स्थिति' मानने की मानसिकता को चुनौती देता है। दरअसल, यह महिलाओं की लंबे समय से ऐसी उपेक्षित समस्या है, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की दरकार है। किसी भी समस्या का हल बात करने से ही निकलता है। अगर हम इस पर व्यापक विचार-विमर्श करेंगे तो महिलाओं की यह मांग मजबूती से उठेगी। शासन और प्रशासन पर दबाव बनेगा और इससे महिलाओं के जीवन को और अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

यह जरूरी है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए अधिक संख्या में स्वच्छ और सुरक्षित यूरिनल बनाए जाएं। महिला शौचालयों के बाहर सीसीटीवी कैमरे, उचित रोशनी, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और नियमित सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। जरूरी है कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट नीति बना कर तत्काल नए बिल्डिंग प्लान में महिला यूरिनल अनिवार्य करने जैसे कदम उठाए। शिक्षा का अधिकार की तर्ज पर कमूत्र करने का अधिकारत जैसे अभियान चलाने पर महिलाओं का मजबूर होना हमारे लिए शर्मिन्दगी का विषय है। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

सोशल मीडिया और महिलाओं की प्रतिष्ठा

उमेश कुमार साहू

वर्तमान डिजिटल युग में, सोशल मीडिया महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मंच तो बना है, लेकिन इसके साथ ही यह उत्पीड़न, भेदभाव और साइबर अपराधों का नया माध्यम भी बन चुका है।

सोशल मीडियाः महिलाओं के लिए अवसर या खतरा?

सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपने विचार व्यक्त करने, कैरियर बनाने और सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का एक बेहतरीन मंच प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाएं आर्थिक स्वतंत्रता, शैक्षणिक अवसर और वैश्विक समुदाय से जुड़ने का लाभ उठा रही हैं। लेकिन दूसरी ओर, यह ऑनलाइन उत्पीड़न, निजता के हनन और मानसिक प्रताड़ना का अड्डा भी बनता जा रहा है।

सोशल मीडिया पर महिलाओं का शोषणः बढ़ती चुनौतियां

1. साइबर हैरसमेंट और ट्रोलिंग

महिलाएं सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते ही ट्रोलिंग और साइबर बुलिंग का शिकार हो जाती हैं। विशेष रूप से राजनीति, समाज, धर्म और लैंगिक समानता जैसे संवेदनशील विषयों पर बोलने वाली महिलाओं को अश्लील टिप्पणियों और धमकियों का सामना करना पड़ता है। यह न केवल उनकी मानसिक शांति को प्रभावित करता है, बल्कि उनकी सामाजिक भागीदारी को भी सीमित कर देता है।

2. मॉर्फिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग

महिलाओं की तस्वीरों को मॉर्फ कर उनका दुरुपयोग करना एक गंभीर अपराध बन चुका है। कई मामलों में, यह ब्लैकमेलिंग, धमकियों और मानसिक प्रताड़ना का कारण बनता है। इससे पीड़िताओं को गहरे मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है और कई बार वे सामाजिक बहिष्कार का शिकार भी होती हैं।

3. साइबर स्टॉकिंग और निजता का उल्लंघन

सोशल मीडिया पर महिलाओं के हर कदम पर नजर रखना, उनके पोस्ट्स को ट्रैक करना, उनकी व्यक्तिगत जानकारियां हासिल कर उन्हें

परेशान करना, साइबर स्टॉकिंग का प्रमुख रूप है। यह न केवल महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल पैदा करता है, बल्कि उनकी आजादी और आत्मनिर्भरता को भी बाधित करता है।

4. डीपफेक टेक्नोलॉजी और महिलाओं की छवि धूमिल करना

डीपफेक टेक्नोलॉजी के माध्यम से महिलाओं की नकली वीडियो और तस्वीरें तैयार कर उन्हें बदनाम करने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह तकनीक ऑनलाइन उत्पीड़न का एक नया और खतरनाक रूप बन चुकी है, जिससे महिलाओं की प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि को गहरी ठेस पहुँचती है।

समाधान और आवश्यक कदम

इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार, टेक्नोलॉजी कंपनियों और समाज को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही, प्रत्येक महिला को अपनी डिजिटल सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी।

1. मजबूत साइबर कानून और सख्त कार्रवाई

सरकार को साइबर अपराधों से निपटने के लिए सख्त कानून लागू करने चाहिए और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।

2. डिजिटल साक्षरता और आत्मरक्षा

महिलाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वे अपनी ऑनलाइन उपस्थिति को सुरक्षित रख सकें। उन्हें यह समझना चाहिए कि कैसे वे अपनी निजता की रक्षा कर सकती हैं और साइबर अपराधियों से बच सकती हैं।

3. सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर कड़ी निगरानी

सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी नीतियों को और अधिक सख्त बनाना चाहिए और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्टिंग और कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को प्रभावी बनाना आवश्यक है।

4. जागरूकता अभियान और सामुदायिक सहयोग

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएँ अपने अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जान सकें। इसके साथ ही, समाज को भी महिलाओं का समर्थन करना चाहिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करनी चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह उनके अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी अवसर है। सोशल मीडिया महिलाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए समाज, सरकार और टेक्नोलॉजी कंपनियों को एकजुट होकर कार्य करना होगा।

महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा केवल उनकी व्यक्तिगत चिंता नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब महिलाएँ निर्भीक होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगी और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी, तभी एक न्यायसंगत और समतावादी समाज की स्थापना संभव हो पाएगी। आइए, इस महिला दिवस पर संकल्प लें कि हम महिलाओं को सुरक्षित डिजिटल भविष्य प्रदान करने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
भारतीय जनता पार्टी
भाई याद राम
M. 9810555891
उपाध्यक्ष अ.जा. मोर्चा
ज़िला नजफगढ़, दिल्ली प्रदेश
ऑफिस:बी-16, शनि बाज़ार, मैट्रो रेस्टोरेन्ट के पीछे, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059
प्रधान रैगर समाज महापंचायत उत्तम नगर

विज्ञान में महिलाओं का योगदान

विजय गर्ग
वरिष्ठ स्तंभकार

हर साल, दुनिया विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है। यह विशेष दिन केवल एक फैंसी शीर्षक नहीं है; यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं के अद्भुत योगदान को पहचानने और उनकी सराहना करने का दिन है। यह भी एक समय है कि वे उन बाधाओं को स्वीकार करें जो वे सामना करते हैं और इन क्षेत्रों में लिंग अंतर को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि हम आ-ईडीडबयुजीआईएस का निरीक्षण करते हैं, हम एक ऐसी कहानी को फिर से लिख रहे हैं, जहां रूढ़िवादिता अब शानदार दिमाग को सीमित नहीं करती है, और लिंग जिज्ञासा को प्रतिबंधित नहीं करता है। इस दुनिया में, ग्राउंडब्रेकिंग खोजें विविध दृष्टिकोणों से निकलती हैं। हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां विज्ञान को "लड़कों के लिए" के रूप में लेबल नहीं किया जाता है, और महिला और लड़कियां इस समावेशी और अभिनव दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए हमने जो प्रगति की है, उसे मनाएं और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखें, जहां हर कोई, चाहे लिंग की परवाह किए बिना, विज्ञान की रोमांचक दुनिया में पनप सकता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास 2011 में वापस, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने एक बड़ी समस्या पर ध्यान दिया: पर्याप्त महिलाएं विज्ञान में नहीं जा रही थीं, भले ही उनके पास बहुत कुछ था। यह लोगों को बात कर रहा था, और 2013 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना पर सहमति व्यक्त की कि महिलाओं और लड़कियों के पास विज्ञान में एक ही मौके थे। इसमें कुछ साल लग गए, लेकिन 2015 में, उन्होंने आधिकारिक तौर पर 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, 'इनोवेशनः द मिसिंग लिंक फॉर वीमेन इन साइंस' थीम पर ध्यान केंद्रित किया। विज्ञान विषयों में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवसः प्रगति का जश्न मनाना, चुनौतियों को संबोधित करना हर साल, आईडीडबयुजीआईएस एक नया विषय चुनता है जो दिखाता है कि महिलाएं विज्ञान में कैसे प्रगति कर रही हैं। अतीत में, हमने 2018 में 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट में लैंगिक समानता के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और नवाचार और' कल के वैज्ञानिकों के लिए निवेश 'जैसी चीजों के बारे में बात की। 2023 में' कल के वैज्ञानिकों के लिए निवेश '। इस बार, हमारा ध्यान' सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महिला नेतृत्व "पर है। हम उन महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना चाहते हैं जो महिला वैज्ञानिक बेहतर भविष्य बनाने में निभाते हैं। विज्ञान के लिए महिलाओं का योगदान पूरे इतिहास में, महिलाओं और लड़कियों के दिमाग से शानदार विचारों ने वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से विचार किया है, उसे आकार दिया है। उनके शोध, आविष्कार, नवाचा-रों और खोजों ने हमारे जीवन को समृद्ध किया है और एक आशाजनक भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, वैज्ञानिक क्षेत्रों में उतनी महिलाएं नहीं हैं जितनी पुरुष हैं। महिलाओं ने विज्ञान के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए अलग -अलग समय पर बाधाओं को पार कर लिया है, जब सही वातावरण प्रदान करने पर उनकी क्षमता साबित होती है। दुर्भाग्य से, विज्ञान में महिलाओं द्वारा कई ग्राउंडब्रेकिंग योगदान की अनदेखी की गई है। एक उदाहरण रोजालिंड फ्रैंकलिन है, एक रसायनज्ञ जिसका काम डीएनए की संरचना की खोज में महत्वपूर्ण था। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, मान्यता केवल मरणोपरांत आ गई। अन्य अनसंग नायिकाओं में नासा में अफ्रीकी-अमेरिकी गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन, डोरोथी वॉन और मैरी जैक्सन शामिल हैं। उन्होंने शुरूआती अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पुस्तक और फिल्म, 'हिडन फिगर्स' को प्रेरित किया, जिसने उनकी उपलब्धियों को सुर्खियों में लाया। मैडम क्यूरी से, केवल 8 वर्षों के भीतर भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला, शाकंटला देवी को, जो अपनी अविश्वसनीय गणितीय क्षमताओं के लिए भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में जानी जाती है। हम बात करते हैंविज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के बारे में। यूनेस्को के अनुसार, दुनिया भर में 30% शोधकर्ता महिलाएं हैं। हालांकि, यह प्रतिशत एक ही क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में एक असमानता को उजागर करता है। इसे पहचानते हुए, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विज्ञान में महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने और प्रोत्साहित करने और अनुसंधान में लिंग अंतर को पाटने के लिए मनाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की सूची 1। जनाकी अम्मल उसके बिना, चीनी आज जिस तरह से मीठा हो सकता

है। वह पेशे से एक साइटोजेनेटिक और वनस्पति विज्ञानी थीं, जिन्होंने समाज द्वारा लगाए गए रूढ़िवादी नियमों को तोड़ दिया और हजारों पौधों की प्रजातियों पर शोध करने में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह चीनी को मीठा बनाने के पीछे का कारण खोजने वाला था। उसे उस नवाचार का श्रेय दिया जाता है और उसे 1977 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। वह केरल में साइलेंट वैली हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में विद्रोही थी। उन्होंने हजारों पुष्प प्रजातियों के गुणसूत्रों पर व्यापक अध्ययन भी किया और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान दिया। 2। अन्ना मणि वह 1918 में पैदा हुई थी। फिर, महिलाओं को विज्ञान का अध्ययन करने या तथाकथित सामाजिक नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं थी। वह इन सभी नियमों को धता बताते हुए आगे बढ़ी और मौसम विज्ञान में अपना शोध शुरू किया। उन्होंने प्रो सीवी रमन की प्रतिभा के तहत भी काम किया और मौसम विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। सौर विकिरण, पवन ऊर्जा और ओजोन पर उनके शोध ने उन्हें वैश्विक अभिनय लाया। वह भारतीय मौसम विभाग की उप निदेशक बन गईं। 3। टेसी थॉमस 1963 में जन्मी, उन्होंने मानक सामाजिक नियमों को तोड़ दिया और एक भारतीय मिसाइल परियोजना के प्रमुख के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक बन गईं। कल्पना कीजिए कि कैसे वह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक पुरुष-प्रधान वैज्ञानिक क्षेत्र में एक शानदार योगदानकर्ता बनने में कामयाब रही। वह ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय वैज्ञानिक थीं, जो अब हमारे पास मौजूद सैन्य शक्ति के स्तर को बढ़ाती थीं। वह एक गृहिणी हैं जो अग्नि क्ष्र और वी मिसाइलों के विकास के लिए परियोजना निदेशक बनने के लिए चली गईं। यह 5,500 किमी की सीमा के साथ एक ठोस-ईंधन अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। 4। कल्पना चावला उसका नाम कौन नहीं जानता है? वह हरियाणा, भारत से पहली भारतीय मूल महिला एरोनॉटिकल इंजीनियर थी। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने के लिए नासा की चुनी हुई इंजीनियर थी। वह राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय और दूसरी भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कल्पना चावला उनके योगदान के कारण, उन्हें कांग्रेस के स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा के प्रतिष्ठित सेवा पदक और नासा स्पेस फ्लाइट मेडल से सम्मानित किया गया। दुर्भाग्य से, वह सभी 6 अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ एसटीएस -107 मिशन में कोलंबिया स्पेस शटल में लौटते समय मर गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक शौकीन भरतनाम डांसर, एक पेशेवर स्कूबा गोताखोर और एक कराटे चैंपियन थी। 5। शकुंतला देवी जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, उसे भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। कुछ सेकंड के भीतर जटिल गणितीय संचालन करने की उसकी उल्लेखनीय शक्ति ने पूरी दुनिया को चकित कर दिया। उसने एक बार 2010 अंकों के साथ एक नंबर की 23 वीं रूट की गणना की। उसने किसी भी उपकरण या यहां तक कि एक कलम का उपयोग किए बिना मानसिक रूप से किया और 1977 में सबसे तेज कंप्यूटर यूनीवैक की तुलना में 12 सेकंड तेजी से किया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शाकंटला देवी के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी। जब वह 6 साल की थी, तब उसने अपनी गणितीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया। 6। मैरी क्यूरी मैरी क्यूरी, वें में एक अग्रणीरेडियोधर्मिता का ई क्षेत्र, विज्ञान में महिलाओं के लिए एक आइकन बना हुआ है। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थीं और दो अलग -अलग वैज्ञानिक क्षेत्रों - भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला बनी हुई हैं। उनकी खोजों ने चिकित्सा उपचारों में प्रगति की नींव रखी और महिला वैज्ञानिकों की भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भूमिका ये सभी नाम इस बात का प्रमाण हैं कि महिलाओं ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये नाम केवल भारतीय मूल के हैं। इस सूची की लंबाई की कल्पना करें जब महिला वैज्ञानिकों और आविष्कारकों के अंतर्राष्ट्रीय नाम शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी प्रतिभा पूल को बढ़ाएगी और भविष्य में उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करेगी। यह महिलाओं को सशक्त भी करेगा और उन्हें विज्ञान के अपने संबंधित क्षेत्रों को चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और गणित में महिलाओं के महत्व और भूमिका को समझने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा, सामाजिक भूमिका मॉडल को जन्म देगा और भविष्य की पीढ़ी को उसी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। महिलाओं ने विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वे अक्सर अद्वितीय चुनौतियों का सामना करती हैं। लिंग पूर्वाग्रह, असमान अवसर, और नेतृत्व भूमिकाओं में प्रतिनिधित्व की कमी लगातार मुद्दे हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों और कैरियर की आकांक्षाओं को संतुलित करना जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, समावेशिता को बढ़ावा देना, रूढ़ियों को चुनौती देना और वैज्ञानिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कार्य-जीवन संतुलन और मेंटरशिप कार्यक्रमों का समर्थन करने वाली पहल अधिक सहायक वातावरण बनाने में योगदान कर सकती है। आधुनिक-दिन के नायकः आज विज्ञान को आकार देने वाली महिलाएं चुनौतियों के बावजूद, महिलाएं आज विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही हैं। प्राइमेट्स पर अपने ग्राउंडब्रेकिंग शोध के लिए प्रसिद्ध डॉ। जेन गुडॉल ने न केवल पशु व्यवहार की हमारी समझ को उन्नत किया है, बल्कि एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता भी बन गए हैं। एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में, डॉ। केटी बुमन ने ब्लैक होल की पहली छवि को कैप्चर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका काम लिंग बाधाओं पर काबू पाने में सहयोग और दृढ़ संकल्प की शक्ति का उदाहरण देता है। विज्ञान में महिलाओं को सशक्त बनाना विज्ञान में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तर पर कई पहल चल रही हैं। मेंटरशिप कार्यक्रम, छात्रवृत्ति और नेटवर्किंग के अवसर महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। लड़कियों को कम उम्र से एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना एक विविध और समावेशी वैज्ञानिक समुदाय के निर्माण में आवश्यक है। इसके अलावा, वैज्ञानिक संस्थानों और उद्योगों के भीतर समावेशिता की संस्कृति को बढ़ावा देना अनिवार्य है। विज्ञान में महिलाओं की उपलब्धियों को पहचानना और जश्न मनाना, अनुसंधान टीमों में विविधता को बढ़ावा देना, और लिंग पूर्वाग्रहों को संबोधित करना एक अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाने में योगदान देता है। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

रमेश सर्राफ धमोरा
वरिष्ठ पत्रकार

अब महिलाओं के प्रति बदलना होगा नजरिया

भारत वह देश है जहां महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत का खास ख्याल रखा जाता है। अगर हम इक्कीसवीं सदी की बात करे तो यहां की महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रही है। अब तो भारत की संसद ने भी महिलाओं के लिये लोकसभा व विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक पास कर दिया है। उससे आने वाले समय में भारत की राजनीति में महिलाओं की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगी। देश में महिलाओं को अब सेना में भी महत्वपूर्ण पदो पर तैनात किया जाने लगा है। जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार है। महिलाएं देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है तथा विकास में भी बराबर की भागीदार है। आज के युग में महिला पुरुषों के साथ ही नहीं बल्कि उनसे दो कदम आगे निकल चुकी है। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार महिलाओं को भी पुरुषों के समान जीवन जीने का हक है। भारत में नारी को देवी के रूप में देखा गया है। कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। प्राचीन काल से ही यहां महिलाओं को समाज में विशिष्ट आदर एवं सम्मान दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च 1911 से पूरे विश्व में मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम है 'कार्रवाई में तेजी लाना'। वर्ष की 2025 थीम में सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण होगी। जो वैश्विक स्तर पर महिलाओं और लड़कियों की प्रगति को रोकने वाली प्रणालीगत बाधाओं को तोड़ने के लिए समावेशन और तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालती

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में भारत में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 अपराध दर्ज किए गए। इन अपराधों में बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध, और अपहरण जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के सामने आए हैं। जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति हमारी उदासीनता को दर्शाते हैं। इससे पहले 2022 में 4,45,256 मामले, 2021 में 4,28,278 मामले 2020 में 3,71,503 मामले दर्ज किए गए थे।

एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति एक लाख आबादी पर महिला अपराध की दर 66.4 फीसदी रिकॉर्ड की गई। ऐसे मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 75.8 फीसदी

रही। एनसीआरबी ने बताया कि भारतीय दंड संहिता के तहत महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा 31.4 फीसदी जुर्म पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता किए जाने के थे। इसके बाद अपहरण के 19.2 फीसदी, शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमले के 18.7 फीसदी और दुष्कर्म के 7.1 फीसदी मामले रहे। एनसीआरबी के मुताबिक पिछले साल देश में जितने मामले सामने आए उनमें से 2,23,635 यानी 50 फीसदी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में 2021 में महिला अपराध के 56,083 और और 2020 में 49,385 मामले दर्ज किए थे। इसके बाद राजस्थान (40,738 और 34,535), महाराष्ट्र (39,526 और 31,954), पश्चिम बंगाल (35,884 और 36,439) और मध्य प्रदेश (30,673 और 25,640) रहे थे।

भारत में वर्षो से महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानून बने है। इसमें हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, इंडियन पीनल कोड 1860, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861, क्रिस्चियन मैरिज एक्ट 1872, मैरिड वीमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874,चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, फॉरेन मैरिज एक्ट 1969, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल कमीशन फॉर वुमन एक्ट 1990, सेक्सुअल हर्रास्मेंट ऑफ वुमन एट वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 आदि। इसके अलावा 7 मई 2015 को लोक सभा ने और 22 दिसम्बर, 2015 को राज्य सभा ने जुवेनाइल जस्टिस बिल में भी बदलाव किया है। इसके अन्तर्गत यदि कोई 16 से 18 साल का किशोर जघन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है तो उसे भी कठोर सजा का प्रावधान है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर से पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिलीं। इसमें 16 हजार से ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं। आंकड़े हैरान कर देने वाली हैं। क्योंकि आयोग में ये शिकायत गरिमा के अधिकार कैटेगरी के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2,411 मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में 1,343, बिहार में 1,312 और मध्य प्रदेश में 1,165 इतने मामले दर्ज किए गए हैं।

2023 के 12 महीने बाद जारी किए गए इस रिपोर्ट में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध में दहेज उत्पीड़न और दुष्कर्म जैसे अपराध दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की यह रिपोर्ट महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता दिखाती है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में यौन उत्पीड़न के 805 मामले, साइबर अपराध के 605 मामले, पीछा करने की 472 मामले और सम्मान से जुड़े अपराध के खिलाफ 409 शिकायतें दर्ज कराई गईं। आंकड़ों के मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बलात्कार के मामले भी शामिल हैं। साल 2023 में बलात्कार और बलात्कार के प्रयास के 1,537 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गरिमा के अधिकार के तहत 8,540, घरेलू हिंसा के 6,274, दहेज उत्पीड़न के 4,797, छेड़छाड़ के 2,349,और महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता के 1,618 मामले दर्ज किए गए।

2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2022 की तुलना में कम हुए हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 30,864 मामले दर्ज किए गए थे। जबकि 2023 में यह संख्या घटकर 28,278 हो गई। यह एक सकारात्मक संकेत है लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साल 2022 के बाद से शिकायतों की संख्या में कमी देखी गई है। जब 30,864 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जो 2014 के बाद से सर्वाधिक आंकड़ा था। जहां तक बात महिलाओं की सुरक्षा की आती है तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अभूतपूर्व निर्णयों से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किये हैं। आज भारत में महिलायें पहले की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है।

हम एक तरफ महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देकर उन्हे आगे बढ़ा रहें है। वहीं दूसरी तरफ उनके साथ अत्याचार की घटनाओं में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आये दिन हमें महिलाओं के साथ बलात्कार, दुर्व्यवहार होने की घटनाये सुनने को मिलती रहती है। ऐसी घटनाओं से महिला सशक्तिकरण के अभियान को धक्का लगता हैं। देश में महिलाओं के प्रति खराब होते माहौल को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं अपितु हर आम आदमी की भी है। हम सभी को आगे आकर महिला सुरक्षा की लड़ाई में महिलाओं का साथ देना होगा तभी देश की मातृ शक्ति सर उठा कर शान से चल सकेगीं। अब महिलाओं को समझना होगा कि आज समाज में उनकी दयनीय स्थिति समाज में चली आ रही परम्पराओं का परिणाम है। इन परम्पराओं को बदलने का बीड़ा स्वयं महिलाओं को ही उठाना होगा। तभी समाज में उनके प्रति सोच बदल पाएगी। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

II Radha Swami II

Rajkumar +919810570832

OM JEWELLERS

Gold ● Silver ● Diamond ● GEMS
●& Hallmark Jewellery

A-1/54,
Hastsal Road,
Uttam Nagar,
New Delhi
PIN-110059,

●omjwlrs@gmail.com

सोना-चांदी साधती बेहाथ तीरंदाज शीतल

अरुण नैथानी

यह कल्पना से भी परे है कि एक बेटी, जिसे कुदरत ने हाथ न दिए हों, वह आत्मबल व सतत साधना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी करने लगे। समाज का हेय दृष्टि से देखना उसकी ताकत बन जाए। निस्संदेह, सुबह जिसकी स्वर्णिम हुई सचमुच साधना में वह सारी रात जागा होगा। इस बात को सिद्ध करती है एशियायी पैरा खेलों में स्वर्ण, विश्व स्पर्धा में रजत और पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली शीतल। जम्मू की शीतल के तीर विजय की अग्नि बरसाते हैं। बिना हाथ के वह सोने-चांदी के तमगे बटोरती है। कल तक जो लोग उस पर व उसके परिवार पर हिकारत के फिक्रे कसते थे, वे आज वाह-वाह कहते नहीं थकते। हाल में उनकी चर्चा ब्रिटिश ब्रॉड कास्टिंग सर्विस के इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड जीतने के रूप में हो रही है। उन्हें हाल में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2024 श्रेणी में यह सम्मान दिया गया। दरअसल, उन्हें यह सम्मान भारत की सबसे कम उम्र पैरालंपिक पदक विजेता की उपलब्धि हासिल करने पर दिया गया।

यह कल्पना करते हुए रोमांच होता है कि कैसे बिना हाथ की एक लड़की ने तीरंदाजी जैसे धैर्य व साधना वाले खेल में भविष्य तलाशने का मन बनाया। बिना हाथ के तीरंदाजी का अभ्यास करना एक दुष्कर कार्य ही है। कैसे वह धनुष उठाती होगी और कैसे सधे निशाने लगाती होगी, आम आदमी को यह समझने के लिये माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन यह हकीकत है कि कुछ ही वर्षों में शीतल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। वर्ष 2022 में एशियायी पैरा खेलों में उन्होंने दो स्वर्ण व एक रजत पदक जीतकर तहलका मचाया। फिर वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में चांदी का पदक जीता। फिर तो ये सोने-चांदी के पदक उसकी प्रेरणा बन गये। उसके मन में देश के लिये पैरालंपिक में पदक जीतने का जज्बा जगा। उसने जमकर

पसीना बहाया। हासिल पदकों ने उसे नई ऊर्जा दी। कहते हैं दृढ़ संकल्प से इंसान असंभव को भी संभव बना लेता है। यही हुआ। शीतल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कांस्य पदक जीत तिरंगा लहरा कर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। निस्संदेह, शीतल की कामयाबी उस हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है जिसके साथ कुदरत ने शारीरिक रूप से न्याय नहीं किया। उन लोगों के लिये भी जो जरा-जरा सी नाकामी से आत्मघात की राह चुनते हैं। बहरहाल, शीतल की सफलता के अग्निबाण सतत साधना के ही सुफल हैं। उसकी मेहनत तब पता चलती है जब शीतल कुर्सी पर बैठकर अपने दाहिने पैर से धनुष उठाती है। उसके बाद अपने कंधे का प्रयोग स्ट्रिंग को पीछे खींचने में करती है। फिर जबड़े की ताकत के इस्तेमाल से तीर को छोड़ती है। ऐसी मुश्किल में निशाने साधने वाली इस बेटी की मुक्तकंठ से प्रशंसा ही की जानी चाहिए।

दरअसल, जम्मू की रहने वाली अठारह वर्षीय का जन्म असाध्य रोग फोकोमेलिया के साथ हुआ। जिसकी वजह से उसकी बांह विकसित नहीं हो पायी। जब वह पैदा हुई तो स्वाभाविक रूप से उसके मां-बाप उसके भविष्य को लेकर आशंकित हुए। लोग-बागों के तानों ने उनकी मुश्किलों को बढ़ाया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि बिना हाथ के भी वह अपने दृढ़ संकल्प व परिश्रम से सोने-चांदी की इबारत लिखेगी।

निस्संदेह, शीतल की यह राह इतनी भी आसान नहीं थी। एक अनाम से गांव में एक साधारण किसान के घर जन्मी शीतल ने पंद्रह साल तक तो धनुष-कमान देखी भी नहीं थी। ईश्वरीय संयोग से उसका जीवन बदलने वाले धैर्यवान कोच कुलदीप वेदवान से उनकी मुलाकात श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड खेल परिसर में हुई। फिर उनकी तैयारी कटरा में एक प्रशिक्षण शिविर में हुई। सही मायनों में शीतल के धैर्य व क्षमता को देखते हुए तीरंदाजी में कामयाबी के सपने उन्हें कोच कुलदीप वेदवान ने ही दिखाए। वे जानते थे कि शीतल के पैरों में अपार क्षमता है क्योंकि वह सभी काम इनकी मदद से ही करती थी। फिर उन्होंने पैरों व ऊपरी शरीर की ताकत से निशाने साधने का प्रशिक्षण शीतल को दिया। लेकिन इस ताकत को संतुलित करके लक्ष्य में बदलने का रास्ता आसान भी नहीं था। शुरूआत में शीतल को कष्ट हुआ तो हौसला कमजोर हुआ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी प्रेरणा विदेशी खिलाड़ी थे, लेकिन उनके जैसे साधन भारत जैसे देश में नहीं थे। विदेशों में प्रशिक्षण दिलाने की क्षमता उनके सामान्य माली हालत वाले परिवार में नहीं थी। उनकी क्षमता के अनुसार धनुष-बाण बनाने से लेकर निशाने साधने में दक्षता हासिल करना एक श्रमसाध्य मार्ग था। फिर मुंह की मदद से तीर छोड़ने के उपकरण तैयार किए गए, जो उनकी जटिल शारीरिक स्थिति में मददगार हो सकें। उसकी कोच अभिलाषा चौधरी ने उसकी कमियों, ताकत व उपकरणों में साम्य स्थापित करने में खासी मदद की। शीतल के लिये विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया। कठिन प्रशिक्षण से शीतल के तीर निशानों को बेधने लगे। लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भी रखा गया। जिससे धीरे-धीरे उनका आत्मबल बढ़ा। उन्हें विभिन्न दूरी के लक्ष्यों के लिये प्रशिक्षण दिया गया। छोटे लक्ष्यों से बड़ी सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। शीतल में सोने-चांदी के तमगे जीतने की भूख पैदा हुई। फिर दुनिया के सामने शीतल के द्वारा एशियाई खेलों में स्वर्ण, वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में चांदी का पदक और पेरिस पैरालंपिक में कांस्य जीतने की कहानी सामने आई। निस्संदेह, शीतल की साधना करोड़ों भारतीयों के लिये प्रेरणापुंज ही है। ●

विश्वनाथ सचदेव
वरिष्ठ पत्रकार, जानेमाने स्तंभकार

संकीर्णता से बौना बनते नेता

भूल जाना आदमी की फितरत है। आदमी अच्छी बातें भी भूल जाता है, और बुरी बातें भी। बुरी बातों को भूल जाना तो अच्छी बात है, पर कुछ अच्छी बातों को भूल जाना अच्छा नहीं है। ऐसी ही अच्छी बात वर्ष 1965 की भारत-पाक लड़ाई है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। पता नहीं कितनों को याद होगा कि उस लड़ाई में अब्दुल हमीद नाम का एक भारतीय सैनिक भी था, जिसने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट करके हमारी जीत को संभव बना दिया था। तब क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद ने हमें जिता तो दिया, पर अपनी जान की कीमत देकर। कृतज्ञ राष्ट्र ने उस जांबाज शहीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था।

इस शहीद का जन्म उत्तर प्रदेश के दुल्लहपुर नामक गांव में हुआ था। गांव वालों ने अपने इस सपूत के सम्मान में गांव के स्कूल का नाम वीर अब्दुल हमीद उच्च प्राथमिक विद्यालय रखा था। बरसों से यह नाम गांव की एक पहचान बना हुआ था। कुछ ही अर्सा पहले स्कूल का नाम बदल दिया गया। नया नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय धामपुर कर दिया गया। क्यों बदला गया, किसी ने नहीं बताया। बस बदल दिया!

नाम बदलने की यह अकेली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से मऊ को जोड़ने वाली सड़क पर बने एक द्वार का नाम ऐसे ही बदल दिया गया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम का यह द्वार बुलडोजर चला कर गिरा दिया गया। मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर बने एक कॉलेज की दीवारें गिरा देने वाला समाचार भी हाल ही का है। यह बात भुला दी गई कि मुख्तार अहमद अंसारी कभी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आजादी की लड़ाई के दौरान यह पद संभालने वाले अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की नींव रखने वालों में थे।

नाम बदलने का यह सिलसिला अब नया नहीं लगता। चौंकाता भी नहीं। पिछले दो दशकों में न जाने कितनी जगह के नाम बदले गए हैं। ज्यादातर नाम मुसलमानों के हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? नाम बदलने से इतिहास नहीं बदलता। औरंगजेब ने भले ही अत्याचार किए हों, पर वह वर्षों तक इस देश में शासन करता रहा, यह हकीकत तो अपनी जगह है। फिर, हम क्यों भूल जाते हैं कि किसी औरंगजेब को याद करने का मतलब उन अत्याचारों की भी याद दिलाता है, जिनसे हमारे इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं। ऐसी बातों को याद रखना इसलिए भी जरूरी है कि इन्हें दुहराया न जाए।

बहरहाल, जगहों के नाम बदलना कोई नयी बात नहीं है। पर इस प्रक्रिया के पीछे की मानसिकता को भी समझा जाना चाहिए। ऐसा नहीं

है कि शहरों आदि के नाम बदलने का काम सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में ही हो रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, द्रमुक आदि पार्टियों ने भी अपने-अपने शासन काल में इस तरह नाम बदले हैं। सच्चाई यह है कि अक्सर यह बदलाव राजनीतिक स्वार्थ का परिणाम होते हैं। अपने-अपने हितों के लिए हमारे राजनीतिक दल अक्सर जगहों का नाम बदलना एक आसान मार्ग समझ लेते हैं। लेकिन, यह आसान मार्ग अक्सर राष्ट्रीय हितों से भटका देता है, इस बात को भुलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।

देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की जो कवायद इस समय चल रही है वह उन सबके लिए चिंता का विषय होनी चाहिए जो राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। सन 2012 से 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के नाम बदले गए थे, और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। इलाहाबाद का प्रयागराज होना या फैजाबाद को अयोध्या नाम दिया जाना तो फिर भी कुछ समझ आता है, पर गोरखपुर के उर्दू बाजार को हिंदी बाजार नाम देने का क्या तुक है? न जाने कब से यह विवाद चल रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस बाजार में एक तरफ की दुकानों के बोर्ड पर पता उर्दू बाजार लिखा होता था और दूसरी तरफ हिंदी बाजार। इस बाजार को यह नाम इसलिए दिया गया होगा कि यहां अधिकतर दुकानों पर उर्दू किताबें बिकती थीं। किताबों की कुछ दुकानें अब भी हैं। दोनों भाषाओं की किताबें बिकती हैं यहां, शायद उर्दू की किताबों वाली दुकानें संख्या में अधिक हों। इस उर्दू बाजार को हिंदी बाजार नाम देने की जिद क्यों? इस तरह की ज़िद से समाज जुड़ता या बनता नहीं, टूटता और बिखरता है।

उत्तर प्रदेश में एक और अभियान भी चल रहा है- उर्दू को कठमुल्ला बनाने की भाषा घोषित करने का! राज्य की विधानसभा में कार्रवाई के अवधी, बृज आदि अनुवादों की व्यवस्था की गई है। जब सदन में यह मांग की गई कि ऐसी व्यवस्था उर्दू के लिए भी की जानी चाहिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा- उर्दू माध्यम से पढ़ाकर कठमुल्ले बनाए जा रहे हैं। इस पर विवाद होना स्वाभाविक था। विवाद चल भी रहा है। किसी भी भाषा के प्रति इस तरह के विचार रखना अपने आप में किसी अपराध से कम नहीं है। पर हमारे राजनेता ऐसे अपराध को राजनीतिक स्वार्थ साधने का माध्यम मानते हैं। यही नहीं, अब तो यह भी खुलेआम कहा जा रहा है कि उर्दू इस देश की भाषा ही नहीं है। कौन बताए कि उर्दू भाषा का जन्म इसी भारत में हुआ है, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ के आस-पास। उर्दू के पक्ष में आवाज उठाने वालों को पाकिस्तान भेजने की बात करने वालों को यह कौन समझाए कि उर्दू पाकिस्तान के किसी भी हिस्से की भाषा नहीं थी। पाकिस्तान ने यह भाषा हमसे ली है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू को पाकिस्तान की राजभाषा बनाने के विरोध में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। मीर, गालिब, फिराक, मंटो जैसे रचनाकारों की भाषा है उर्दू। इसे कठमुल्ला बनाने वाली भाषा कहकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वास्तव में अनुचित ही कहा है। उन्हें शायद यह भी याद नहीं, या वे याद रखना नहीं चाहते, कि वर्ष 1989 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.डी. तिवारी ने उर्दू को राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया था।

योगी आदित्यनाथ शायद यह भी भूल गए हैं कि भाषा के आधार पर राजनीति करना देश के उस संविधान का उल्लंघन करना है जिसका गुणगान वे अक्सर करते रहते हैं। उन्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि जिस भाषा को वह कठमुल्लों की भाषा कह रहे हैं, उसके शब्द हिंदी में भरे पड़े हैं। बिना उर्दू शब्दों वाली हिंदी की कल्पना करना भी मुश्किल है। बिना उर्दू शब्दों के हिंदी के पांच वाक्य लिखना अपने आप में एक चुनौती है।

हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि किसी भी भाषा को धर्म के साथ जोड़ना अपने आप में एक अपराध है। जिस तरह हिंदी सिर्फ हिंदुओं की नहीं, भारत की भाषा है, उसी तरह उर्दू सिर्फ किसी धर्म विशेष की नहीं, पूरे भारत की भाषा है। भले ही अलग-अलग राज्यों में विभिन्न भाषाएं हों, पर हैं सब भारत की भाषाएं। हमें यह नहीं भूलना है कि हमारी भाषाओं के इस गुलदस्ते की सुंदरता इसी विविधता का परिणाम है। भाषा को राजनीति का मोहरा बनाना भी किसी अपराध से काम नहीं। कब समझेंगे हमारे राजनेता कि भाषा की राजनीति उन्हें बौना बना रही है, अपराधी भी? ●

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

शेखर गुप्ता
वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रमुख स्तंभकार

अफसरशाही पर ट्रंप और मोदी का विपरीत नजरिया

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जिस समय ईलॉन मस्क को देश की अफसरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने के अधिकार दे दिए हैं, लगभग उसी समय भारत में मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी कर दी है।

इनमें से पहला यानी ट्रंप का कदम सरकार का आकार कम करने और खर्च घटाने का नाटकीय तथा अराजकता भरा प्रयास है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कदम सरकार के आकार और वेतन पर होने वाले खर्च में विस्तार से जुड़ा है, जो 2029 के चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। दोनों नेताओं ने कमोबेश एक से वादे पर चुनाव जीता। हम मोदी की बात को तरजीह देंगेः न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।

प्रशासन और उस पर आने वाले खर्च पर दोनों नेताओं के नजरिए में अंतर का इससे बेहतर उदाहरण शायद नहीं मिलेगा। ट्रंप एक तरह से बागी हैं, जो अफसरशाहों को बहुत बुरा मानते हैं। चुनाव में कोई जीते, कोई हारे, अफसरशाह अपना कार्यकाल आराम से पूरा करते हैं। वे नियम कायदों के हिसाब से देश चलाते हैं या उसे चलाने में सरकार की मदद करते हैं।

परिभाषा के हिसाब से उन्हें किसी तरह की राजनीतिक या वैचारिक वफादारी नहीं करनी होती। इस व्यवस्था में तो वफादारी को बहुत खराब माना जाता है। ट्रंप की नजर में यह अश्लीलता है। उनके लिए यह अनिर्वाचित लोगों की सत्ता है, जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसीलिए वह इसे समाप्त करना चाहते हैं।

मोदी के लिए अफसरशाह निरंतरता, बदलाव और वफादारी के प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रशासनिक ढांचे और कर्मी जब तक मौजूदा राजनीति के हिसाब से ढले रहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। यही वजह है कि हमने मोदी युग में यूपीएससी से चुने गए अफसरशाहों को सबसे ज्यादा अधिकारसंपन्न बनते देखा।

आठवें वेतन आयोग का गठन तो रूपक भर है। मोदी के कार्यकाल में केंद्र सरकार का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए लुटियन की दिल्ली से बाहर की नई दिल्ली देखें तो आपको विकास के साथ ढेरों नए 'भवन' बने दिख जाएंगे।

ट्रंप के अमेरिका में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के नवनियुक्त प्रमुख वॉशिंगटन में बना एफबीआई मुख्यालय नष्ट करने और उसके कर्मचारियों की छंटनी करने और उनको अल्बामा जैसे स्थानों पर भेजने की बातें कहकर चर्चा में आ गए हैं। यह तो वही बात हुई कि भारत में सीबीआई के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश में कुशीनगर या सोनभद्र अथवा तेलंगाना में मेडक या आंध्र प्रदेश में कुरनूल भेज दिया जाए।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के निकट सीजीओ कॉम्प्लेक्स में नया और विशाल भवन मिला है। दिल्ली पुलिस को लुटियंस दिल्ली के मध्य एक शानदार नया ठिकाना मिल गया है। आईटीओ चौराहे के पास बना उसका पुराना मुख्यालय अब भी उसके पास है। प्रवर्तन निदेशालय की अपनी इमारत है, जो खान मार्केट के निकट लोक नायक भवन के उसके पुराने कार्यालय के मुकाबले कई गुना बेहतर है। सच कहूं तो लोक नायक भवन कतई सरकारी झुग्गी है। किसी भी इंसान को वहां काम करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लुटियन की दिल्ली का पुनर्निर्माण करते समय इसे ढहा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन संस्थानों में शामिल है जिन्हें आईएनए मार्केट के पीछे बारापुला फ्लाईओवर के निकट बनी लाल बलुआ पत्थर वाली इमारत में एक पूरी मीनार मिल गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को कॉपरनिकस मार्ग पर अपना भवन मिल गया है और देश भर में उसके क्षेत्रीय केंद्र फैले हुए हैं। कोई भी यह नहीं पूछता कि इनमें बैठे अफसरशाहों का प्रदर्शन कामकाज के पैमाने पर कैसा है या ये संस्थाएं कैसा काम कर रही हैं। इसी तरह केंद्र और राज्यों में भी सभी अपेक्षाकृत नए संस्थानों (जरूरी नहीं कि मोदी सरकार ने ही बनाए हों) का खूब विस्तार हुआ है और उन्हें खूब भवन मिले हैं। केद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के सूचना आयोग, राज्यों के लोकपाल और लोकायुक्त तथा कई पंचाट इसमें शामिल हैं।

अब सरकार के कारोबार पर नजर डालें तो

एयर इंडिया की बिक्री को छोड़कर लगभग सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम न केवल मोदी सरकार के अधीन बने रहे बल्कि उनमें जनता के पैसे से भारी-भरकम नया निवेश भी किया गया। इस वर्ष के बजट में 14.7 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के उपक्रमों में निवेश के लिए आवंटित किए गए हैं। राहुल गांधी अक्सर आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार सरकारी उपक्रमों को 'बेच' रही है। उधर मोदी खुद कई बार बता चुके हैं कि उनके कार्यकाल में इन उपक्रमों ने कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्र ने विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में 11,440 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है, जबकि दो दशक से इसके निजीकरण की बात चल रही थी।

केंद्रीय उपक्रमों ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है? जब निफ्टी और सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से 13 फीसदी गिरे हैं, तब इन उपक्रमों का सीपीएसई इंडेक्स 30 फीसदी लुढ़क चुका है! इससे करीब 13 लाख करोड़ रुपए या करीब 23 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। जरा सोचिए भारत इतने पैसे से क्या कर सकता था? देश में उत्तर से दक्षिण तक जाने वाली बुलेट ट्रेन बनाई जा सकती थी? पीएम किसान सम्मान की राशि कई गुना बढ़ाई जा सकती थी? या शायद एफ-35 विमानों के दो बेड़े खरीदे जा सकते थे, जिससे ट्रंप भी खुश हो जाते। ध्यान रहे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दशकों से कहते रहे हैं कि 'जिस देश का राजा व्यापारी, उस की प्रजा भिखारी।'

मोदी के नेतृत्व वाले भारत में सरकार के बहुत अधिक हस्तक्षेप की समस्या कभी नहीं रही। यहां खर्च की भी बात नहीं है। अफसरशाह चुनकर नहीं आते यह भी अच्छी बात मानी जाती है। वैचारिक शुद्धता तो आदर्श स्थिति है, लेकिन जहां यह नहीं होती वहां अफसरशाहों को काबू करने के उपाय होते हैं-पुरस्कार या दंड के जरिए। बेहतरीन जगह पर नियुक्ति, अधिकार और आप ज्यादा काम के हैं तो आपको कभी सेवानिवृत्त ही नहीं होने दिया जाएगा।

शुरू में प्रमुख पदों पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया मसलन भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में। मगर उसके बाद हम भरोसेमंद आईएएस के दौर में लौट आए हैं। अवर सचिव के स्तर पर सीधी भर्ती का विचार तो एकदम काफूर हो गया। अर्थशास्त्री संजीव सान्याल के अधीन कम से कम एक साहसी प्रयास चल रहा है, जिसमें सरकारी रोजगार कार्यक्रम के तहत बने ढेरों संस्थान बंद किए जा रहे हैं। यह अच्छी पहल है। ध्यान रहे कि हमारी व्यवस्था में किसी की नौकरी नहीं जाती। उन्हें बस कहीं और भेज दिया जाता है।

मोदी के मंत्रिमंडल में भी अब विदेश मंत्रालय से लेकर पेट्रोलियम, रेलवे, आईटी आदि मंत्रालयों की कमान पूर्व अफसरशाहों के हाथ में है। मोदी को वहां राहत मिलती है, जहां ट्रंप की नफरत बरसती है। हमें नहीं पता कि कौन अच्छा है कौन बुरा क्योंकि किसे पता कि ट्रंप की नीतियां अमेरिका को कहां ले जाएंगी? हम केवल यह कह रहे हैं कि शासन का ढांचा तैयार करने का ट्रंप और मोदी का तरीका एक दूसरे के उलट है।

मोदी और भाजपा के समर्थकों के लिए डीप स्टेट (नीतियों पर असर डालने वाली गैर सरकारी ताकतें) वह निराकार सत्ता है, जिसमें ग्लोबल फाउंडेशन, वाम एक्टिविस्ट निकाय और निवेशक तथा उनके सहयोगी खुफिया तंत्र शामिल माने जाते हैं। वहीं ट्रंप के लिए डीप स्टेट ऐसी जगह है जहां अनिर्वाचित नौकरशाह रहते हैं, कई राष्ट्रपतियों के दौर में काम करते रहते हैं और राजनीतिक आदेश के आगे सर नहीं झुकाते। वह इसे नष्ट करना चाहते हैं और न्यायाधीशों के साथ भी वह ऐसा ही करेंगे।

ट्रंप और मोदी अलग-अलग ढंग के नेता हैं। उनके राजनीतिक तौर तरीके और शैलियां अलग हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह उनकी शासन शैली में कैसे नजर आता है? ●

प्रवासियों की वापसी पर सियासत की चुप्पी

आदिति फडणीस

भारत और अमेरिका के रिश्तों पर देसी राजनीति में हमेशा से ही गरमागरम बहस होती रही है। अमेरिका ने 1956 में भारत की गुटनिरपेक्षता को 'अनैतिक और बेवकूफाना' बताया था, जिसके बाद पूरी संसद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ खड़ी हो गई थी। इंदिरा गांधी ने 1971 में तत्कालीन सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके साथ यह बात भी साफ हो गई कि भारत सोवियत संघ के पाले में खड़ा है। उस समय अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर हो रहा था। इस संधि को इंदिरा गांधी की चाल भी कहा जाता है, जो उन्होंने 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद अपने नेतृत्व को मिल रही चुनौती खत्म करने के इरादे से चली थी।

उन्होंने अमेरिका को 'विदेशी ताकत' करार देते हुए उसके प्रति शत्रुता की धारणा गढ़ी और उसे हवा भी दी। बाद में हुए चुनावों में यह राजनीतिक जुमला बन गया, जिसका जमकर इस्तेमाल किया गया। भारत और अमेरिका के बीच 2008 में जब असैन्य परमाणु समझौता हुआ तो मनमोहन सिंह सरकार की तीखी आलोचना के बीच वामपंथी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिरते-गिरते बची। उनका कहना था कि 'इस समझौते के जरिये भारत की विदेश नीति की संप्रभुता के साथ समझौता किया गया है'।

फिर भी अमेरिका से हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारत भेजे गए अपमानित और हताश भारतीयों की तस्वीरों ने भी देश की राजनीति में कोई हलचल नहीं मचाई। आखिर क्यों?

नितिन पटेल के सितारे आज गर्दिश में हैं मगर उनका नाम गुजरात की राजनीति में अनजाना नहीं है। वह छह बार विधायक रह चुके हैं और 2016 से 2017 तथा फिर 2017 से 2021 तक राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे। पिछले 20 साल में उन्होंने वित्त तथा राजस्व समेत कई मंत्रालय भी संभाले हैं। उन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और मेहसाणा लोकसभा सीट से दावेदारी ठोकने के बाद पिछले साल बिना कोई कारण बताए अचानक दौड़ से बाहर चले गए।

इसीलिए जब पटेल ने संवाददाताओं को बुलाकर राज्य सरकार से हथकड़ी और बेड़ियों में अमेरिका से वापस भेजे गए लोगों का अधिक ध्यान रखने की बात कही तो लोगों ने उन्हें गौर से सुना। अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों में सबसे ज्यादा तादाद गुजरातियों की

ही है और उनमें भी काफी लोग मेहसाणा से आते हैं, जहां पटेल का अच्छा-खासा रसूख है। पटेल ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना करते हुए जब कहा, 'मैं राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूं कि उन लोगों को परेशान नहीं किया जाए' तो असल में वह अपने राजनीतिक करियर को नई सांस देने की कोशिश भी कर रहे थे। राज्य सरकार ने जवाब में 'अवैध' बांग्लादेशी प्रवासियों को धर पकड़ा और शिविरों में रख दिया, जहां से उन्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा।

अमेरिका से हुए प्रत्यर्पण पर राजनीतिक खेमे की प्रतिक्रिया दिलचस्प है। गुजरात समेत पूरे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं, जिन्हें उन लोगों से कोई भी सहानुभूति नहीं है और जिन्हें लगता है कि उनके साथ सही हुआ है। उदाहरण के लिए हरियाणा की राजनीति में खलबली मचाने के आदी मंत्री अनिल विज ने कहा, 'हर देश को अवैध रूप से रहने वालों को वापस भेजने का अधिकार है और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बिल्कुल सही किया है।' विज सात बार के भाजपा विधायक हैं और राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आलोचना करने के कारण उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। दिलचस्प है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की राय भी विज की तरह ही थी। खट्टर ने कहा कि किसी भी देश में अवैध रूप से घुसने वाले 'अपराधी' होते हैं।

पड़ोसी राज्य पंजाब में वापस भेजे गए लोगों का पहला जत्था सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से हवाई अड्डे पर मिला। उसके बाद से धालीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान को हवाई अड्डा जाने से रोक दिया गया है। मान खीझकर पूछ रहे हैं कि वापस आ रहे लोगों को पंजाब के हवाई अड्डों पर ही क्यों उतारा जा रहा है। मान कहते हैं, 'दिल्ली के बजाय आपने अमृतसर क्यों चुना? यह पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने के लिए किया गया।' साथ ही वह यह भी पूछते हैं कि अगर ये लोग निर्दोष हैं और अपराधी नहीं हैं तो हरियाणा सरकार उन्हें पुलिस की गाड़ियों में आगे क्यों भेज रही है। गुजरात का विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया जताने में ढीला दिखा। कांग्रेस को पिछले हफ्ते तब सुधि आई, जब अमेरिका से अवैध प्रवासियों के तीन जत्थे देश आ चुके थे। पार्टी के विधायक काले कपड़े पहनकर और खुद को बेड़ियों में जकड़कर विधानसभा के बाहर खड़े हो गए।

इस तरह वे लोगों को याद दिलाना चाहते थे कि सरकार को जिन्होंने वोट दिया उन्हीं के साथ किस तरह विश्वासघात किया गया है। यह बात अलग है कि विधानसभा के बाहर लोग उन पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तेलंगाना में कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के हैदराबाद दफ्तर के बाहर जमा हो गए। उनमें से कुछ हथकड़ी पहने थे और बाकी के हाथ में 'मनुष्य हैं अपराधी नहीं' लिखी तख्तियां थीं।

कई जत्थों की वापसी हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठाकर यह पक्का क्यों नहीं कर रहे कि वापस भेजे जा रहे लोगों के साथ गरिमा भरा व्यवहार हो। उद्धव ठाकरे की शिव सेना के संजय राउत ने सीधे कदम उठाने की हिमायत की। उन्होंने कहा, 'अमेरिकी जहाजों (जिन पर हथकड़ियों में लोग लाए गए थे) को उड़ने या उतरने ही नहीं दिया जाए।' संसद में भी इस मसले पर गतिरोध दिखा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान भी दिया।

प्रत्यर्पण का यह मामला थकी और उबाऊ राजनीति को जगाने वाले पटाखे का काम कर सकता था मगर लोग इसके विरोध में सड़कों पर ही नहीं आए। उसके बजाय राजनेता अपनी ही पार्टी के नेतृत्व से बदला लेने के इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या विपक्षी नेता इसके बहाने सरकार की आलोचना कर रहे हैं।

आम चर्चा का लब्बोलुआब हैः इन लोगों ने भारत में मिल रहे मौके छोड़ दिए और विदेश में देश की छवि खराब की। सरकार ने भी इस मसले का इस्तेमाल कर राजनीतिक पहल कर दी है, जिससे अमेरिका की तर्ज पर वह भी भारत में बैठे अवैध घुसपैठियों को उनके देश भेज सकती है। ●

(व्यक्त विचार लेखिका के अपने हैं)

दीप्ति अंगरीश
वरिष्ठ पत्रकार, चर्चित स्तंभकार

क्या अब दिल्ली की रूपरेखा बदलेंगी रेखा !

विकास के कई रास्ते होते हैं। दिल्ली में विकास अब आड़ी-तिरछी रेखाओं के सहारे नहीं चलेगी, बल्कि सीधे रास्तों का अनुसरण करेगी। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभाली है। भले ही कई लोग इस चुनाव को लेकर मन में कुछ सवालों को स्थान दें, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है। जो दिल्ली के विकास भवन से लेकर सीधी रेखा में लोक कल्याण मार्ग तक जाती है। वही लोक कल्याण मार्ग जहां 7 नंबर में समेकित विकास और समावेशी सोच के पैरोकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोहती देश की शासन-व्यवस्था को विकास की रेखा से जोड़ते हैं।

दरअसल, रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय रही हैं और विभिन्न दायित्वों को संभाल चुकी हैं। उन्हें एक जमीनी नेता के रूप में जाना जाता है, जो आम जनता के मुद्दों को उठाने में आगे रहती हैं। भाजपा के महिला मोर्चा से लेकर स्थानीय निकाय राजनीति तक, उन्होंने लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

यूं ही शासन-प्रशासन में महिलाएं बेहतर काम करती आ रही हैं। राजनीति और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री की बात करें, तो दिल्ली को पहली महिला मुख्यमंत्री का सम्मान बीजेपी को जाता है, जब अक्टूबर 1998 में सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री पद पर रहीं। माना उनका कार्यकाल सिर्फ दो महीने का ही रहा। इसके बाद कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतकर शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाया, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल तक राज्य की सेवा करती रहीं। उनका कार्यकाल दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद आतिशी 152 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं। इसके बाद दिल्ली

की मुख्यमंत्री बनीं है रेखा गुप्ता। या कह सकते हैं कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं रेखा गुप्ता।

दिल्ली में महिला नेतृत्व का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। जहां पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित जैसी मजबूत महिला नेताओं ने राज्य की राजनीति में अपनी पहचान बनाई, वहीं अब रेखा गुप्ता भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। उनकी नियुक्ति इस बात का प्रतीक है कि महिलाएं राजनीति में अपनी स्थायी जगह बना रही हैं और उनके नेतृत्व से राज्य की राजनीति में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार और रेखा गुप्ता का नेतृत्व आने वाले समय में राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनके नेतृत्व में दिल्ली के लोग एक और मजबूत महिला मुख्यमंत्री देखेंगे, जो राज्य की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगी।

अब राजनीति की बात करें, तो 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनी है। बीजेपी ने अपनी यात्रा वहीं से शुरू करने का निर्णय लिया, जहां पिछली बार यह थमी थी। सुषमा स्वराज के बाद रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री चुनकर दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री देने का कार्य किया गया है। यह निर्णय दिल्ली की राजनीति में महिला नेतृत्व को और सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने से दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में नया जोश और दिशा देखने को मिल सकती है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत दिया है, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार शामिल हैं। कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू हो रहा है, जहां रेखा गुप्ता के रूप में राज्य को एक बार फिर महिला नेतृत्व प्राप्त हुआ है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी और लगातार दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ, दिल्ली ने यह साबित कर दिया कि महिला नेतृत्व न केवल सक्षम है, बल्कि उसे राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। ●

(व्यक्त विचार लेखिका के अपने हैं)

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चार शिक्षाविदों को शिखर सम्मान

डॉ. ध्रुब कुमार को रामकृष्ण परमहंस शिखर सम्मान

डॉ. पी के वर्मा को डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिखर सम्मान

प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार को विवेकानंद शिखर सम्मान

डॉ. महेश प्रसाद सिंह को रविन्द्र नाथ टैगोर शिखर सम्मान

प्रो. (डॉ.) मधु प्रभा सिंह को 'तस्वीर' एवं 'तुम कहो न' भेंट

बी. डी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) विवेकानंद सिंह का सम्मान

डॉ अरविंद कुमार सिन्हा को सम्मानित करते हुए भेंट की गई 'तस्वीर'

डॉ. ध्रुब कुमार को रामकृष्ण परमहंस शिखर सम्मान

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ए. एन. कॉलेज में पीजी हेड से अवकाश प्राप्त शिक्षाविद डॉ ध्रुब कुमार को उनके आवास पर सम्मान प्रदान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें रामकृष्ण परमहंस शिखर सम्मान से नवाज़ा गया। इस सम्मान के तहत उन्हें शॉल, शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं दूसरा मत का साहित्य-विशेषांक भेंट की गई। यह सम्मान दूसरा मत के संपादक एवं 'सामना' के लेखक ए आर आज़ाद ने उन्हें उनके योगदानों के मद्देनज़र प्रदान किया।

प्रो. (डॉ.)ध्रुब कुमार ए. एन. एस. कॉलेज बाढ़ के प्राचार्य रहे हैं। इनका एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है। राजनीति विज्ञान के प्रोफ़ेसर के तौर पर शिक्षण जगत में एक मुक़ाम हासिल करने वाले प्रो. (डॉ.) ध्रुब कुमार कई कार्यशालाओं एवं सेमिनारों में हिस्सा लिया और आयोजित किया।

प्रो. (डॉ.)ध्रुब कुमार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के सदस्य भी हैं। शैक्षणिक परिषद के भी सदस्य हैं। और सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य हैं। इन्होंने टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार में प्रति-कुलपति का दायित्व भी संभाला है। वे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रतिकुलपति भी रहे हैं। इन्होंने अब तक एक दर्जन से अधिक पुरस्कारों को ग्रहण किया है। इनमें कुछ प्रमुख पुरस्कारों में नागालैंड के कुलाधिपति और मगध विश्वविद्यालय, बोधगया के कुलपति के हाथों सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का पुरस्कार भी शामिल है। इसके अलावा इन्हें आईयूटीएसएफ ने शिक्षा में ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट पुरस्कार 2013 से भी नवाज़ा है।

इन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में भी हिस्सा लिया, जिनमें ऑरलैंडो, फ्लोरिडा, यू.एस.ए. ,मॉन्ट्रियल (कनाडा), लास वेगास, नेवादा, यू.एस.ए. शामिल हैं। यहां इन्होंने 'भारत में दूरस्थ शिक्षा की स्थिति' शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से दो दर्जनों से अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सेमिनारों में भी हिस्सा लिया। इन्होंने यूएसए एवं कनाडा का भी दौरा किया। इनकी देखरेख में पीएच.डी. की कई डीग्रियां प्रदान की गईं।

इनकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। इनमें 'इंदिरा गांधी और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था', 'भारत में लोकतंत्र-चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ', बिहार सुशासन की ओर' 'नीतीश कुमार - विकास की राजनीति' आदि शामिल हैं।

प्रो. (डॉ.) ध्रुब कुमार कई संस्थाओं के सदस्य और आजीवन सदस्य भी हैं।

शिक्षा के औचित्य पर इनके विचार हैं कि रचनात्मक क्षमता हम सभी में है, इसे समृद्ध बनाने के लिए शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से इसका समर्थन और संवर्धन किया जाना चाहिए। रचनात्मकता सीखने का सबसे अच्छा तरीका इसका अभ्यास करना है।

उनका मानना है कि 'रचनात्मकता' शब्द अक्सर किसी भी मौजूदा घटक से जुड़े बिना नवीनता बनाने का निहितार्थ व्यक्त करता है, जबकि एक विरोधाभासी परिभाषा यह हो सकती है कि रचनात्मकता का अर्थ है विभिन्न स्रोतों से मौजूदा विचारों को एक नए वातावरण में संचारित, संयोजित और लागू करके कुछ नया उत्पन्न करना।

उनका मानना है कि आज भारत में उच्च शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि के बजाय गुणात्मक वृद्धि की आवश्यकता है। अपने विकास को बनाए रखने के लिए, भारत को बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली जनशक्ति की आवश्यकता है। और इस उद्देश्य के लिए उसे हर साल अपने कुछ मिलियन अतिरिक्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करने का तरीका खोजना होगा। इस शिक्षा के लिए, बदले में, वास्तविक संसाधनों, वास्तविक शिक्षकों और वास्तविक कॉलेजों की आवश्यकता होती है। ●

डॉ. पी के वर्मा को डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिखर सम्मान

राम लखन सिंह यादव कॉलेज बख़्तियारपुर के प्राचार्य डॉ पी के वर्मा शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना-पहचाना नाम है। शिक्षा जगत में उनके योगदानों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें डॉ सर्वपल्ली राधा कृष्णन शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान के तहत उन्हें शॉल, प्रशस्ति-पत्र, शील्ड एवं दूसरा मत का साहित्य- विशेषांक भेंट की गई। यह सम्मान उन्हें पुस्तक 'बेटी : एक ग़ज़ल' के लेखक ए आर आज़ाद ने अपने हाथों से प्रदान किया।

मालूम हो कि डॉ. पी. के. वर्मा, एक ऐसा नाम है जिसे शिक्षा जगत में किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। डॉ. वर्मा ने क़रीब 40 वर्ष पूर्व पटना के मीठापुर स्थित बी. डी. कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर अपना योगदान दिया।

गौरतलब है कि बी. डी. कॉलेज में योगदान से पूर्व डॉ. वर्मा ने प्रतिष्ठित पटना यूनिवर्सिटी, पटना से स्नातकोत्तर (भौतिकी) में सर्वोच्च अंक पाने वालों में से एक थे। समय के साथ दिन-प्रतिदिन डॉ. वर्मा की ख्याति विद्यार्थियों एवं शिक्षा जगत में तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। अनूठे अंदाज़ में उनका पढ़ाना एवं सरल से सरल शब्दों में विद्यार्थियों को जटिल से जटिल भौतिकी समझाना उनकी ख़ासियत बन गई। यही कारण रहा कि उन्हें विद्यार्थियों के बीच सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक माना जाने लगा।

डॉ. वर्मा के पर्यवेक्षण में तकरीबन 10 शोधकर्ताओं ने पी.एच.डी की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही साथ इन्होंने तक़रीबन 30 शोधपत्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की हैं, जो की स्कोपस इंडेक्स्ड एवं यूजीसी केयर में भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने शिक्षा जगत में अपने योगदान एवं उपलब्धि के लिए अनेकों अवार्ड भी हासिल किए हैं।

डॉ. वर्मा ने शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ समय-समय पर मिले प्रशासनिक ज़िम्मेदारी को बख़ूबी निभाया है। इन्होंने बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा में प्रति कुलपति के रूप में भी अपना योगदान दिया है। इन्हें चार-चार विश्वविद्यालय में कुलसचिव के रूप में कार्य करने का पूर्ण अनुभव भी प्राप्त है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पटना स्थित अनेकों प्रतिष्ठित महाविद्यालय जैसे ए. एन. कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, बी. डी. कॉलेज, श्री अरविंद महिला कॉलेज, राम कृष्ण द्वारिका महाविद्यालय, एस. एम. डी. कॉलेज, पुनपुन तथा आर एल एस वाई. बख़्तियारपुर में प्रधानाचार्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं हैं। ●

प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार को विवेकानंद शिखर सम्मान

वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, आरा की कंस्टीट्यूएंट यूनिट एस पी जैन कॉलेज, सासाराम के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं विशिष्ट योगदान के लिए विवेकानंद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके प्रिंसिपल ऑफ़िस में प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार एवं 'दूसरा मत' के संपादक ए आर आज़ाद ने प्रदान किया। इस मौक़े पर उन्हें शॉल, प्रशस्ति-पत्र एवं शील्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्हें 'दूसरा मत' का साहित्य विशेषांक भी भेंट की गई। इसी के साथ उन्हें 30 से अधिक मौलिक पुस्तकों के लेखक ए आर आज़ाद ने अपनी ताज़ातरीन दो पुस्तकें 'रेल की पटरियां' एवं 'ये शाहीन बाग़ है', भेंट की।

मालूम हो कि एस पी जैन कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और इन्होंने तीन विषयों में एम.ए. के साथ-साथ एम.एड., पी-एच.डी. एवं डी.लिट्. भी हैं।

मालूम हो कि प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार 2009 से अबतक स्थाई प्रधानाचार्य के पद पर सेवारत हैं। वे आधा दर्जन से अधिक महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य रहे हैं। इनके अब तक 25 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने लगभग 40 विभिन्न सम्मेलनों एवं सेमिनारों में शोध पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार चार पुस्तकों के लेखक भी हैं। इन्होंने भूगोल विषय से संबंधित चार महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में भूटान से 'द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड' से इन्हें नवाज़ा गया। इसी तरह इन्होंने इस वर्ष यानी 2025 में इन्डोनेशिया के बाली में पेपर प्रस्तुत किया है। इन्होंने 21 शोधार्थियों को अपने मार्गदर्शन में पीएच.डी. की डिग्री भी दिलाई है। इतना ही नहीं अपनी कार्यकुशलता का बेहतर नतीजा पेश करते हुए उन्होंने अपने नेतृत्व में एस.पी. जैन कॉलेज को नैक (NAAC) से 2024 में ग्रेडिंग करवाया है।

प्रो. (डॉ.) नवीन कुमार विश्वविद्यालय के सिनेट, सिंडीकेट, विद्वत परिषद के सदस्य एवं प्राक शिक्षा ज़िला केंद्र रोहतास के निदेशक भी हैं। ●

डॉ. महेश प्रसाद सिंह को रविन्द्र नाथ टैगोर शिखर सम्मान

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के सरदार पटेल मेमोरियल (एसपीएम) कॉलेज के प्राचार्य डॉ महेश प्रसाद सिंह को उनके ऑफ़िस में सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए समर्पित किया गया। बिहार शरीफ़ में मौजूद सरदार पटेल मेमोरियल (एसपीएम) कॉलेज के प्राचार्य डॉ महेश प्रसाद सिंह को रविन्द्र नाथ टैगोर शिखर सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान के तहत उन्हें शॉल, शील्ड, प्रशस्ति-पत्र एवं दूसरा मत का साहित्य-विशेषांक भेंट की गई। यह सम्मान दूसरा मत के संपादक एवं देश की चर्चित पुस्तक 'बेटी : एक ग़ज़ल' के लेखक ए आर आज़ाद ने उन्हें उनके योगदानों के मद्देनज़र प्रदान किया। ●

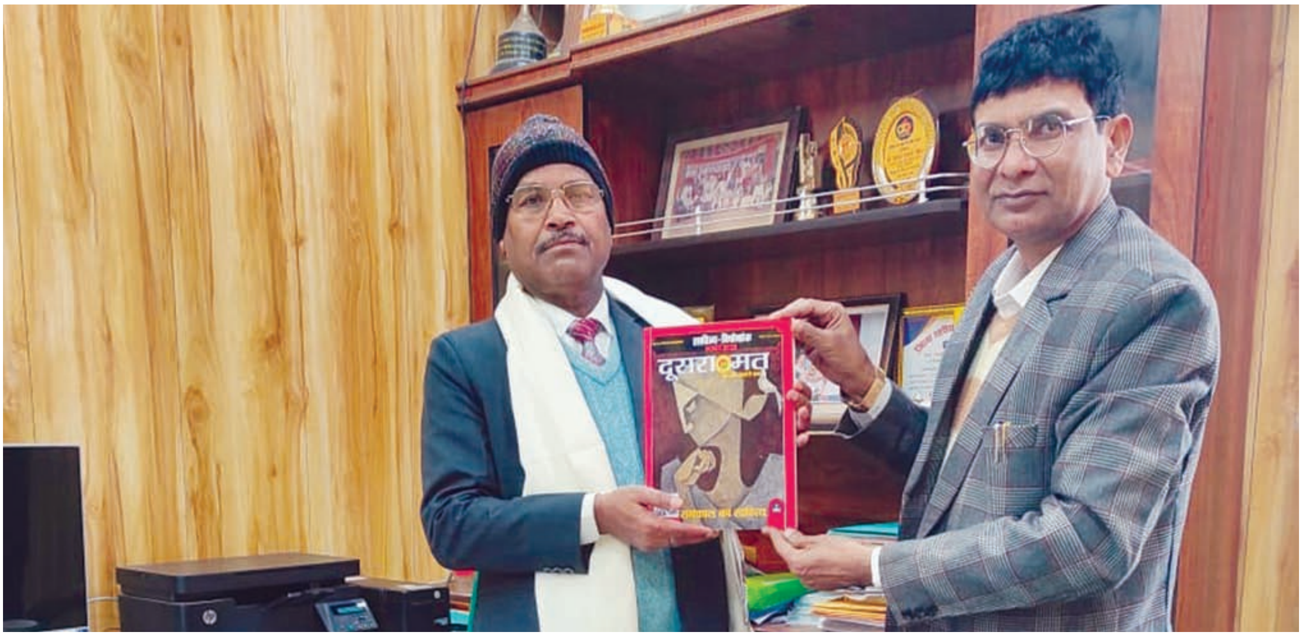

प्रो. (डॉ.) मधु प्रभा सिंह को 'तस्वीर' एवं 'तुम कहो न' भेंट

प्रो. (डॉ.) मधु प्रभा सिंह पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की घटक इकाई जेएनएल कॉलेज यानी जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल की प्राचार्य हैं। ये कॉलेज दानापुर रेलवे स्टेशन के क़रीब है। इसी के साथ वे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ही एक अन्य घटक इकाई बी.एस कॉलेज, दानापुर की भी प्राचार्य हैं।

प्रो. (डॉ.) मधु प्रभा सिंह से बी.एस कॉलेज, दानापुर में एक अनौपचारिक भेंट हुई। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, तो बी.एस कॉलेज, दानापुर की स्थिति और परिस्थिति पर भी खुलकर चर्चा हुई। हॉस्टल से लेकर खेल के मैदान तक पर चर्चा हुई। कई एकड़ में फैले इस महाविद्यालय परिसर में उनके साथ ख़रामा-ख़रामा चलते हुए खेल के मैदान का भी नज़ारा किया। और उस हॉस्टल को भी अपनी आंखों से देखा, जिस पर कभी अवैध क़ब्ज़ा भी हुआ करता था। हॉस्टल को क़ब्ज़े से मुक्त कराने में प्रो. (डॉ.) मधु प्रभा की अहम भूमिका रही है। कॉलेज को संवारने और इसे एक नई दिशा देने में भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है।

बातों का सिलसिला खेल के मैदान और हॉस्टल से होते हुए प्राचार्य कक्ष तक पहुंचा। प्राचार्य कक्ष सुंदर और सजा हुआ दिखा तो अनायास एक प्रश्न लाज़मी था। लेकिन उन्होंने इसे सहज भाव में लेते हुए कहा कि यहां नया कुछ नहीं है, बल्कि नए तरह से इसको तरतीब दी गई है। सारे के सारे सामान बस वही के वही पुराने हैं। इसे ही हमने नया लुक दिया है। इसके बाद चाय का एक दौर चला। फिर मैंने उन्हें अपनी ताज़ा तरीन दो पुस्तकें भेंट की। एक पुस्तक 'तस्वीर' एवं दूसरी पुस्तक 'तुम कहो न' बराए नजर की। और यही भेंट इस मज़मून का सबब भी बनी। ●

बी.डी.कॉलेज के प्रिंसिपल प्रो.(डॉ.)विवेकानंद सिंह का सम्मान

पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित बी. डी कॉलेज, पटना के प्रिंसिपल प्रो. (डॉ.) विवेकानंद सिंह को उनके कार्यालय में दूसरा मत के संपादक एवं देश के जानेमाने साहित्यकार और 30 से अधिक मौलिक पुस्तकों के लेखक ए आर आज़ाद ने उन्हें शॉल भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्हें देश की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक 'सामना' भेंट की। इसके साथ ही उन्हें कविता-संग्रह 'तस्वीर' एवं कहानी-संग्रह 'निः शब्द' भी भेंट की। इस मौक़े पर उनसे कई अहम मुद्दों के साथ साहित्य, समाज और पत्रकारिता पर भी बातचीत हुई।

मालूम हो कि प्रो. (डॉ.) विवेकानंद सिंह का जन्म पटना ज़िले के दानापुर कैंट के पास एक छोटे से गांव में हुआ। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में एम.ए. की डिग्री प्राप्त की। उन्हें पटना विश्वविद्यालय से ही पी.एच.डी. की डिग्री प्रदान की गई है। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से ही बी.एड. और एल.एल.बी. की डिग्री भी प्राप्त की है। वे 1996 में BRABU के अंतर्गत B.M.D. कॉलेज में मनोविज्ञान में सहायक प्रोफ़ेसर के रूप में नियुक्त हुए।

उन्होंने 2011 से 2023 तक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी.एस. कॉलेज दानापुर पटना में सेवाएं दीं। जनवरी, 2024 से वे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत बी.डी. कॉलेज पटना में प्राचार्य हैं।

अध्यापन में भी उनकी बहुत अच्छी योग्यता और पकड़ है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में अपने कई शोध-पत्र प्रस्तुत किए हैं। कई पत्रिकाओं में उनके कई लेख प्रकाशित हुए हैं। वे कई पत्रिकाओं और मनोवैज्ञानिक समितियों जैसे JAAP MIER, ISC, GJP आदि के आजीवन सदस्य हैं।

इतना ही नहीं प्रो. (डॉ) विवेकानंद सिंह ने पीएचडी की डिग्री के लिए उम्मीदवारों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन भी किया है। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के एम.ए के पाठ्यक्रम के लिए एक पुस्तक लिखी है। एक अन्य पुस्तक प्रकाशनाधीन है।

आशा और विश्वास है कि उनकी गतिविधि और कार्यशीलता उन्नत कार्यशैली के मद्देनज़र बेहतर परिणाम लेकर सामने लाएगी।●

बिहटा के जी. जे. कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ) अरविंद कुमार सिन्हा को सम्मानित करते हुए भेंट की गई 'तस्वीर'

इसी कड़ी में रामबाग़ बिहटा के जी. जे. कॉलेज के प्राचार्य प्रो. (डॉ) अरविंद कुमार सिन्हा से आत्मीय भेंट करते हुए उनके योगदानों का सहज समर्थन और मान किया गया। इस भेंट के बीच उन्हें दूसरा मत के संपादक ए आर आज़ाद ने अपनी ताज़ातरीन काव्य-संग्रह की विमोचित पुस्तक 'तस्वीर' एवं साहित्य-विशेषांक भेंट की। इस मौक़े पर जी. जे. कॉलेज के बरसर एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ मुकेश कुमार को साहित्य-विशेषांक भेंट की गई।

साहित्यकार डॉ. मुकेश कुमार को साहित्य-विशेषांक की गई भेंट

▸▸ के. पी. मलिक
वरिष्ठ पत्रकार

प्राकृतिक संपदा अपार बावजूद पिछड़ता कृषि क्षेत्र

प्राकृतिक संपदा के नजरिए से हिंदुस्तान दुनिया में तकरीबन सबसे अच्छा देश माना जाता है, इसलिए हिंदुस्तान कृषि और पशुपालन के क्षेत्र के रूप में भी अति संपन्न देश माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ हिंदुस्तान में वो सब कुछ पैदा होता है, जिसकी लोगों को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हिंदुस्तान का कुल भौगोलिक क्षेत्र तकरीबन 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का तकरीबन 2.4 फीसदी है, जबकि हिंदुस्तान में दुनिया की तकरीबन की 17.8 फीसदी आबादी रहती है और कृषि उत्पादन के लिहाज से हिंदुस्तान में तकरीबन दुनिया के 17 से 17-5 फीसदी लोगों का पेट भरने के लिए अनाज, दालें, सब्जियां, फल इत्यादि पैदा होते हैं। इसके साथ ही मसाले इतने पैदा होते हैं जिनसे तकरीबन दुनिया के 30 फीसदी लोगों का काम चल सकता है। इतना ही नहीं नमक उत्पादन में भी हिंदुस्तान का कोई मुकाबला दुनिया में आसानी से नजर नहीं आता है। कृषि के लिए कई तरह की उपजाऊ मिट्टी, जल संसाधन, जिनमें नदियों और जमीन के पानी से लेकर वर्षा तक का भरपूर पानी है। जैव संपदा समेत कई अन्य संपदाओं का खजाना भी हिंदुस्तान में भरपूर है और यहां की जलवायु भी इतनी उपयोगी और महत्वपूर्ण होती है कि जो हिंदुस्तान में आता है, वो फिर यहां की धरती को छोड़ना ही नहीं चाहता। यह दूसरी बात है कि यहां के राजनीतिक कारनामों, जाति-धर्म और क्षेत्रवाद के झगड़ों और गंदगी करने वाले लोगों ने कुछ सालों से विदेशियों का मोहभंग किया है।

बहरहाल, हिंदुस्तान की संपदा का अगर हम आंकलन करें, तो यहां की भौतिक संपन्नता भले ही बराबर के हिसाब से लोगों में न बंटी हो, लेकिन यहां पर पहले विदेशियों की लूट होने से लेकर आज भी लगातार पूंजीपतियों और नेताओं द्वारा की जा रही लूट से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कितनी संपन्नता रही होगी और जो आज भी बरकरार है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भारत से इतना खजाना लूटा कि पूरे लंदन को चारों तरफ से चार बार उस पैसे से लपेटा जा सकता था। इसलिए कहा जाता है कि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, जिसका मतलब है कि यहां के हर घर में सोना हुआ करता था। यहां के ज्यादातर बड़े मंदिर सोने से मढ़े हुए थे। यही वजह रही कि अब तक न जाने कितने ही विदेशी, जो यहां लूटपाट करने आते थे, यहीं आकर बसते चले गए थे। बहरहाल, दुनिया की कुल कृषि योग्य भूमि की तकरीबन 11 फीसदी ही है, जिसमें से हिंदुस्तान के पास तकरीबन 56 फीसदी कृषि भूमि है। इसके अलावा पूरी दुनिया की जमीन पर कुल 64 तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा, तकरीबन 46 तरह की मिट्टी हिंदुस्तान में पाई जाती है। इसके अलावा औषधि योग्य वनस्पतियों में भी दुनिया में हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा हिंदुस्तान में बारिश भी साल में कई बार होने के साथ-साथ दूसरे माध्यमों से भी पानी की उपलब्धता काफी ज्यादा है।

आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन हर साल 4 हजार अरब घन मीटर बारिश होती है, ये दूसरी बात है कि हम इस बारिश के पानी का भी महज 10 से 15 फीसदी पानी ही अपने उपयोग में ला पाते हैं। देश का कुल भूभाग तकरीबन 32.87 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से तकरीबन 30 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर पानी आसानी से उपलब्ध है यानि ये 30 करोड़ हेक्टेयर का एरिया केचमेंट एरिया कहलाता है। पूरे देश में तकरीबन 4 सौ 45 नदियां हैं, जिनकी कुल लंबाई तकरीबन दो लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा झीलें, पोखर, तालाब आदि हैं। एक अनुमान के मुताबिक, आजाद हिंदुस्तान यानि साल 1947 में बारिश के पानी के संरक्षण के लिए तकरीबन 28 लाख झीलें, पोखर और तालाब हुआ करते थे। हालांकि अब पोखर और तालाबों को काफी ज्यादा संख्या में पाटकर लोगों ने वहां बसावट कर रखी है। भूजल की दृष्टि से भी हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा संपन्न देशों में से एक माना जाता है। लेकिन ये दुखद है कि न सिर्फ हमारे देश के ज्यादातर पूंजीपति और नेता आज सोने-चांदी के भाव वाला विदेशी पानी पीते है, बल्कि अपने देश की जमीन और नदियों के पानी को दूषित कराकर पानी का काला बाजार चलाकर कमाई कर रहे है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि जहां अधिक उपज प्राप्त करने की दृष्टि से हरित क्रांति को किसानों के लिए वरदान माना जाता है लेकिन इस क्रांति के चलते जमीन से जल का दोहन बड़ी मात्रा में दोहन किया गया है कि आज देश के तकरीबन 264 से ज्यादा जिले डार्क जोन में चले गए हैं और जमीन से तेजी से निकाले जा रहे पानी के चलते हर साल जमीन के पानी का स्तर तकरीबन 0.3 मीटर की दर से घट रहा है। इसके अलावा हिंदुस्तान में तकरीबन 77 सौ किलोमीटर लंबा समुद्री तट और तकरीबन 20 लाख वर्ग

किलोमीटर का अपना आर्थिक क्षेत्र है, जो मत्स्य उत्पात ही नहीं, बल्कि बहुमूल्य तेलों, गैसों और खनिज पदार्थों के साथ-साथ बिजली उत्पादन के लिए काफी उपयोगी होने के बावजूद सरकार का ध्यान इस ओर जाता दिखाई नहीं देता।

कृषि मामलों के जानकार और भारतीय किसान संघ के पूर्व अध्यक्ष नरेश सिरोही कहते हैं कि पूरी दुनिया में करीब 15 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं और कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से 127 जलवायु क्षेत्र हैं, जो सभी के सभी भारत में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में कुल 6 ही ऋतुएं होती हैं और हिंदुस्तान में सभी 6 ऋतुएं होती हैं, जो कुछेक देशों में ही होती हैं। जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो 48 हजार किस्म के पेड़-पौधे हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, जिनमें 15 सौ खाद्य पौधे हैं और घरेलू एवं वन्य प्राणियों की 811 नस्लें पाई जाती हैं, जो कुल विश्व जैव संपदा का 11 एवं 10 फीसदी है। हिंदुस्तान फलों में भी इतना संपन्न है कि हर मौसम के दर्जनों तरीके के फल यहां मिलते हैं, लेकिन हम ड्रैगन और कीवी के पीछे पड़े हैं और उन्हें इतना महंगा खरीद लेते हैं, जिससे हमें उनसे 20 गुना ज्यादा पोषण उतने ही पैसे में हिंदुस्तानी फलों में मिल सकता है। आपको हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में फलों की तकरीबन 3 सौ 75 किस्में, सब्जियों की तकरीबन 2 सौ 80 किस्में, कंदमूलों की तकरीबन 80 किस्में, खाए जाने वाले फूलों और बीजों की तकरीबन 60 किस्में और मेवों की तकरीबन 24-25 किस्में पाई जाती हैं। दुनिया में जो कहीं नहीं होता, वो यहां होता है। मसलन, शिलाजीत, केसर और दूसरी कई चीजें भी हिंदुस्तान में ही मिलती हैं। अगर भारत पाकिस्तान नहीं बंटा होता तो सेंदा नमक भी हिंदुस्तान में ही होता था। इसी प्रकार से घरेलू व पालतू पशुओं में गायों की तकरीबन 32 नस्लें, भैंसों की तकरीबन 8 नस्लें, बकरियों की तकरीबन 42 नस्लें, भेड़ों की तकरीबन 20 नस्लें, घोड़ों और ऊंटों की 6-6 नस्लें और इसी प्रकार दूसरे जानवरों की कई कई नस्लें हिंदुस्तान में पाई जाती है, इसलिए हमारा देश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी ज्यादा प्राकृतिक संपदा, वनस्पति और पशु पक्षियों की नस्लें दुनिया के किसी देश के पास नहीं हैं।

बहरहाल, यहां विचार करने लायक बात यह है कि इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद कृषि और किसानों की उतनी तरक्की क्यों नहीं हुई? जितनी आज हो सकती थी? ग्रामीण इलाकों में विकास की दर बहुत धीमी और पिछड़ी क्यों है? ग्रामीण विकास की दर में तेज गति की संभावनाओं को अब तक देश और राज्य की सरकारें क्यों साकार नहीं कर सकी हैं? किसान इतने भरपूर संसाधनों का सही और ज्यादा से ज्यादा उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? किसानों और गांवों में बसे बाकी लोगों की जिंदगी बेहतर क्यों नहीं हो पा रही है? देश के निर्माण और अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने में उनका रोल क्यों नहीं उभर पा रहा है? ऐसे दर्जनों ज्वलंत सवाल आज सरकारों के ही नहीं, बल्कि हमारे सामने भी सीना तानें खड़े हैं, जिनका समाधान खोजना ही होगा। क्योंकि समस्या के सभी पक्षों और पहलुओं को समझने और उनमें से बेहतर रास्ता निकालने के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृषि और ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है?

दरअसल, आज तक इन जरूरी मुद्दों पर उतना ध्यान ही नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। कृषि क्षेत्र की उपेक्षा का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि औद्योगिकीकरण, वित्तीय कराधान, व्यापार, आयात-निर्यात, यातायात, खनिज, मनोरंजन, पर्यटन आदि छोटे-बड़े सभी क्षेत्रों पर राष्ट्रीय नीतियां बनाई गईं, लेकिन कृषि के लिए एक भी ऐसी समग्र, समेकित राष्ट्रीय कृषि नीति तैयार नहीं की गई जिससे कृषि, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ देश का विकास भी तेजी से होता। कहने को कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए बात करने को कई-कई बार बैठकें हुईं समितियां बनीं, उनकी रिपोर्टें भी आईं लेकिन बावजूद इसके आज तक इधर किसी भी सरकार ने उतना ध्यान ही नहीं दिया, जितना दिया जाना चाहिए था। आज एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार कृषि को पूंजीपतियों के मुनाफे का सौदा बनाने पर तुली है और दूसरी ओर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तक नहीं देना चाहती। जो थोड़ा-बहुत हरित क्रांति के अलावा कृषि नीति-2000 एवं 2007 के तहत काम हुआ भी है, तो उसके अपेक्षित परिणाम सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए सरकारों को चाहिए कि वो कृषि और किसानों की तरक्की के लिए इन प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों के दीर्घकालीन टिकाऊ समुचित उपयोग के कार्यक्रमों के साथ-साथ उन्हें इनका सही उपयोग करने में मदद करे, जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कृषि और किसानों का योगदान बढ़ सके, जो हमेशा से देश के अवाम के लिए दिन-रात अन्न उगाने में लगे रहते हैं उन्हें देश की आर्थिक प्रगति में न्यायोचित हिस्सा भी मिलना चाहिए जिसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं पर सही तरीके से काम करना होगा।

(लेखक दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं)

युवा हाथों का उद्यमशीलता बने हथियार

डॉ दर्शनी प्रिय
वरिष्ठ स्तंभकार

देश के पहले कौशल विकास विश्वविद्यालय की आधारशिला ने प्रायोगिक ज्ञान के मंदिरों की उपादेयता और प्रासंगिकता को बढ़ा दिया है। इसे व्यावसायिक शिक्षा के समग्र समावेशन और उद्यमशीलता के दूरगामी प्रभावों के आलोक में देखा जाना चाहिए। विमर्श के नए केंद्र अब युवा और उससे जुड़े अनन्य उद्यम है। निश्चित ही देश की राजधानी दिल्ली अन्य राज्यों के लिए नजीर बनी है। जहां दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी (डीएसयूई) में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सभी 6,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर यमुना प्राधिकरण भी बड़ी लागत के साथ विश्वस्तरीय सुविधाओं वाले कौशल विश्विद्यालय की घोषणा कर दी है। झारखंड और हरियाणा जैसे छोटे राज्य भी बड़े आर्थिक निवेशों के साथ कौशल विश्व विद्यालयों की स्थापना की दौड़ में आगे निकल आए है।

उद्यमिता और लघु व्यवसाय किसी भी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। आज के परिवेश में वर्तमान और उभरते रोजगार के बाजार की जरूरतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कुशल कार्य बल का विकास करना हमारी प्राथमिकता है और अनिवार्यता भी। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षण देकर मानसिक तौर पर मजबूत किया जाना और उन्हें उद्यमी बनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण देना जरूरी है। अर्थशास्त्रीय अनुभव बताता है कि उद्योग से ही उद्योग का सृजन किया जा सकता है। जाहिर है कौशल विकास के जरिए रोजगार सृजन बहुत सहज और सरल हो जाता है। इसके जरिए आर्थिक और सामाजिक विकास की गतिशीलता को भी बनाए रखा जा सकता है। युवाओं को नई नई तकनीक से अवगत करा कर और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित

दूसरा मत

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

पढ़ें और पढ़ाएं दूसरा मत

एक शुभचिंतक, दिल्ली

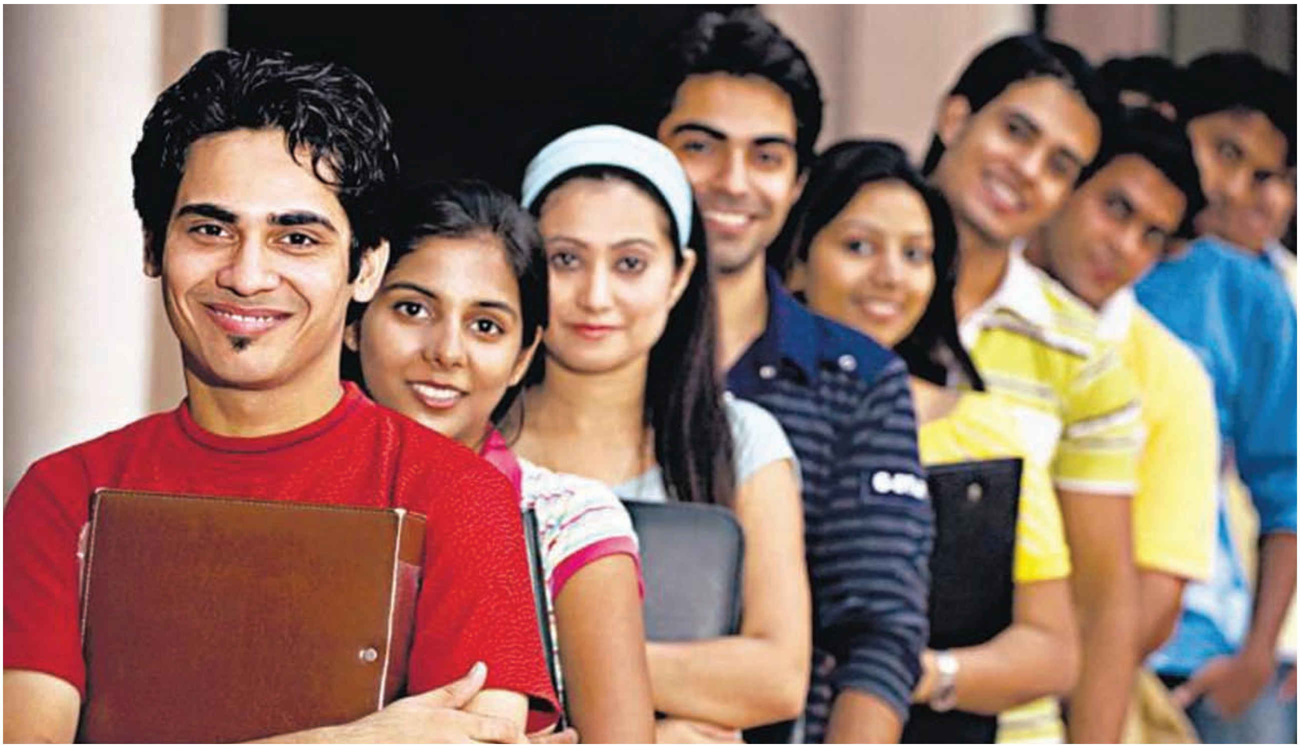

करके उनकी कार्य क्षमता में विस्तार कर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

लेकिन इन सबके बीच ये आवश्यक होगा कि स्किल डेवलपमेंट के जिन विषयों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाये, उनसे संबंधित औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों और ट्रेड से जुड़ी आवश्यकताओं का ध्यान भी रखा जाए ताकि शिक्षित-प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से तत्काल जोड़ा जा सके।

कुछ नए पाठ्यक्रमों जैसे ई-कॉमर्स संचालन, डेटा विश्लेषण, डिजिटल डिजाइन एंड मीडिया, फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, ऐसथेटिक्स एंड ब्यूटी जैसे कोर्सों को प्रमुख रूप से शामिल कर युवाओं को उद्यमिता के नए अवसरों से जोड़ा जा सकता है।मौजूदा समय में सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशीलता बनानी होगी।केवल तभी बड़ी युवा शक्ती की रचना धर्मिता का समग्र रूप में युक्ति संगत रूप से इस्तेमाल

किया जा सकेगा।वर्तमान और उभरते रोजगार के बाजार की जरूरतों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कुशल कार्यबल का विकास करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आगामी वर्षों में भारत को दुनिया की कौशल की राजधानी बनाने के प्रयास करने होंगे। युवाओं को इस तरह से कुशल बनाना होगा ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और उनकी उद्यमिता क्षमता में सुधार हो सके ।हमें स्वाबलंबन,स्वरोजगार और स्वजीवी के मूल तत्व को लेकर आगे बढ़ना होगा। आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए यह समाधान का एक बड़ा माध्यम बन सकती है। मौजूदा वैश्वीकरण के युग में उद्यमशीलता के बिना अंतरराष्ट्रीय शक्ति नहीं बना जा सकता है। स्वच्छ, स्वस्थ,समृद्ध और सशक्त, नए भारत के निर्माण में उद्यमशीलता और स्वरोजगार ही काम आएगा।

कई राज्य की सरकारें छात्रों-युवाओं को कौशल और तकनीक आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए न केवल निजी क्षेत्रों और संस्थानों का सहयोग ले रही है अपितु पॉलीटेक्निक जैसे संस्थानों को स्किल यूनिवर्सिटी से जोड़ रही है ताकि और सुगमता और सहूलियत से छात्रों को उद्यमिता के जरिये बड़ी संख्या में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अन्य तकनीकी यूनिवर्सिटी में चलाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की संरचना, मान्यता, इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य पहलुओं पर गहरा अध्ययन कर उनका अनुकरण किया जाना जरूरी है।

पूरे विश्व को कौशल सीखे हुए लोगों की जरूरत है।ऐसे कौशल और उद्यमी यूनिवर्सिटियां विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशल में पारंगत करने वाली बने।

वर्तमान में कई प्रदेशों में ऐसे स्किल यूनिवर्सिटी की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि वहां के अकुशल मजदूर बड़ी संख्या में रोजी-रोटी की तलाश में प्रदेश से बाहर जाते हैं। वहां वे धान काटने से लेकर निजी गाड़ी चलाने तक कई कार्यों में लगे होते है। तकनीकी जानकारी न होने के कारण उन्हें उनकी मेहनत का उचित भुगतान नहीं मिलता। अगर वे प्रशिक्षित हो जाएंगे तो उन्हें इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें अपने प्रदेश में ही काम मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य प्रदेशों के लोग भी यहां प्रशिक्षण लेने पहुंचेंगे। इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग करने अन्य प्रदेशों में जाते हैं। अगर उस तरह की सुविधा उन्हें अपने ही प्रदेश में मिल जाए तो बच्चों को सहूलियत होगी।

उद्यम और कौशल आने वाले कल का सुनहरा इतिहास है। भविष्य की तैयारी वर्तमान में हो इसके लिए त्वरित तैयारी जरूरी है।भविष्य के दरवाजे तेजी से खुले इसके प्रयास अभी करने होंगे।देश की एक बड़ी बेरोजगार आबादी को उद्यमिता के बूते आसानी से साधा जा सकता है। देश का युवा प्रशिक्षित और रचनाशील होगा तभी राष्ट्र निर्माण में श्रम का आहूत दे सकेगा। और एक मजबूत इकाई के रूप में देश की संचित पूंजी बन सकेगा। ●

50 साल बाद वाली परिसीमन को लेकर चिंता

डॉ सत्यवान सौरभ
वरिष्ठ स्तंभकार

उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। राज्यसभा के समान एक मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुकसान पहुंचाए बिना एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है।

2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्त्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए। एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए, हमें दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल, भारित मतदान या राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने जैसी नवीन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए।

राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मजबूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे निर्वाचन क्षेत्रों का आकार छोटा होगा और शासन में सुधार होगा। संसदीय सीटों को 543 से बढ़ाकर 800 से अधिक करने से संसद सदस्य मतदाताओं की जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से सम्बोधित कर सकेंगे। निश्चित सीट आवंटन के कारण उत्तरी राज्यों को कम प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ा है और परिसीमन इन ऐतिहासिक असंतुलनों को सुधारने का एक मौका प्रदान करता है।

बिहार का प्रतिनिधित्व अभी भी 1971 के आंकड़ों पर आधारित है, बावजूद इसके कि इसकी जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है। नवीनतम जनगणना आंकड़ों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों को संशोधित करने से लोकतांत्रिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और चुनावी प्रतिनिधित्व में जनसंख्या असमानताओं को रोका जा सकेगा। झारखंड, जिसे 2000 में बिहार से अलग कर दिया गया था, अभी भी पुरानी निर्वाचन संरचना का पालन कर रहा है, जो राजनीतिक स्पष्टता को कम करता है। अधिक आबादी वाले राज्यों से सांसदों की संख्या में वृद्धि विकास सम्बंधी असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि नीतिगत हस्तक्षेप अविकसित क्षेत्रों की ओर लक्षित हों। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए अधिक संख्या में सांसदों से बेहतर बुनियादी ढांचा नियोजन और निवेश का बेहतर आवंटन हो सकता है।

प्रगतिशील राज्यों की घटती भूमिका संघवाद और निष्पक्ष राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचाती है। प्रभावी शासन वाले दक्षिणी राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है, जिससे ठोस नीति प्रबंधन के लिए प्रेरणा कम हो सकती है। केरल की उच्च साक्षरता दर से प्रेरित विकास पर्याप्त

सीट आवंटन में तब्दील नहीं हो सकता है, जिससे अन्य राज्य समान रणनीति अपनाने से हतोत्साहित हो सकते हैं। अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीकृत नीति निर्माण की ओर रुझान को जन्म दे सकता है, जो क्षेत्रीय शासन स्वायत्तता को प्रतिबंधित कर सकता है। कृषि राज्यों के पक्ष में विधायी समायोजन औद्योगिक क्षेत्रों की जरूरतों की उपेक्षा कर सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बाधित हो सकता है। यह राजनीतिक पुनर्संरेखण वित्त आयोग के करों के आवंटन को प्रभावित कर सकता है, जो संभावित रूप से बड़ी आबादी वाले राज्यों के पक्ष में हो सकता है।

अपने महत्त्वपूर्ण आर्थिक इनपुट के बावजूद, तमिलनाडु और महाराष्ट्र कम प्रतिनिधित्व के कारण अपने राजकोषीय हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। केवल जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व में वृद्धि उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन को बढ़ा सकती है, जिससे क्षेत्रीय तनाव पैदा हो सकता है। तमिलनाडु में राजनीतिक दल परिसीमन के खिलाफ हैं, उन्हें डर है कि अधिक हिन्दी भाषी आबादी वाले राज्यों को सत्ता का नुकसान होगा, जिससे राजनीतिक परिदृश्य और अधिक विखंडित हो सकता है। निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिक आबादी वाले राज्यों के लिए अधिक सीटें जोड़ते हुए वर्तमान सीट अनुपात को बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है। राज्यसभा जैसा मॉडल प्रगतिशील राज्यों को नुकसान पहुँचाए बिना संतुलित दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। सीटों का पुनर्वितरण करते समय, हमें आर्थिक योगदान, विकास मीट्रिक और शासन प्रभावशीलता को ध्यान में रखना चाहिए।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने वाले राज्यों को विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जो अच्छे शासन को पुरस्कृत करता है। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और तेजी से बढ़ते राज्यों के प्रभुत्व को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाने चाहिए। संसद के भीतर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना से कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों के हितों की वकालत करने में मदद मिल सकती है। 2031 की जनगणना के बाद एक क्रमिक दृष्टिकोण हितधारकों के साथ चर्चा और एक सहज संक्रमण की अनुमति देगा। किसी भी परिसीमन से पहले, एक राष्ट्रीय आयोग को संभावित प्रभावों का आकलन करना चाहिए और आवश्यक सुरक्षा उपाय सुझाने चाहिए। राज्य सरकारों के लिए स्थापित चैनलों के माध्यम से परिसीमन वार्ता में सक्रिय रूप से भाग लेना महत्त्वपूर्ण है। सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी सीट के पुनर्वितरण को अंतिम रूप देने से पहले अंतर-राज्य परिषद के साथ अनिवार्य परामर्श होना चाहिए।

एक सुनियोजित परिसीमन प्रक्रिया जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को संघवाद की अखंडता से जोड़ सकती है। क्षेत्रीय असमानताओं से बचने के लिए, हमें दोहरे प्रतिनिधित्व मॉडल, भारित मतदान या राज्यसभा की शक्तियों को बढ़ाने जैसी नवीन रणनीतियों पर विचार करना चाहिए। राजकोषीय संघवाद और संस्थागत ढांचे को मजबूत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि राजनीतिक निष्पक्षता जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के साथ संरेखित हो, जिससे एक सुसंगत और एकजुट भारत को बढ़ावा मिले। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

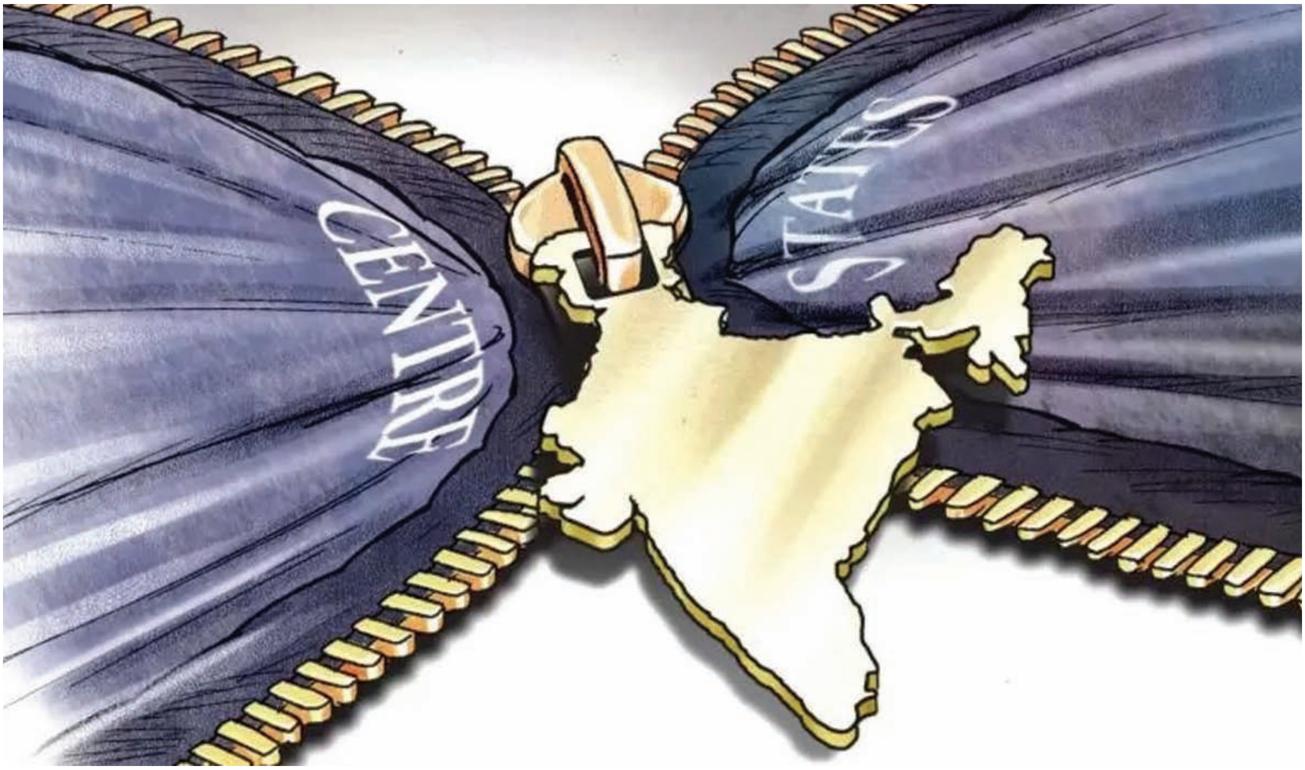

अद्भुत समागम है प्रयागराज

डॉ दिनेश चंद्र सिंह

प्रयागराज मेरी कर्मभूमि है। मैंने इसे हर नजरिए से पढ़ा है और आत्मीयता भाव पूर्वक उसे गढ़ा है। इस शहर की इंद्रधनुषी सांस्कृतिक छंटा आपको भाव विभोर किये बिना नहीं रहेगी। महाकुंभ 2025 के आयोजन से इसकी विश्वव्यापी प्रसिद्धि बढ़ी है। धार्मिक आस्था और पौराणिक महत्व वाले इस शहर के विभिन्न पहलुओं की चर्चा मैं यहां कर रहा हूँ ताकि इसके विभिन्न महत्ता से आप भी अवगत हो सकें।

वैसे तो ज्ञान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समागम की पवित्र भूमि प्रयागराज की महिमा, गरिमा, पूण्य प्रताप और आशीर्वाद के बारे में मैंने विभिन्न लेख में बहुत आत्मीय अनुभूति और गहन अध्ययन के साथ लिखता आया हूं। लिहाजा, यहां पर मैं अपने मन में प्रयागराज विश्वविद्यालय (पूर्व नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय), जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड करार दिया जाता है और ऐसा ही गौरव उसे प्राप्त है, के कुछ अनछुए पहलुओं की चर्चा करूँगा।

मेरा स्पष्ट मत है कि यदि लेखन में अनुभूति, सत्यता और निर्भीक होकर अपने अनुभूति जन्य भावों को प्रकट करने की क्षमता का अभाव है तो ऐसा लेखन निंदनीय और अपठनीय होता है। सच कहूं तो मैंने अपने जीवन में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जनकवि कबीर जी को जिया है, अर्थात निराला जी की योग्यता के साथ आर्थिक विपन्नता का दंश भी झेला और क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी नाम के आगे टाइटिल नहीं लगाने का साइड इफेक्ट्स भी झेला। परंतु जैसे सत्य पराजित नहीं होता है, उसी प्रकार शिक्षा पर आधारित ज्ञान, योग्यता, दक्षता को भी किसी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता है।

काव्यात्मक शब्दों में कहूं तो- संपदा से कहीं अधिक जग में, मान-सम्मान की जरूरत/जरारत है, यार, मेरा ख्याल है तुझको, सिर्फ ईमान की जरुरत है। जिसने बख्शी तुम्हें बुलंदी, तुम, उसको पांवों की धूल मत समझो, खींच लेगा जमीन पर तुमको, दर्द उसका फिजूल मत समझो।

'अतिथि देवो भवः' जिसके साक्षात दर्शन प्रयागराज में एवं आसपास के जनपदों के नागरिकों के द्वारा कराए गए। पड़ोसी जनपद जौनपुर में तैनाती के कारण अतिथियों की व्यवस्था या अन्य प्रशासनिक कार्यों से उनकी सेवा का अवसर मुझे भी मिला, इसके लिए मैं विनम्रता के साथ अपने को अहोभाग्यशाली एवं जनसेवक मानता हूं। ऐसा सौभाग्य मुझे सेवा के रूप में जीवनपर्यंत मिले, यही मनोकामना है। पुनः प्रयागराज वासियों की सहृदयता, सहनशीलता तथा अतिथियों के प्रति आदर-सम्मान की भावना से हृदय से सम्मान और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक दूरदर्शिता, जनमानस तथा भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा का कायल हूं, क्योंकि इन सबका अनूठा संगम आपके व्यक्तित्व में प्रखरता से प्रकाश पुंज की तरह आलोकित हुआ है।

चिरंतन सत्य उक्ति है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। हां, सत्य की जीत में प्रतीक्षा होती है। आज मैं ध्यान दिलाता हूं प्रयागराज की कुछ तहजीब और हेकड़ी जनित व्यवस्था की ओर, जिसके बारे में आपको जानना समझना चाहिए। मसलन, प्रयागराज की तहजीब और ज्ञान के प्रति अनुराग को देखना हो तो कहना न होगा कि तदसमय रिक्शा चालक भी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के समस्त दैनिक पेपर (अखबार) पढ़े बिना किसी भी दाम पर सवारियों को रिक्शा पर नहीं बैठता था। आज क्या स्थिति है, मुझे मालूम एवं अनुभूति नहीं है।

वहीं, हेकड़ी की बात करूँ तो प्रत्येक शिक्षित, अशिक्षित व्यक्ति जिसको अपने बाहुबल पर अपनी सियासत और दबदबा कायम करना होता था, वह बात-बात पर 'अमा बम्ब दागकर चीथड़े उड़ा दूंगा' कहते हुए सुना ही नहीं जाता था अपितु अनेक घटनाओं को कारित होते हुए सुना एवं देखा है। इसलिए बिना किसी का नाम अभिव्यक्त किए यह बताना पर्याप्त है। चूंकि धर्म, आस्था, ज्ञान व प्रेम की नगरी प्रयागराज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने वाले 'ज्ञान के सागर' अपराधी भी कई प्रकार के संरक्षण में खूब नामी-गिरामी बने रहे। वह इस शहर से चमकने वाले लेखक, शिक्षाविद, न्यायाधीश, राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारियों से भी ज्यादा शक्तिशाली और पॉपुलर (प्रसिद्ध) हुए। हालांकि, ऐसे सभी तत्व अब पाताल वासी हो गए हैं।

वहीं, चर्चा जब प्रयागराज की हो तो इलाहाबाद के प्रसिद्ध सुपाच्य यानी पाचन योग्य और प्रोटेम रिच तथा सभी प्रकार से गुणकारी 'इलाहाबादी अमरूद' के गुणों का उल्लेख किये बिना लेख को समाप्त करना उचित नहीं होगा। मेरी अल्प बुद्धि, ज्ञान और अनुभव से मैंने यह अनुभूति की है कि प्रयागराज की ज्ञान की प्रतिभा को आयुर्वेदिक दृष्टि से प्रौढ़ता के साथ अपने पराक्रमी रूप में छात्र-छात्राओं, योग्य सभी क्षेत्र के ज्ञानी मनीषियों के

पाचनतंत्र को शुद्ध और हाजमे को उत्कृष्ट रखने के लिए 'इलाहाबादी अमरूद' की महिमा का वर्णन भी अत्यंत महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है।

यहाँ के गरीब छात्र-छात्राएं या आर्थिक दृष्टि से कहीं भी अभाव वाले, किसी भी क्षेत्र के नागरिकों की जीवन चर्या को एवं व्यक्तित्व को रोगमुक्त करने में ३इलाहाबादी अमरूद३ अत्यंत महत्वपूर्ण, आवश्यक रहा है। कम पैसों में यह वर्णन मेरे समय का है। अभी भी कम रुपए में वहां के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए रामबाण और उपयोगी है और रहेगा। जिसके कारण यह अध्ययन रत छात्र-छात्राओं और माननीय न्यायाधीश, विद्वान अधिवक्ता-ओं, लेखकों, और शिक्षा विद राजनीतिज्ञों, कर्मकारों और सामान्य नागरिकों की जीवन चर्या का अभिन्न, कम मूल्य मिलने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित एवं बिकने वाला फल इलाहाबादी लाल अमरूद सदैव पवित्र तीर्थराज प्रयागराज की पावन भूमि पर आकर्षण का केंद्रबिंदु रहेगा।

इलाहाबादी गुलाबी अमरूद में पर्याप्त मात्रा में मौजूद विटामिन सी इम्यून सिस्टम को दुरूस्त करता है। उत्कृष्ट गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी के फाइबर हमारे पाचनतंत्र के लिए फायदेमंद हैं। फाइबर की वजह से पेट में गैस जैसी समस्याएं नहीं होती हैं और हमारी आंतें साफ रहती हैं। अमरूद में पोटैशियम और मैग्नीशियम के कारण दिल के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। खट्टेपन की वजह से कम कैलोरी मोटापे को रोकता है और शुगर एवं ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। इससे स्वस्थ त्वचा बनती है तथा विटामिन ए आंखों को ठीक रखता है। इसलिए इलाहाबादी अमरूद छात्र-छात्राओं को और प्रयागराज के बुद्धिजीवियों तथा सभी का प्रिय है।उपरोक्त कारणों से भी यहां के छात्र-छात्राएं प्रतियोगिता परीक्षा में बाजी मार लेते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहने के कारण उनकी सफलता का प्रतिशत भी औसत रूप से अधिक रहता है। अतः इलाहाबादी अमरूद भी यहां की शान है और ज्ञान के अलख को प्रकाशित रखने के लिए आवश्यक है।

एक खास बात और, अमरशहीद चंद्रशेखर और अल्फ्रेड पार्क के बिना प्रयागराज की चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि इनकी बदौलत भी प्रयागराज/इलाहाबाद को ख्याति मिली है। उनसे जुड़ा यह पार्क राष्ट्रीयता और निर्भीकता का प्रेरणा स्थल है।

वहीं, पुस्तकें खरीदने, पढ़ने और सुरक्षित रखने का जज्बा देखना हो तो किसी पुरातन छात्र से सुनें, देखें और सीखें। प्रयागराज का छात्र भूख को मारकर भी पुस्तकों को खरीदता था और पढ़ता था। आज भी कुछ क्षरण के साथ वहां अभी मौजूद मुस्लिम शासकों और ईसाईयत की भी दूरदृष्टि रही है कि प्रयागराज की गरिमा के कारण वहां उस काल में भी यहां के अतीतकालीन गौरव की महिमा और गरिमा को बढ़ाने के लिए पौराणिक बट वृक्ष के पास यमुना किनारे किले बनाये गए और अंग्रेजों ने सबसे बड़े शिक्षा केंद्र एवं न्याय की पीठ को प्रयागराज में स्थापित किया।

आज भी यहां कुछ क्षरण के बाद पुस्तकों को पढ़ना, लेखन के प्रति अभिरुचि जीवित है। मुस्लिम शासकों ने भी प्रयागराज के पौराणिक महत्व, ज्ञान, त्याग और व्यापारिक महत्व की उपादेयता को समझा था। इसलिए यहां पवित्र बट वृक्ष के समीप मां यमुना के किनारे युद्ध सामरिक किले का निर्माण कराया। जो आज भी सभी को अपने दर्शन, शिल्प एवं वास्तुकला के लिए आकर्षित करता है। इसी महत्व को अंग्रेजों ने भी समझा। इसलिए ट्रेड की दृष्टि से इसके महत्व को समझकर शिक्षा एवं न्याय के लिए अनेकों विद्यालय जैसे इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज, नैनी कृषि विश्वविद्यालय, उच्च न्यायालय एवं ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी अपनी उपादेयता के लिए सभी को आकर्षित करता है।

आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत का संविधान सर्वोपरि है। इसलिए संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्रीय व्यवस्था का संचालन होगा। यही भारत के लिए अपरिहार्य एवं युगीन विकास का वाहक होगा।

संविधान के प्रति सच्ची आस्था एवं विश्वास ही हमारे भारत वर्ष की विकास यात्रा का मार्च प्रशस्त करेगा। अन्य व्यवस्था अब गौण हो चुकी है। इसलिए जातिगत, धर्मगत, भाषागत आधार पर हम अपने राष्ट्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते हैं। भारत का संविधान ही हमें कार्य के लिए बल प्रदान करता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। परंतु भारतीय संविधान हमारी पीढ़ी/नस्लों को वटवृक्ष की तरह पोषित करती है। और भारत का संविधान भी हमारी भारतीय संस्कृति से ही जीवंतता एवं शक्ति प्राप्त करता है एवं करेगा। इसलिए आवश्यक है हम ज्ञान, परिश्रम, शिक्षा, उद्योग पर, कृषि पर ध्यान देकर विकास की राह को गति प्रदान करें।

महत्वपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्था में कठिनाई उतपन्न हुई, परन्तु पराक्रम, सत्यनिष्ठा पूर्वक साधना एवं परिश्रम से सफलता मिली और योग्यता, असाध्य परिश्रम, अनवरत साधना से स्थापित किये जाने में सफलता भी मिली। इस राह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की पक्तियां प्रेरणा बनीं- 'काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। गीत नया गाता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा।' यह सबकुछ इसलिए हुआ, क्योंकि प्रयागराज में मिलता है ज्ञान, कर्म और आस्था की महात्रिवेणी मां गंगा, यमुना, सरस्वती की अविरल, अनंत कोटि काल अविचल, अविरल, चिरंतन आगामी काल तक अपने पूण्य प्रताप से मानवता के कल्याण के लिए अपने अस्तित्व के साथ बहने वाली मां, जिनको नदियां कहना तीनों माताओं का अनादर होगा। यह तो साक्षात परम पूण्य मानवता के प्रति अविरल बहने वाली उन सबकी माताएं हैं।

अंत में अपने मनोभाव और अभिव्यक्ति को कबीरदास जी की निम्नवत साखियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगा-

सभी अध्ययन करते हैं, अपनी-अपनी योग्यता, माता-पिता के आशीर्वाद और गुरुजनों के आशीर्वाद तथा पुण्य प्रारब्ध से विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठा पूर्ण पदों पर पहुंचते या कुछ लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं। एवं किताबी ज्ञान की अपेक्षा पांडित्य पूर्ण ज्ञान, प्रेम की भाषा को भी पढ़ना, समझना और उसको जीवन में अनुपालन करना आवश्यक है, तभी विजयी मानवता होगी।

'पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोई; ढाई आखर प्रेम का, पढ़ि से पंडित होय।' ●

(ये लेखक के अपने विचार हैं। लेखक आईएएस हैं)

गांधी, भगत, अम्बेडकर में समन्वय

अंबुज कुमार

प्राचीन काल में शैव और वैष्णव संप्रदाय के बीच संघर्ष और मतभेद चलते थे। दोनों की सोच और मान्यताएं अलग अलग थी। इसके अलावा धार्मिक भक्ति आंदोलन के दौरान भी बहुत से संप्रदाय बने हुए थे। जब इस्लामिक आक्रमण हुआ और सूफियों का प्रभाव समाज पर पड़ने लगा तब इन संप्रदायों में एकता की चर्चा होने लगी। रामचन्द्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को इस्लामिक प्रतिक्रिया माना है जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बताया है। बहरहाल गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के माध्यम से समन्वय बनाकर एकता स्थापित करने की बात की है। ये अलग बात है कि जातीय श्रेष्ठता के भाव से वे भी बाहर नहीं निकल पाए लेकिन शैव और वैष्णव संप्रदाय को एक कर व्यापक स्वरूप देने का काम किया। ये अलग बात है कि समाज जातीय भेदभाव के साथ चलता रहा और विदेशियों के आने तक अस्मिता बोध के कई केंद्र बने रहे। श्रेष्ठि लोग और सत्ताधारी लोग अपने लोगों पर अत्याचार कर पुरुषार्थ साबित करते रहे और विदेशी हुकूमत स्थापित होती रही।

वर्तमान समय में गांधी, अम्बेडकर और भगत सिंह, ये तीन विचारधारा समाज में प्रबल तरीके से विद्यमान हैं। तीनों की मंजिल एक ही है। गांधीवादी विचारधारा शांति और अहिंसा के रास्ते समाज को लोकतांत्रिक,गणराज्य बनाए रखने पर जोर देती है। संघर्ष के लिए सत्याग्रह इसके प्रमुख हथियार हैं। अम्बेडकर विचारधारा धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था को चुनौती देते हुए समानता और भाईचारे पर जोर देते हुए कल्याणकारी लोकतांत्रिक समाज पर जोर देती है। भगत सिंह क्रांतिकारी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें मजदूरों, किसानों की भी समान भागीदारी हो। वे भी क्रांति के लिए बम,बंदूक को आवश्यक नहीं मानते हैं। इनका कहना था कि क्रांति विचारधारा की सान पर तेज होती है।

अमूमन हम देखें तो भारत जैसे विविधता सम्पन्न देश में हथियारबंद क्रांति प्रासंगिक नहीं है। इसे किसी भी कीमत पर आम जनता का समर्थन हासिल नहीं होता है। यही कारण है कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का अभियान जन जन तक फैल गया लेकिन भगत सिंह का अभियान जन जन तक नहीं फैला। आज भी लोग शांति पूर्ण संघर्ष में ज्यादा भाग लेते हैं। हथियारयुक्त क्रांति में राजसत्ता की असीम ताकत और दमन के आगे टिकना मुश्किल होता है। वामपंथी लेखक सुधीर सिंह की किताब 'बिहार में भगत सिंह' उस दौर के क्रांतिकारियों की अनेक चुनौतियों को इंगित करती हैं। ये लोग सामाजिक,आर्थिक, राजनीतिक,मुखबिरी की समस्याओं से गुजरते हुए राजसत्ता और आम जनता के भी नजरों पर चढ़े रहते थे। रात या दिन, भूमिगत रहकर ही मिशन की कामयाबी में लगे रहते थे। आज के दौर में इस तरह की क्रांति की परिकल्पना हम नहीं कर सकते।।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी इनके बीच मतभेदों के बावजूद समन्वय का उदाहरण मिलता है। इस किताब से मालूम होता है कि क्रांति की गतिविधियों के दौरान भी साथी कांग्रेस से जुड़े होते थे, अधिवेशनों में भाग लेते थे और किसी से मिलने के लिए भी कांग्रेस के दफ्तर का इस्तेमाल करते थे। गांधी जी का अछूतोद्धार कार्यक्रम भी अम्बेडकर से जुड़ा हुआ था। वे मुस्लिमों और सिखों के पृथक निर्वाचन के भी विरोधी थे। यही कारण है कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों को पृथक निर्वाचन दिया जाने लगा तो उन्होंने विरोध किया। वे पृथक निर्वाचन को राष्ट्र का विभाजन मानते थे। 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम में मुस्लिमों

यात्रा कर चुकी है।

उक्त तीनों विचारधारा संघ की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। वे इसे विभाजनकारी और लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल नहीं मानती हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाजवाद, धर्म निरपेक्षता पर खतरे के रूप में देखती है। व्यक्तिगत पूंजी संकेद्रण को राष्ट्र पर खतरे के रूप में आगाह कर रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से भगत सिंह और डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने की घटना को प्रेक्षक इसी नजरिए से विश्लेषित कर रहे हैं।

गांधी, भगत सिंह, अम्बेडकर की तीनों विचारधारा को विश्लेषण करने और उनके कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मैंने महसूस किया कि तीनों में भिन्नता के बावजूद एक

के पृथक निर्वाचन के कारण ही पाकिस्तान राष्ट्रवाद की बीज पड़ी थी। गांधी जी ने पृथक निर्वाचन की जगह विधायिका में सीट आरक्षित करने का समर्थन किया था जो संविधान में दर्ज है और आज भी जारी है।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही गोलवलकर और हेडगेवार की हिंदुत्ववादी विचारधारा भी परवान चढ़ने लगी थी। आज हिंदुत्व की विचारधारा सबसे तीव्र गति से बढ़ी है। यह सब पर भारी है। हिंदू महासभा, आरएसएस जनसंघ से होते हुए यह बीजेपी के रूप में राजसत्ता तक की

समानता है। इस समानता को ताकत बनाकर आपसी समन्वय बनाया जा सकता है। ऐसा करने से एक सामान्य विचारधारा का जन्म होगा, जो सर्वमान्य भी होगा और भारत के मन मिजाज के अनुकूल भी होगा। इससे सैकड़ों साल के आजादी, समानता,भाईचारे, समाजवाद,लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता के संघर्ष को सफलीभूत किया जा सकता है। ●

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

फार्मा उद्योग: यूएसएफडीए के निरीक्षण में सुधार

अंजलि सिंह

भारतीय फार्मास्यूटिकल्स उद्योग ने बीते एक दशक में अमेरिकी औषधि नियामक (यूएसएफ डीए) के विनियमनों के अनुपालन में सुधार किया है। आधिकारिक कार्रवाई जरूरी (ओएआई) के मामले साल 2014 के 23 फीसदी से 2024 में कम होकर 11 फीसदी हो गई है, जो मौजूदा वैश्विक औसत 14 फीसदी से कम है। ओएआई के जरिये विनियामक उल्लंघनों की पहचान होती है।

इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस (आईपीए) ने खुलासा किया है कि दुनिया भर में यूएसएफडीए के निरीक्षण की संख्या में गिरावट आई है और यह साल 2014 के सालाना 1,849 से कम होकर साल 2024 में करीब 940 हो गई है। हालांकि, भारत में होने वाले निरीक्षण की संख्या में इजाफा हुआ है। साल 2014 में दुनिया भर में ओएआई दर्जे की हिस्सेदारी 6 फीसदी थी, जो अब दोगुना से अधिक होकर 14 फीसदी हो गई है।साल 2014 में वैश्विक निरीक्षणों का सिर्फ 6 फीसदी ही भारत में हुआ था। अब यह आंकड़ा तीन गुना बढ़कर 18 फीसदी हो गया है, जो वैश्विक दवा आपूर्ति श्रृंखला में भारत की बढ़ती भूमिका को दशार्ता है।

अमेरिकी औषधि नियामक कोई कार्रवाई नहीं जरूरी (एनएआई), स्वैच्छिक कार्रवाई जरूरी (वीएआई) और आधिकारिक कार्रवाई जरूरी (ओएआई) जैसे अपने निरीक्षण के निष्कर्ष तीन हिस्सों में बांटता है। एनएआई से

पता चलता है कि संयंत्र में सभी नियमों का अनुपालन किया जा रहा है और कोई बड़ी खामी नहीं मिली है। वीएआई से पता चलता है कि निरीक्षण के दौरान कुछ मसले मिले थे मगर वे इतने गंभीर नहीं है कि नियामकीय कार्रवाई की जरूरत पड़े। सबसे महत्त्वपूर्ण ओएआई श्रेणी है, जिसका मतलब होता है कि गंभीर अनुपालन मुद्दों की जानकारी मिली है, जिस कारण चेतावनी पत्र, आयात अलर्ट और उत्पाद वापस मंगाने जैसे नियामक प्रवर्तन हो सकते हैं।

सुधारों के बावजूद आईपीए ने जोर देकर कहा है कि गुणवत्ता उत्कृष्टता अब भी बरकरार है। नियामकीय जांच भी लगातार विकसित हो रही है। इससे ध्यान बुनियादी उत्पाद विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के अनुपालन से हटकर संदूषण नियंत्रण, संयंत्रों के रखरखाव और विनिर्माण विसंगतियों के मूल कारण जैसी छोटी-छोटी बातों पर केंद्रित किया गया है इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के महासचिव सुदर्शन जैन ने कहा, 'पिछले एक दशक में भारत ने वैश्विक फार्मास्युटिकल्स निरीक्षण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नियामक उल्लंघन के मामलों की संख्या में कमी की है। मगर गुणवत्ता उत्कृष्टता का स्तर लगातार बढ़ रहा है और कंपनियों को भी उभरती अनुपालन चुनौतियों से निपटने में सक्षम होना चाहिए।' ●

(व्यक्त विचार लेखिका के अपने हैं)

कामकाज में तेजी आई या नहीं?

ए के भट्टाचार्य

जून 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार निर्माण पर एक साहसी घोषणा की थी। उसने अगले 18 महीनों में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही थी। घोषणा के मुताबिक ये भर्तियां 'मिशन' की तरह की जानी थीं।

घोषणा के राजनीतिक और आर्थिक मायने थे। राजनीतिक इसलिए यह 2024 में होने वाले आम चुनावों से महज दो साल पहले की गई थी, जब राजनीतिक दलों और आम लोगों के बीच नौकरी अहम मुद्दा बन गई थी। आर्थिक इसलिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था श्रम बाजार में तेजी से जुड़ते लोगों के लिए वेतन वाली और अधिक नौकरियां तैयार करने की चुनौती से जूझ रही थी। केंद्र सरकार सबसे अधिक रोजगार देने वालों में है और वह इस राजनीतिक तथा आर्थिक जरूरत को पूरा करना चाहती थी।

केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में बनी रिक्तियों ने इस वादे को पूरा करने का काम तेज किया। फरवरी-मार्च 2022 में तत्कालीन कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में मार्च 2020 तक करीब 8.70 लाख पद खाली थे। सबसे ज्यादा 2.47 लाख असैन्य पद रक्षा मंत्रालय में खाली थे।

उसके बाद रेलवे में 2.37 लाख, गृह मंत्रालय में 1.28 लाख (ज्यादातर केंद्रीय पुलिस बलों में), डाक विभाग में 90,000 और अंकेक्षण विभाग में 28,000 रिक्तियां थीं। कुल रिक्तियों की 84 फीसदी तो इन्हीं में थीं। उस समय केंद्र सरकार में कुल 40 लाख कर्मचारी तय किए गए थे।

फरवरी के आरंभ में प्रस्तुत 2025-26 के केंद्रीय बजट से पता चलता है कि केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के अलावा अपने सभी विभागों और मंत्रालयों में किस तरह भर्तियां कीं। हकीकत में आंकड़े दिखा रहे हैं कि रेलवे सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है। मगर बढ़ोतरी उतनी नहीं है, जितनी का वादा जून 2022 में किया गया था।

केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों की संख्या मार्च 2022 के अंत में 31.7 लाख थी। इसमें सशस्त्र बल के कर्मचारी शामिल नहीं हैं। दो साल बाद यानी मार्च 2024 के अंत में आंकड़ा बढ़कर 33 लाख हो गया। इस तरह दो साल में 1.37 लाख यानी केवल 4 फीसदी कर्मचारी बढ़े। अनुमान है कि मार्च 2025 तक संख्या बढ़कर 36.6 लाख हो जाएगी।

ध्यान रहे कि मार्च 2025 के आंकड़े कर्मचारियों की वास्तविक संख्या नहीं बताते। परंतु अगर इस संशोधित आंकड़े को भी सही मान लें तो अप्रैल 2022 से अब तक कर्मचारियों की संख्या में करीब 4.89 लाख अथवा 15 फीसदी का इजाफा हुआ। इस बात के लिए सरकार की आलोचना की जा सकती है कि 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों का वादा किया गया मगर तीन साल बाद उसकी आधी नौकरियां भी नहीं दी गई हैं। सरकार यह कहकर खुद को सही साबित करेगी कि आधे लक्ष्य ने भी रोजगार की चिंता को कुछ हद तक दूर किया है।

ज्यादा सरकारी नौकरियों के सृजन के अच्छे या खराब पहलू पर बात करने के बजाय इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि 1991 से 2022 तक सभी सरकारों के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों का आंकड़ा कम ही हुआ है। केंद्र सरकार के कुल असैन्य कर्मचारियों की बात करें तो मार्च 1991 में करीब 40 लाख कर्मचारी थे। मार्च 2014 तक इनकी संख्या कम होकर 33.2 लाख रह गई।

मोदी सरकार भी मार्च 2022 तक इनकी तादाद कम करके 31.7 लाख पर ले आई। सार्वजनिक नीति संबंधी अधिकतर बहसों में जिस बात की अनेदखी कर दी जाती है वह यह है कि हाल के सालों में सरकार ज्यादा विरोध या आंदोलन का सामना किए बगैर कर्मचारियों की संख्या घटाने में कामयाब रही है।

यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि रिक्तियों को जानबूझकर नहीं भरा गया और कई नौकरियां खत्म कर दी गईं। उन्हीं नौकरियों को ठेके पर या अस्थायी कर्मचारियों के जरिये कराया गया। मगर कर्मचारियों की तादाद तीन दशक में 21 फीसदी घटा दी गई और कोई उथल-पुथल भी नहीं हुई!

ध्यान रहे कि इन सरकारों में से किसी ने भी इन कर्मचारियों की मंजूर संख्या नहीं घटाई और वह अब भी 40 लाख ही है। यह भी सच है कि मोदी सरकार ने पिछले तीन साल में कर्मचारियों की संख्या 15 फीसदी बढ़ाई है मगर आंकड़ा 36.5 लाख तक ही पहुंच पाया है, जो 40 लाख से काफी कम है।

परंतु बीते तीन सालों में यह इजाफा कैसे हुआ? यहां याद रहना चाहिए कि कुल कर्मचारियों में से 86 फीसदी तो रेलवे, डाक, केंद्रीय पुलिस बल और कर विभाग से ही हैं। मोदी सरकार के पहले सात सालों में भारतीय रेल के कर्मचारियों की तादाद में लगातार कमी आई और मार्च 2015 में 13.2 लाख से कम होकर ये मार्च 2022 में 12.1 लाख ही रह गए।

बीते तीन सालों में असैन्य कर्मियों की कुल संख्या में 4.89 लाख का इजाफा हुआ है मगर भारतीय रेल के कर्मचारियों में केवल 3,000 की बढ़ोतरी हुई। बीते तीन सालों में डाक विभाग में सबसे अधिक 1.79 लाख और पुलिस में 1.43 लाख कर्मचारी बढ़े। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर विभागों में करीब 71,000 कर्मचारियों का इजाफा हुआ और उनके कुल कर्मचारी 1.72 लाख तक पहुंच गए। केंद्र सरकार द्वारा की जा रही नियुक्ति कई सवाल पैदा करती है।

केंद्रीय पुलिस बलों की संख्या में तेज वृद्धि बताती है कि केंद्र सरकार कानून प्रवर्तन में दखल बढ़ा रही है। इस क्षेत्र में राज्यों को अधिक नियुक्तियां करनी चाहिए ताकि पुलिस और आबादी का अनुपात बढ़ जाए। डाक विभाग के कर्मचारियों की संख्या में इजाफे से सवाल खड़ा होता है कि जब लोग डाक संचार से दूरी बनाकर डिजिटल तरीके अपना रहे हैं तो डाक विभाग को दूसरे कामों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं।

आप इस बात पर भी ताज्जुब कर सकते हैं कि जब कर रिटर्न डिजिटल तरीके से दाखिल किए जा रहे हैं और ऑनलाइन जांच तथा कर निर्धारण का चलन बढ़ता जा रहा है तो कर विभाग के कर्मचारियों की संख्या आखिर क्यों बढ़ रही है। मगर हकीकत यही है कि कर विभाग में बहुत अधिक भर्तियां की गई हैं।

सवाल यह नहीं है कि सरकार को अधिक कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए अथवा नहीं। सच तो यही है कि केंद्र सरकार के असैन्य कर्मचारियों पर सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1 फीसदी खर्च करती है, जो ज्यादा नहीं है। कई विकासित और विकासशील देशों की तुलना में यह आंकड़ा काफी कम है।

रेल कर्मचारियों को हटा दें तो कर्मचारियों पर केंद्र का कुल खर्च और भी कम हो जाता है। ज्यादा कायदे का सवाल यह है कि भर्तियों में इजाफा उत्पादकता तथा क्षमता, दक्षता बढ़ाने के इरादे से किया जा रहा है या नहीं। साथ ही इससे सरकार का दखल कम हो रहा है या नहीं। अधिक कर्मचारियों का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि गतिरोध बढ़ें और प्रभाव कम हो।

(व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं)

प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरौनी डेयरी के नव निर्मित दूध उत्पाद संयंत्र का किया उद्घाटन

देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, बरौनी डेयरी में नव निर्मित दूध उत्पाद संयंत्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मान समारोह के बीच किया। बरौनी डेयरी के प्रबंध निदेशक रविन्द्र प्रसाद ने बताया गया कि 133 करोड़ रूपए के निवेश से इस नवोन्मेषी एवं अत्याधुनिक तकनीक आधारित इस उत्पादन संयंत्र का निर्माण एवं प्रतिस्थापन संध ने संस्थागत स्रेत, भारत सरकार के, डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डी.आई.डी.एफ.), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एन.पी.डी.डी.) योजनान्तर्गत वित्तीय सहयोग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) के तकनीकि सहयोग एवं पर्यवेक्षण में आ-ई०डी०एम०सी०लि०, आनंद से किया गया है। इसकी क्षमता 2.07 लाख लीटर प्रति दिन है।

प्रबंध निदेशक के मुताबिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के दुग्ध जन्य उत्पादों के उत्पादन की सुविधाओं से लैश इस नए उत्पादन संयंत्र में सम्मानित उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप उत्पाद सुलभकराने की पर्याप्त क्षमता है। इसमें विशिष्ट रूप से 10 टन दैनिक उत्पादन क्षमता का स्वचालित पनीर उत्पादन संयंत्र, 20 टन दैनिक उत्पादन क्षमता का स्वचालित दही उत्पादन संयंत्र सहित उच्च दैनिक उत्पादन क्षमता के स्वचालित गुलाब जामुन उत्पादन संयंत्र, खोवा, पेड़ा, मिस्टी दही, लस्सी, स्पेशल, चमचम, रसकदम आदि उत्पाद शामिल हैं। ऊर्जा, जल एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं उच्च सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस अत्याधुनिक संयंत्र में 364 किलोवाट क्षमता का सोलर आधारित ग्रिड कनेक्टेड पावर प्लांट भी प्रतिस्थापित किया गया है। इससे ग्रीन इनर्जी को बढ़ावा देने के साथ-साथ ऊर्जा खर्च में कटौती सुनिश्चित होगी।

प्रबंध निदेशक रविन्द्र प्रसाद के अनुसार पुराने संयंत्र में सीमित स्थान / सुविधाओं के कारण हम सम्मानित उपभोक्ताओं की, खासकर लगन / त्योहारी मांग, को पूरा नहीं कर पाते थे किन्तु नये संयंत्र के निर्माण एवं प्रतिस्थापन से संघ न सिर्फ अपने सम्मानित उपभोक्ताओं को उनकी मांग के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के उत्पाद सुलभ कराने में समर्थ हुआ है बल्कि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के नये उत्पादों का शुभारंभ करने की दिशा में भी अग्रसर है।

इसमें तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं कि पूर्वोत्तर भारत में दुग्ध जन्य उत्पादों के उत्पादन को समर्पित यह अद्वितीय इकाई आने वाले समय में न सिर्फ संघ बल्कि पूरे बिहार के डेयरी उद्योग के उत्तरोत्तर विकास को त्वरा प्रदान करेगी।

इस समारोह में जिले के विभिन्न विधान सभाओं के माननीय विधायकगण / विधान परिषद सदस्यगण, दुग्ध संघ बरौनी के अध्यक्ष विजय शंकर सिंह निदेशक मंडल के सभी सदस्य, बिहार सरकार / कॉम्फेड के वरीय पदाधिका-रीगण, विभिन्न दुग्ध संघों / ईकाइयों के प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक, एन.डी.डी०बी., आई.डी.एम.सी.लि. के पदाधिकारीगण, कई गणमान्य अतिथी, सम्मानित, पशुपालक, डेयरी के पदाधिकारी / कर्मचारी/ श्रमिक बंधु आदि शामिल रहे ।

प्रबंध निदेशक ने इस अद्वितीय संयंत्र के निर्माण एवं प्रतिस्थापन में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से मिले, सहयोग के लिए दुग्ध संघ बरौनी की ओर से सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

यूरिया खाद की कालाबाजारी नहीं रुकी तो घेराव

बिहार राज्य किसान सभा के आठवां बेगूसराय जिला सम्मेलन के लिए चुने गए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारी जो उपलब्धियां है, उसको हमें किसानों के बीच में ले जाना होगा।

आज यूरिया खाद के लिए चारों ओर हाहाकार मची हुई है। यूरिया खाद के अभाव में किसानों का गेहूं का फसल बर्बाद हो रही है। यूरिया खाद का कारखाना हर्ल कंपनी का धुआं और जहर हम पीते हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरा वाली कहावत यहां चल रहा है। हमारे घर में ही हर्ल कंपनी है। और उसका खाद बेगूसराय को ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर जिला प्रशासन अविलंब ठोस पहल नहीं करेगी, तो हर्ल कंपनी का खाद यहां से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर कार्यकारी जिला सचिव दिनेश सिंह, अंचल सचिव भोला सिंह, प्रभारी चंद्र भूषण सिंह, पूर्व प्रमुख रामसागारथ सहनी आदि ने भी अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सनातन सिंह ने की।

कुमार रामचंद्र महतो, नरसिंह साह, अमित कुमार शाह, हीरा झा, नितेश झा, राहुल देवा, धर्मराज सहनी, आनन्द प्रेम सहित सैकड़ो लोग मौजूद थे।

पैगाम ए अमन कमेटी की टीम कस्बा पहुंची

बलिया प्रखंड के कस्बा गांव की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर क्षेत्र के लोग काफी आक्रोशित हैं। बलिया थाना अध्यक्ष ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिए काफी समझदारी से पहल कर रही है। आक्रोशित लोगों को समझाने के लिए पैगाम ए अमन कमेटी की ओर से एक जत्था कस्बा पहुंचा। इसमें कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद

अहसन, संरक्षक एवं ईश्वर अस्पताल के निदेशक डॉ. संजय कुमार, पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल, डॉ. राहुल कुमार, शाहपुर मुखिया महेश राय, सामाजिक कार्यकर्ता मदन कुमार, मुखिया मो. राशिद, जदयू नेत्री अस्मत खातून, डॉ.आमोद कुमार, डॉ. एवं रामानुज शर्मा सहित कई अन्य लोग शामिल थे। मालूम हो कि मासूम का अस्पताल में सघन इलाज जारी है।

बेगूसराय से एस आर आज़मी की रिपोर्ट

अमिता भूषण ने पीड़ित बच्ची और परिवार से मिलकर सांत्वना प्रकट की

पिछले दिनों बलिया अनुमंडल के कसबा गांव में नाबालिग बच्ची से हुए दुष्कर्म की घटना के सन्दर्भ में सदर बेगूसराय की पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण ने पीड़ित बच्ची और उसके परिजनों से मिलकर घटना के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। और इसे नैतिक समाज को कलंकित करने वाला बताया।

उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार व उनके नुमाइंदो की चुप्पी यही साबित करती है कि सरकार सिर्फ दिखावे को चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं ली, तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने को वाध्य होगी। इस मौके पर बलिया पूर्व प्रखंड अध्यक्ष हारून रशीद, बलिया नगर अध्यक्ष तारिक उर्फ पप्पु, छोटे, ताहिर, अख्तर हुसैन, कुमार रत्नेश टुल्लू आदि ग्रामीण मौजूद थे।

अलका लाम्बा ने संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया

दूसरी तरफ महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदर की पूर्व विधायक श्रीमती अमिता भूषण के निर्देशन में बीरपुर प्रखंड के बीरपुर पूर्वी पंचायत के पकड़ी गांव में नारी न्याय संवाद का आयोजन किया गया। महिलाओं की समृद्धि, सम्मान, अधिकार और न्याय की थीम पर आधारित इस संवाद कार्यक्रम में अलका लाम्बा ने उपस्थित जनप्रतिनिधि से दोतरफा संवाद किया।

इस दौरान महिला जिलाध्यक्ष गायत्री देवी, पूर्व अध्यक्ष अर्जुन सिंह, पंचायत समिति सदस्य वीणा देवी, रीता देवी, रीमा कुमारी, सुनीता देवी, वार्ड सदस्य हालिमा खातून, काला देवी, सुखिया देवी, प्रेमलता देवी, जितेन्द्र कुमार, मो. रियाज, रूपक कुमार, मुकेश कुमार, राकेश कुमार, राजा

जन्म : जमशेदपुर, झारखण्ड
शिक्षा-स्नातकोत्तर (हिन्दी, डी.एल.एड.)
कृतियां -- इतने अंधेरे में (काव्य संग्रह)
लेखन - विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में कविताएं- सांस्कृतिक रपट एवं साक्षात्कार प्रकाशित,
सम्मान - राघव आलोक सम्मान, जमशेदपुर
सम्प्रत्ति - अध्यापन (श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल, बिष्टुपुर जमशेदपुर)
संपर्क-रोड नंबर-15, क्वार्टर नंबर- 55/1/8, आदित्यपुर-2, जमशेदपुर, झारखण्ड-831013
मोबाइल - 9135362244
Email:chandrakantskps@gmail.com

चंद्रकांत की कविताएं

1. चिड़िया

शक भरी निगाहों से
देख रही बूढ़ी चिड़िया
अपनी ही संतानों को
टकटकी लगाए

यकीन नहीं
करेंगी बुढ़ापे में रखवाली भी
अचानक
घुसता है एक नर चिड़िया
रचाता है ब्याह
उसकी लाड़ली बिटिया से
बनता है घरजमाई
अधिकार जमाता
बूढ़े-बूढ़ी पर

खामोश है
मुंह खोला
तो उड़ जाएगी लाड़ली
अपने प्रेमी के साथ
पंख फड़फड़ाकर

शोर हवाओं को चीरेंगे
बतकही करेंगे
आसपास के घोंसल
दोषी ठहराएँगे
संभाल नहीं पाये उन्हें

मां विवश है
क्या करे
बच्चों के पंख खुजलाने लगे
घोंसले नहीं
उनकी जद में आकाश है
फिर क्यों बंधेंगे वे
घोंसले में ?

आकाश नापने में
शायद उन्हें मिल जाए
कोई नया स्वर्णिम घोंसला
बूढ़े मां-बाप तो केवल
सपना ही देख सकते हैं
उनके लिए
खोकर अपना सब कुछ ...

2- मेरे दोस्त

क्यों आए
मेरी बस्ती में
तुम, बुर्जुआ
क्या तुम्हें पता नहीं
तुम्हारे आने से
मेरी बस्ती की जीवनधारा रुक सकती है
हरियाली की प्रकृति
बदल सकती है
तुम्हारे जैसे तथाकथित स्वनामधन्य
विचारक
जब यहां आते हैं
मैं डर जाता हूं
जानते हो क्यों?
मैंने महसूस किया है
तुम्हारे आने से
श्रम के गीतों का गूंजना बंद हो जाता है
एक अनागत संकट की
छाया घेर लेती है सम्पूर्ण परिवेश को
जीवन की बहुलता, पृथक्ता
सूख जाती है
पुष्पित-पल्लवित होने के पहले ही
क्यों आते हो तुम
तुम्हारा रूप, तुम्हारा सौन्दर्य
तो बाजार के लिए है
जहां
जीवन उत्पाद होता है
बेचने, खरीदने के लिए
स्पंदनहीन
यह बस्ती जीवित है अभी
इसके सौंदर्य में
संवेदना के रिश्ते हैं
अंचल की करुणा में गीतों के बोल
और संघर्ष की कटीली राहों
पर थिरकते, नृत्य करते
उत्साहित पग
तुम्हारी दुनिया दूसरी है दोस्त
यहां न तो बाजार है
न विज्ञापन

यहां तो रिश्तों का है
अपनापन

3. समवेत स्वर

कविता खत्म नहीं होती
जहां उसके खत्म होने का
होता है आभास
मुकम्मल शुरू होती है
वहीं से
एक कविता
आलोचक ,समीक्षक ,पाठक
ढूंढते हैं
उस रोशनी का स्रोत
जो उस कविता से
निकलती है
चीरती है
अंधेरे को
लाती है
नई किरण
नई उम्मीदें

हां ,
यह सच है
कि उस रोशनी को
लाने में
स्वयं मरा है कवि
कई बार

कविता
बन गई है
आवाज
हाशिए पर रहनेवालों की
नहीं रही बयानबाजी
वह तो ढूंढ रही है
समवेत स्वर
शोषित - पीड़ितों
दबे-कुचलों की।

4 .आंसू के सैलाब

आती है चिट्ठियां
खोलकर पढ़ता हूं
शहीदों के संदेश
चोटों के निशान
जिनके घर जल गए हैं
किसी दंगे में

कहां रखूं
इन चिट्ठियों को मैं
इतिहास पढ़ने के बाद भी
आज तक नहीं पढ़ पाया
दंगों की आत्मकथा
क्या उन्हें दर्द का एहसास है ?
जो करते हैं दंगे
कितना खामोश रहूं मैं

जानता हूं मैं
दंगा किनकी जरूरत है
इंसान दंगे नहीं फैलाते
वे तो शैतान ही होते हैं
जो घर बसा नहीं सकते
जला सकते

कितनी व्यथा है
इन चिट्ठियों में
आंसू के सैलाब
खून की नदियां
फिर भी सूखी हैं
चिट्ठियां
चुप तो हैं
पर संवाद तो कर रही हैं।

अगर बांट दो तुम एक मुट्ठी वसंत

डॉ सुधा गुप्ता अमृता

अपनी विराटता से
अगर बांट दो तुम
एक मुट्ठी वसंत
रंग लेगी पत्नी
आंचल का छोर
मुस्काएगी आंखों की कोर
बनेगी घर में तरकारी
बिसूरेगा नहीं बचपन
गूंजेगी किलकारी
हो जाएगा सघन
पृथ्वी का मन
झरने लगेगा
उसके वक्षस्थल से झरना
फेंक देगी
वह रात की काली चादर
गाने लगेगी विभास
पलने लगेगी
उसकी कोख में धूप
ढोंगी नहीं होंगे संत
अगर बांट दो तुम
एक मुट्ठी वसंत-
सधने लगेगा कबीर का सूत
देगी समय को चुनौती
फिर रैदास की कठौती
फिर चढ़ेगा तुलसी का पानी
गूंजेगी मीरा की वाणी
काव्य नहीं होगा
चुटकुलों के मानिंद
सधेगी स्वस्थ कविता
बनेगा विराट महाकाव्य
सधेंगे कुम्हारों के हाथ
रचेंगे नया संसार
सजेंगी दिशाएं /वनिताएं
रचेगा नया भूगोल
झरेगा पतझर का रूखापन
निखरेगी वसुधा
ज्यों लगाकर उबटन
फूटेंगी जीवितों की चुप्पियां
धनिकों के होंगे
बाघ मुख बंद
ज्वाला से निकलेंगे
बहू बेटी के अनुबंध
होगा सम्मोहित सा इतिहास
अनारदाना सा फूटेगा हास
भूलेगी छटपटाहट
नाचेगी आजादी
होगा संघर्षों का अंत
अगर बांट दो तुम
एक-एक मुट्ठी वसंत-
एक-एक मुट्ठी वसंत -

'क़सबे का आदमी'

कमलेश्वर

सुबह पाँच बजे गाड़ी मिली। उसने एक कंपार्टमेंट में अपना बिस्तर लगा दिया। समय पर गाड़ी ने झाँसी छोड़ा और छह बजते-बजते डिब्बे में सुबह की रोशनी और ठंडक भरने लगी। हवा ने उसे कुछ गुदगुदाया। बाहर के दृश्य साफ हो रहे थे, जैसे कोई चित्रित कलाकृति पर से धीरे-धीरे ड्रेसिंग पेपर हटाता जा रहा हो। उसे यह सब बहुत भला-सा लगा। उसने अपनी चादर टाँगों पर डाल ली। पैर सिकोड़कर बैठा ही था कि आवाज़ सुनाई दी, 'पढ़ो पटे सित्तारम सित्तारम'....

उसने मुड़कर देखा, तो प्रवचनकर्ता की पीठ दिखाई दी। कोई ख़ास जाड़ा तो नहीं था, पर तोते के मालिक, रूई का कोट, जिस पर बर्फ़ीनुमा सिलाई पड़ी थी और एक पतली मोहरी का पाजामा पहने नज़र आए। सिर पर टोपा भी था और सीट के सहारे एक मोटा-सा सोंटा भी टिका था। पर न तो उनकी शक्ल ही दिखाई दे रही थी और न तोता। फिर वही आवाज़ गूँज उठी, 'पढ़ो पटे सित्तारम सित्तारम'...

सभी लोगों की आँखें उधर ही ताकने लग गईं। आख़िर उससे न रहा गया। वह उठकर उन्हें देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ा। वहाँ तोता भी था और उसका पिंजरा भी, और उसके हाथ में आटे की लोई भी, जिससे वे फुरती से गोलियाँ बनाते जा रहे थे और पक्षी को पुचकार-पुचकारकर खिलाते जा रहे थे। पर तोता पूरा तोता-चश्म ही था। उनकी बार-बार की मिन्नत के बावजूद उसका कंठ नहीं फूटा। गोलियाँ तो वह निगलता जा रहा था, पर ईश्वर का नाम उसकी ज़बान से नहीं फूट रहा था। लौटते में एक नज़र उसने उन पर और डाली, तो लगा, जैसे चेहरा पहचाना हुआ है। अपनी सीट पर आकर बैठ गया। दिमाग़ पर बहुत ज़ोर डाला पर याद नहीं आया। तभी उन्होंने तोते की ओर से दृष्टि हटाकर शिवराज की ओर देखा, अंगूठा और तर्जनी निरंतर एक रफ्तार से अब भी गोली को शक्ल प्रदान कर रहे थे। माथे पर लहरें डालते हुए और आँखों को गोल कर कुछ अजीब निरीह-सा मुँह बनाकर वे शिवराज को संबोधित करते हुए बोले, 'शिब्बू शिवराज है न तू?'

और अपना नाम उनके मुँह से सुनते ही उसे सब याद आ गया। ये तो छोटे महराज हैं।

वे जाति के वैश्य थे, पर कमज़ के कारण महराज पुकारे जाने लगे थे। म्युनिसिपालिटी की दूकानों के पासवाली इमली के नीचे बैठकर वे पानी पिलाया करते थे। क़स्बे की सबसे रौनकदार जगह वही थी। वहीं कुएँ पर छोटे अपनी टाँगें तोड़े, जाँघ तक धोती सरकाए, जनेऊ डाले, चुटिया फहराए, नंगे बदन टीन की टूटी कुरसी पर जमे रहते। गाँववाले पानी पीकर एक-आध पैसा उनके पैरों के बीच उसी कुरसी पर रखकर चल देते। पैसा पाकर वह सामर्थ्य - भर आशीर्वाद देते। जब एक कूल्हा दर्द करने लगता, तो दूसरी तरफ़ ज़ोर डालने के लिए थोड़ा-सा कसमसाते और इसमें अगर कहीं कुरसी ने खाल दाब ली, तो तीन-चार मिनिट लगातार कुरसी को गालियाँ देते रहते। लगे हाथों ननकू हलवाई को भी कोसते, जिसने प्याऊ के लिए यह कुरसी दी थी।

तब छोटे महराज की उमर कोई ख़ास नहीं थी, यही 35-36 के क़रीब रही होगी। छोटे महराज के बाप-दादा सोने-चांदी का काम करते थे। काफ़ी पुराना घर था, दूकान थी। पर जब बाप मरे, तो छोटे की उमर बहुत कम थी। माँ पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थीं। बाप के मरने के बाद दूर के रिश्ते की एक चाची आकर सब देखभाल करने लगीं। फिर बहुत बड़ी-सी चोरी हुई और छोटे का घर तबाह हो गया। चाची को तीरथ की सूझी, तो छोटे को साथ लेकर चल दीं। खर्चे की ज़रूरत पड़ने पर एक मुख़्तार से जब-तब रुपए मँगवाती रहीं। छोटे साथ थे, सो रसीद भेजते रहे। आख़िर जब तीरथ से वापस आए, तब पाँच-छह बरस मकान में और रहना हुआ। फिर मुख़्तार ने मूल और ब्याज के बदले एक दिन मकान कुर्क करा लिया, गवाही में छोटे के हाथ की रसीदें पेश कर दीं और औने-पौने में मकान झाड़ दिया। तब से उनकी चाची ने जनाने और अस्पताल में नौकरी कर ली और छोटे बिस्किटों का ठेला लगाने लगे और घूम-घूमकर बाज़ार की सड़कों पर चीखने लगे - 'एक पैसे में पचास, पचास बिस्किट इनाम जितना लगाओगे, उतना पाओगे -'

ठेले में मैदे के छोटे-छोटे बिस्किटों का ढेर लगा रहता। एक कोने पर एक बड़ी-सी फिरकनी रखी रहती, जिस पर नंबर के खाने बने रहते और उस पर एक सुई नाचती रहती। जब कोई पैसा लगाकर घुमानेवाला न मिलता, तो खड़े-खड़े स्वयं घुमाते रहते, जितना नंबर आता, उतने बिस्किट गिनते और फिर ढेर में डालकर अनाज की तरह रोरते रहते। कभी करारे-करारे बीस-पचीस छाँट लेते, सुई घुमाते, अंटी से एक पैसा निकालकर पैसा रखनेवाले फूल के कटोरे में झन्न से मारते और जितना नंबर आता, उतने गिनकर, बाकी ढेर के सुपुर्द कर जलपान कर लेते।

लेकिन इस तरह कैसे पेट पलता। फिर एक होम्योपैथिक डॉक्टर की दूकान को रोज़ सुबह खोलने तथा झाड़ने-पोंछने का काम ले लिया। दो-चार घरों का पानी बाँध लिया। तड़के उठकर चार-चार डोल खींचकर डाल आते और डॉक्टर की दूकान की सफ़ाई आदि करके कोने में पड़े मोढ़े पर इज्जत से दोपहर तक बैठे रहते। डॉक्टर साहब की अनुपस्थिति में मरीज़ों के हालचाल पूछ लेते। कुछ देसी दवाइयों के नुस्खे बताते और जमज़ दवाइयों की अहमियत समझाते।

तभी से छोटे अपने को बहुत-कुछ, एक छोटा-मोटा वैद्य समझने लगे थे। मरीज़ की दशा देखते ही रोग का ऐलान कर देते। तमाम रोगों के इलाज पर उन्होंने दखल जमा लिया था। जब मोतियाबिंद हो जाने के कारण डॉक्टर साहब को दूकान बंद कर देनी पड़ी, तो छोटे अपनी कोठरी में ही एक छोटा-सा औषधालय खोलने का मन्सूबा बाँधने लगे। रतनलाल अत्तार के यहाँ से आठ-दस आने की जड़ी-बूटियाँ भी बँधवा लाए, जिन्हें घोंट-पीस और कपड़छन करके सफ़ेद शीशियों में भरा और ताक में सजा दिया। फ़सली बुखार, हरे-पीले दस्त, नाक-कान-सिर-दर्द की हुक्मी दवाइयाँ बाँटने का ऐलान भी कर दिया। पर गली के परिवारों का सहयोग न मिलने के कारण उन्होंने इस नेक इरादे को छोड़ दिया। सारी हकीमी दवाइयों को थोड़ा-थोड़ा करके चूरन की पुड़ियों में मिलाकर उन्होंने आख़िर अपने पैसे सीधे कर लिए।

इस तरह के न जाने कितने घरेलू धंधे उन्होंने चलाए। जन्म से वैश्य होते हुए भी प्रकृति से परोपकारी होने के कारण उन्हें ब्राह्मणत्व भी प्राप्त करना ही था। इसीलिए जब गली-टोले के लड़कों ने उन्हें प्याऊ पर बैठते देखा और चमकदार काली पीठ पर जनेऊ दिखाई पड़ा, वे वंशगत भावनाओं से अनजान, कर्मगत संस्कारों के आधार पर उन्हें महराज पुकारने लगे। तभी से छोटेलाल छोटे महराज हो गए।

जिस इमली के नीचे वह बैठते थे, उस पर दैव की कृपा से महूक ने छत्ता धर लिया, तो एक दिन अंधियारे पाख में जाकर स्टेशन के पास से एक कंजर पकड़ लाए। छत्ता बटाई पर तै हो गया। पर छोटे महराज शहद का क्या करते। चलते वक्त उसे कस दिया कि आधे दाम कल आ जाएँ। पर महीना-भर टल गया। झोंपड़ी पर तगादा करने पहुँचे। नगद पैसे तो मिले नहीं, अच्छी-ख़ासी डाँट लगाकर पैसों के बदले में तोता छाँट लिया। कंजर ने मिन्नत की कि तीनों तोते पेशगी दामों के हैं, इस बार जाएगा तो उनके लिए भी पकड़ लाएगा। पर छोटे न माने, दो-चार गालियाँ सुना दीं, तैश में बोले, 'मेरे पैसे क्या हराम के थे, वह भी तो पेशगी में से ही हैं, ला निकाल जल्दी इस टुइयाँ को।'

और तभी से यह तोता उनके पास है, जिसे जान की तरह चिपकाए रहते हैं।

शिवराज ने प्रसन्नता से उन्हें देखा। 'पालांगे महाराज' कहकर बोला, 'इधर निकल आएँ महाराज, बहुत जगह है।'

जब वह पास आकर बैठ गए तो उसने पूछा, 'झाँसी किस्के यहाँ गए थे?'

'यहीं एक ब्याह था, उसमें आए थे, आना पड़ा अपनी कहो लेकिन देख, पहचान कैसा। नज़र कमज़ोर है लला, पर अपने गली-कूचे के पले लोगों की तो महक बहुत अच्छी होती है'... और वे धीरे-धीरे गरदन हिलाने लगे। उँगलियों के बीच गोली अब भी नाच रही थी और पिंजरे में बैठा संतू गोली के लालच से मुँह खोलता, आँखें बंद करता, पर बोलता नहीं था।

'बदन तो तुम्हारा एकदम लटक गया है, पहले से चोथाई भी नहीं रहा' शिवराज बोला। उसे कुछ दुःख-सा हो रहा था, जब उसने पिछली मरतबा देखा था, तब कितने हट्टे-कट्टे थे। यों उमर का उतार तो था, पर इतना फ़र्क तो बहुत है। भला उमर बने-बनाए आदमी को इतनी जल्दी भी तोड़ सकती है!

गाड़ी की चाल धीमी पड़ गई। छोटे महराज ने संतू के पिंजरे को तनिक ऊपर उठाया। उसकी ओर प्यार-भरी दृष्टि से निहारते रहे। तोता कुछ बोला। छोटे महराज के मुख पर मुसकान दौड़ गई। बड़े स्नेह से पुचकारते हुए शिवराज को बताने लगे, 'इसका नाम संतू है! यानी संत जब बोले तो बानी बोले, हाँ, संत बानी सित्ताराम!' इतना कहते-कहते वे अपनी ही बात में डूब गए।

गाड़ी रुकी, कोई मामूली-सा स्टेशन था। छोटे महराज ने पेट पर हाथ फेरा और सिर हिलाते हुए बोले, 'देखो शिब्बू, कुछ खाने-पीने का डौल है यहाँ?' मिठाईवाला पास से गुज़रा, शिवराज ने रोक लिया। छोटे महराज बोले, 'कुछ ठीक-ठाक हो तो पाव-आध पाव'..

मिठाई लेकर पैसे शिवराज ने दे दिए। दोनों हाथों में दोना पकड़कर शिवराज के सामने करते हुए वह बोले, 'लो शिब्बू, चखो तो ज़रा, अच्छी हो तो पाव-भर और ले लो।'

और इससे पहले कि शिवराज चखे, उन्होंने खुद पोपले मुँह में एक टुकड़ा

डालते हुए अपनी राय प्रकट कर दी, 'है तो अच्छी बुलाओ उसे।' शिवराज को बात कसक गई। वह चुप ही बैठा रहा। झाँककर मिठाईवाले को बुलाने की कोई दिखावटी चेष्टा भी उसने नहीं की। पर जैसे ही मिठाईवाला फिर गुज़रा, उनकी दृष्टि पड़ गई। उसे रोकते हुए बोले, 'हाँ भाई, ज़रा पाव-भर और देना तो।' फिर शिवराज की ओर मुख़ातिब होकर बोले, 'ले लो, शिब्बू असल में बात यह है कि मुझसे अब कोई ऐसी-वैसी चीज़ तो खाई नहीं जाती, दाँत ही नहीं रहे। खोया-वोया थोड़ा आसान रहता है न।' कहकर उन्होंने निष्काम भाव से खाना शुरू कर दिया।

पैसे उसने फिर दे दिए। खाते समय छोटे महराज का निरीह-सा मुँह और एकदम सट जानेवाले जबड़े देखकर उसे रहम आ गया। उनकी झुकी गरदन, बार-बार पलकों का झपकना और ज़रा-ज़रा करके खाना, जैसे सारे कार्य और तन की सारी भाव-भंगिमाओं में लाचारी थी। उन्होंने एक टुकड़ा पिंजरे में डाल दिया। तोते ने खा लिया। पुचकारते हुए उन्होंने फिर एक टुकड़ा डाल दिया। वे स्वयं खाते रहे और संतू को खिलाते रहे। फिर बात चल निकली और उसी के मध्य उनका स्टेशन भी आ गया। स्टेशन से बाहर आने पर शिवराज और छोटे महराज एक ही इक्के में बैठ गए। दो सवारियाँ और हो गईं। इक्का चला तो हचकोला लगा। छोटे महराज अपने तोते के पिंजरे को पटरे से बाहर लटकाए किसी तरह बैठे रहे। अस्पताल के पास वह इक्के से उतर पड़े। संतू का पिंजरा पटरी पर रख दिया और झोले में से कुछ निकालते हुए कहने लगे, 'मैं यहीं उतर जाता हूँ। चाची को ब्याह का हालचाल बताकर कोठरी पर आऊँगा! हाँ, तुमसे एक काम है। ये एक कपड़ा है सिलक का, वहीं शादी में मिला था। मेरे तो भला क्या काम आएगा, तुम अपने काम में ले आना!' बात खतम करते-करते वह कपड़ा झोले से निकालकर शिवराज की गोद में रख दिया।

शिवराज ने लेने से इनकार कर दिया। पर वे नहीं माने। शिवराज भी नहीं माना, तो बड़े झुंझलाकर कपड़ा इक्के में फेंककर संतू का पिंजरा, झोला और सोंटा लेकर बड़बड़ाते चल दिए, 'अरे पूछो मेरे किसी काम का हो तो एक बात भी है। ज़िंदगी-भर में एक चीज़ दी, उससे भी इनकार सब वक्त की बातें हैं, रहम दिखाते हैं मुझ पर, तेरे बाप होते तो अभी इसी बात पर चटख जाती।' फिर मुड़कर ऊँचे स्वर में बोले, 'पैसे नहीं हैं मेरे पास, इक्केवाले को दे देना।' और वे जनाने अस्पताल के फाटक में गुम हो गए।

दूसरे दिन सवेरे छोटे महराज अपनी कोठरी में दिखाई दिए। देहरी पर बैठे-बैठे कराह रहे थे। कभी-कभी बुरी तरह से खाँस उठते। साँस का दौरा पड़ गया था। गली से शिवराज निकला तो पिछले दिन वाली बात के कारण उसकी हिम्मत कुछ कहने की नहीं पड़ी। सोचा कतराकर निकल जाए, पर पैर ठिठक रहे थे। तभी हाँफ्ते-हाँफ्ते छोटे महराज बोले, 'अरे शिब्बू!' फिर कराहकर टुकड़े-टुकड़े करके कहने लगे, 'दौरा पड़ गया है, कल रात से, हाँ, अब कौन देखे संतू को। बड़ी ख़राब आदत है इसकी, गरदन सलाख से बाहर कर लेता है। रात-भर बिल्ली चक्कर काटती रही, बेटा। छन-भर को पलक नहीं लगी। अपने होश-हवास ठीक नहीं तो कौन रखवाली करे इसकी। अपने घर रख लो, बेफ़िकर हो जाऊँ।'

और इतना कहकर बुरी तरह हाँफने लगे। गले में कफ़घड़घड़ा आया, तो औंधे होकर लेट रहे। पीठ बुरी तरह उठ-बैठ रही थी। शिवराज 'अच्छा' कहकर पिंजरा उठाकर चलने लगा, तोते को एक बार पूरी आँख खोलकर उन्होंने ताका। उनकी गंदली-गंदली आँखों में एक अजीब विरह-मिश्रित तृप्ति थी। जैसे किसी बूढ़े ने अपनी लड़की विदा कर दी हो। सिर नीचा करके उन्होंने एक गहरी साँस खींची, जैसे बहुत भारी ऋण से उऋण हो गए हों।

तीन-चार दिन हो गए थे। छोटे महराज की हालत ख़राब होती जा रही थी। अकेले कोठरी में पड़े रहते। कोई पास बैठनेवाला भी नहीं था। चौथे दिन हालत कुछ ठीक नज़र आई। सरककर देहरी तक आए। घुटनों पर कोहनियाँ रखे और हथेलियों से सिर को साधे कुछ ठीक से बैठे थे। कभी कराह उठते, धाँस लगती तो खाँस उठते। पर उनके चेहरे पर अथाह शोक की छाया व्याप रही थी, जैसे किसी भारी गम़ में डूबे हों। उनकी आँखों में कुछ ऐसा भाव था, जैसे किसी ने उन्हें गहरा धोखा दिया हो, उनके कानों में बार-बार संतू की वह आवाज़ गूँज रही थी, जो उन्होंने दोपहर सुनी थी।

दोपहर संतू की कातर आवाज़ जब शिवराज के बरोठे से सुनाई दी तो वे घबरा गए थे कि कहीं बिल्ली की घात तो नहीं लग गई। बड़े परेशान रहे, पर उठना तो बस में नहीं था। शिवराज के घर की ओर बहुत देर आस लगाए रहे कि कोई निकले, तो पता चले। काफ़ी देर बाद मनुआ तोते के दो-तीन हरे-हरे पंखों का मुकुट बनाए माथे से बाँधे, दो-तीन बच्चों के साथ खेलता दिखाई पड़ा, देखते ही सनाका हो गया। संतू की पूँछ के लंबे-लंबे पंख! किसी तरह बुलाकर पूछा तो पता चला कि मुनुआ को राजा बनना था, सो उसने संतू की पूँछ पकड़ ली। बात की बात में दो-तीन पंख नुच आए।

छोटे महराज का जैसे सारा विश्वास उठ गया। ये लड़का तो उसे मार डालेगा! इस वक्त तबीयत कुछ ठीक मालूम हुई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना डंडा पकड़ा, हिलते-काँपते शिवराज के बरोठे में पहुँचे और अपना तोता वापस माँग लाए। कोठरी में आकर उसकी बूची पूँछ देखते रहे, पर मुँह से कुछ बोले नहीं। संतू को पुचकारा तक नहीं।

शाम हो आई थी। तिराहे पर लालटेन जल गई थी। पूरी गली में उदास अंधियारा भरता जा रहा था। उन्होंने संतू के पिंजरे को भीतर रखकर कोठरी के दरवाज़े उढ़का लिए और फिर नहीं निकले। भीतर कुछ देर तक खुट-पुट करते रहे, फिर रात भर कोई आवाज़ नहीं आई।

सवेरे शिवराज उधर से निकला तो कोठरी की ओर निगाह डाली।

दरवाज़े उसी तरह भिड़े थे। उसने धीरे से खोलकर झाँका, देखा महराज सो रहे थे। चुपचाप धीरे से दरवाज़ा बंद करने लगा, तो गली के रामनरायन बोल पड़े, 'क्यों, आज नहीं उठे महराज अभी तक?'

और इतना कहते-कहते उन्होंने पूरे दरवाज़े खोल दिए। दोनों ने ग़ौर से देखा, तोते का पिंजरा सिरहाने रखा था, जिस पर कपड़ा था कि कहीं बिल्ली की घात न लग जाए, परंतु छोटे महराज का पिंजरा खाली पड़ा था, पंछी उड़ गया था।

छोटे महराज ने स्वयं तो नहीं पढ़ा था, पर रामलीला आदि में सुनने के कारण यह उनका पक्का विश्वास था कि अंतिम काल में यदि राम का नाम कानों में पड़ जाए तो मुक्ति मिल जाती है। पता नहीं, उनके अंतिम क्षणों में भी संतू तोते की वाणी फूटी थी या नहीं।

डॉ. हरिबल्लभ सिंह 'आरसी' की कविताएं

राष्ट्रीय मयार्दा कलंकित

राज्य से संसद तक मर्यादा कलंकित
यह योजनाबद्ध कार्य किये जा रहे
'विपक्ष' शब्द का नाम विद्रोही हुआ अब
विद्रोह इनका जन्मसिद्ध अधिकार बना।

राष्ट्रीय आचरण को भुला दिया गया
आंदोलनकारी नेताओं की मर्यादा दाँव पर
आज तो जो जितना उदंड है वही
सर्वश्रेष्ठ विपक्षी नेता कहा जाता है।

नेता विदेश में अपने देश के विरूद्ध
संगठन बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता भंग हेतु
सुझाव नहीं दे सकते, उलझा सकते हैं
विदेशी एजेंटों के हाथ बिके हुए हैं।

चुनाव में विदेशी फंडिंग की चर्चा
चंद न्यूज दाता भी इसमें सम्मिलत हैं
विकास की योजना पर बहस नहीं होती
विनाश कैसे हो, विद्रोही मंच बोलती रहती।

आतंकवाद

भय और आतंक के नेता
पोशाक से नहीं पहचाने जाते
आतंक हृदय की भावनाएँ हैं
देख कर कार्यशैली से पहचानो।

मानवता का जो विनाश चाहता
लूट, हत्या व अत्याचार जो चाहता
सत्ता पाने की भूख से चिल्लाता
विकास को जो रोकता, विनाश करता।
वहीं जमात दुनियाँ को जंग की आग में
शान्ति को नष्ट कर सत्ता चाहता है
आप चंद को पहचानते भी हैं
कार्य और वचन में अंतर होता है।

विकास के पथ पर युद्ध की आग
प्रेम की जगह घृणा फैलाते जो
उसे पहचानो भारत पर भी खतरा है
वंशवाद विचार भी आतंकवाद ही है।

देर से न्याय

इंदिराजी की हत्या के बाद
बेकसुर सिक्ख भाईयों की सामूहिक
हत्या व लूट की घटना के एक दोषी को
कई दशकों के बाद सजा की घोषणा।

न्याय शब्द भी लज्जित हुआ है
देर से न्याय, वेदना मरने पर होती
यह विचारणीय प्रश्न खड़ा करता
क्या न्याय में विलंब प्रभाव नही होता।

न्यायविदों को मानवीय वेदना की पहचान
नहीं सांसद भी चुप्पी साधे
तत्काल न्याय हेतु कदम उठाने की जरूरत
जन भावनाओं के विचार से हो रहे।
हर अपराध हेतु न्याय की सीमा बाँधों
न्याय की प्रतीक्षा में जन भावनाएँ मरती
लोकतंत्र लज्जित हो रहा आज क्यों ?
आजादी के बाद भी हम जंजीर से बँधे हैं।

जनता बोलती

भ्रष्टाचार रूपी मगरमच्छ सर्वव्यापी
कोई कम कोई ज्यादा भ्रष्टाचार के शिकार
पार्टी या व्यक्तिवादी नहीं, सर्वव्यापी बना
चुनाव के खर्च ने सबको भ्रष्ट कर दिया।

जनता को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं
रुपए पर जाति, धर्म पर जब मत बिकते हैं
मात्र नेता ही नहीं, जनता भी उतनी ही भ्रष्ट
हाँ भ्रष्टाचार का जनक नेता लोग ही हैं।

अपराधियों या उन्हें पालने वाले लोग ही
व्यापार सा भ्रष्टाचार को खानदानी पेशा बनाया
आम ईमानदार, विद्वान लोग नहीं जाते हैं अब
सदनों की मयार्दा कौन तोड़ते हैं प्रतिदिन वहाँ।

दिन प्रतिदिन ऐसी गिरावट होती जाएगी
चंद वर्षों के बाद देश का क्या होगा बताओ
न्याय भी बीमार होते जा रहा प्रतिदिन विश्वास
जनता का उठते जा रहा क्यों बताओ।

झारखंड है क्या?

सौ से अधिक विद्यालयों में
एक भी छात्र ही नहीं है
शिक्षक छात्र के जगहों पर
वेतन विभाग समय पर देता।

शिक्षा विभाग की हालत ही
अन्य विभागों की दुर्दशा का
परिचय आप स्वयं देख सकते
बोला कौन जहाँ कर्मचारी है पर काम नहीं।

टेबुलों पर फाइलें पड़ी रहती
प्रतीक्षा संबंधित लोगों, की होती
वर्षों एक ही फाइल घूमती रहती
पुनः उसी फाइलों पर विचार होता।

बजट प्रचलित शब्द

हर साल सभी सरकारें प्रसारित करती
शब्द पर इतना बोझ पड़ता है कि वह
आधी रकम फाइलों में ही मर जाती
जनहित में कम, लूट होती रास्ते में।

बजट केन्द्र का हो या राज्य का
कानूनन अनुमानित खर्च का आँकड़ा होता
विभाग विकास हेतु खर्च करता रहता
कभी रकम घटती तो कभी शेष रहती।

जनहित में कम, व्यक्तिगत में अधिक खर्च
नेता चिल्लाते मेरे विभाग में कम रकम
कोई नहीं कहता कि हमारे विभाग में अधिक आबंटित
जितना अधिक रकम, फाइलें उतना ही कमाती।

सभी का हाल एक सा ही समूचे देश में
पक्ष और विपक्ष-एक रस्म अदा किया जाता
आय विभागीय अधिकारियों की बढ़ जाती
दशकों से यही रस्म अदा होती रहती।

जमशेदपुर, झारखण्ड-831013

विगत 23 वर्षों से देशहित में समाज-निर्माण के संकल्प के साथ

न हम डरते है न डराते हैं
हम देशप्रेम की भावना जगाते हैं

अगर आप में है जोश और
देश से प्यार

तो आइए दिल्ली से प्रकाशित
राष्ट्रीय पाक्षिक पत्रिका
दूसरा मत
के साथ

अगर शिक्षक, प्रोफेसर, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हो तो हमेशा एक ही काम करोगे लेकिन पत्रकार बनते हो तो दुनिया समझने को मिलेगी, दुनिया समझाने को मिलेगी। दुनिया को पढ़ने का मौक़ा मिलेगा, दुनिया को पढ़ाने का मौक़ा मिलेगा

हम आपके हाथ में देते हैं क़लम
समाज-निर्माण की ताक़त के साथ।

योग्यता
ख़बरों की समझ
और देश के साथ
सच्ची प्रेम-भावना

सोचो, समझो और दूसरा मत से जुड़ो

संपर्क : +91-9643709089

45
YEARS OF EXCELLENCE
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
!! RADHA SOAMI JI !!
KJ
Kasturi Jewellers
SINCE 1976
100% HALLMARK JEWELLERY SHOWROOM
#GOLD #DIAMOND JEWELLERY #SOLITAIRES
100% Lifetime Maintenance Free
100% Buy Back Diamond Jewellery
100% Certified Diamond Jewellery
Shop No. 15, 16, 17, 18, SDM Market, Mangal Bazar Road, Uttam Nagar, New Delhi-110 059
Shop No. 54-55, Main Pankha Road, Opp. Sagar Pur Police Station, New Delhi-110 046
Kasturi Lal Ph. 98186 09444 | Manish (Monu) Ph. 98186 11313

‘दूसरा मत’ प्रकाशन

‘आमने-सामने’ अपने-आप में एक ऐतिहासिक इंटरव्यू-संग्रह है। इस संग्रह में देश की 62 अहम शख़्सियतों एवं हस्तियों के साक्षात्कार शामिल हैं। यह संग्रह देश ही नहीं विदेशों में भी ख़ासा चर्चित रहा है।

देश के जाने-माने प्रकाशन ‘राजपाल’ के प्रकाशक एवं डीएवी मैनेजमेंट कमिटी के वायस प्रेसिडेंट विश्वनाथ जी ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है,- “इस तरह के विशाल इंटरव्यू-संग्रह देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अभी तक नहीं आए हैं।

आमने-सामने (मूल्य 750/)

सामना (मूल्य 1100/)

‘सामना’ भी एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू-संग्रह के तौर पर ‘आमने-सामने’ की तरह सामने आया है। इसे भी शख़्सियतों एवं साक्षात्कार की कला को क़ुबुल करने वाले लोगों ने हाथों-हाथ लिया है। इस संग्रह में देश की विभिन्न क्षेत्रों की 82 हस्तियों की इंटरव्यू की शक्ल में लेखा-जोखा एवं उनकी हस्ती की पड़ताल है।

अपने-अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाले और देश व दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने वाले लोगों के एक समूह विशेष इस अंक में शामिल हैं।